



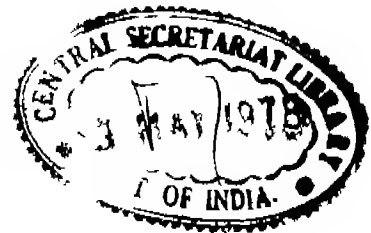
भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण,
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 72]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15, 1978/चैत्र 25, 1900

No. 72]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 1978/CHAITRA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

व्याणिज्य, नागरिक सम्भरण और सहकारिता मंत्रालय

(व्याणिज्य विभाग)

(आयात व्यापार नियंत्रण)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1978

सार्वजनिक सूचना

सं० 25-आई०टी०सी० (पी०एन०)/78/मिसिल सं० आई०पी०सी०/39/13/76—1977-78 के लिए ऋच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तियुक्त किए गए आयात लाइसेंसों को जारी करने के संबंध में लागू होने वाले नियम तथा शर्तों को इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 तथा 2 में दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट I

ऋच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत निजी क्षेत्र अयातों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए शर्तें

खण्ड 1— सामान्य

नीदरलैंड्स इन्वेस्टीरिंग्स बैंक धीरे धीरे आटविकलिंग्स लेन्डन एन० बी० द्वारा प्रदान किए गए 1977-78 के लिए ऋच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट को विकासशील देशों के लिए खोल दिया गया है। तदनुसार इस क्रेडिट के अधीन वित्तियुक्त किए जाने वाले माल एवं पण्य वस्तुएं एवं इससे संबंध

आनुषंगिक सेवाएं नीदरलैंड्स से आयात की जा सकती हैं और परिशिष्ट 'क' के रूप में "नीदरलैंड्स द्वारा द्विपक्षी विकास ऋण के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन" सूची में सम्मिलित सभी देश (अनुबन्ध-1) इस क्रेडिट के अन्तर्गत "पात्र स्रोत देश" होंगे। दोनों साख करारों अर्थात् बी एफ एल 1 20 मिलियन और बी एफ एल 54 मिलियन में प्रतिपूर्ति की अंतिम तिथि 31-12-1980 होगी।

2 किन्तु पात्र से इतर स्रोत देशों से रसायन के संबंध में 10% की सीमा तक और अन्य आयातों के संबंध में 20% की सीमा तक के सवटकों को इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है। यदि कोई हो तो इस संबंध में विशिष्ट आवेदन सविदा पूर्ण होने से पूर्व ही वित्त मंत्रालय (प्राधिकार्य विभाग) का किए जाने चाहिए।

3 इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए पात्र स्रोत देशों से उपर्युक्त खंड 1 (2) में सकेतित सीमा से अधिक सम्भरण को सम्पूर्ण बनाने के लिए पात्र से भिन्न स्रोत देशों से माल और सेवाओं के सीमित सम्भरणों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके लिए नीदरलैंड्स की सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

खण्ड 2—आयात लाइसेंस जारी करना

2(1) आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए लागत बीमा भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा। वैध अवधि में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे वैध अवधि के भीतर ही

संबंध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करे जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग से परामर्श लेगा।

2(2) पक्के आदेश नीदरलैंड में समुद्रपार सभरकों को या अनुबन्ध-1 में उल्लिखित देशों को लागत कि बीमा भाड़ा/लागत तथा भाड़ा के आधार पर भव्य दिए जाने चाहिए और आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 4 मास के भीतर ही आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। यदि पक्के आदेश देने का निर्णय निर्धारित चार मास की अवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो लाइसेंस-धारी को चाहिए कि वह जैसा भी मामला हो मुख्य नियंत्रक आयात नियति को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए कि क्यों नहीं प्रारम्भिक वैध अवधि के भीतर ही आदेश देने का काम पूरा हो सका इसके औचित्य एवं आख्या के साथ आदेश देने की अवधि में वृद्धि की मांग करने के लिए प्रस्ताव रखे। आदेश देने की ऐसी अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन पर विचार प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और चार मास की अवधि वृद्धि वे सकते हैं। लेकिन यदि आयात जारी होने की तारीख से 8 मास से अधिक की वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अर्थ कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) वित्त मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए।

2(3) लाइसेंस पर 'छप सामान्य प्रयोजन क्रेडिट' अंकित होगा और यह उस सार्वजनिक सूचना की सं० का संकेत करेगा जिसके अन्तर्गत यह लाइसेंस शर्तें जारी की जाती हैं। प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एम"/"एन एन" होंगे। इस लाइसेंस कोड का उल्लेख सभी पोतलवान प्रलेखों में होना चाहिए और साथ ही साथ रुपया जमा करते समय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र "एस" में भी इसका उल्लेख होना चाहिए।

2(4) जैसे ही आयातक आयात लाइसेंस प्राप्त करता है उसे चाहिए कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को एक रिपोर्ट भेजे:—

- (1) आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक
- (2) मूल्य
- (3) यदि कोई हो तो आयात लाइसेंस में संकेतित मुद्रा विनिमय दर
- (4) वह तारीख जिस तक आर्थिक कार्य विभाग को संविदा की प्रतियां भेजने की सम्भावना है।

खण्ड 3—क्रेडिट को पूर्ण करना

3(1) इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए पात्र संविदा का न्यूनतम मूल्य डी एफ एल-25,000/- होगा।

3(2) आयात लाइसेंस के मद्दे केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने के लिए अनुमति दी जाएगी जिसके लिए आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख के तुरन्त बाद ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

3(3) माल के आयात के लिए संविदा और नीदरलैंड से सेवाओं और पात्र स्रोत देशों का निश्चय अनुबन्ध-1 में यथा उल्लिखित माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

3(4) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर माल और सेवाएं औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी:—

- (क) जहां नीदरलैंड आयाती के लिए परम्परागत या केवल एक मात्र स्रोत है, या
- (ख) जहां आयातों का मूल्य डी एफ एल 1.25 मिलियन से कम का है, या
- (ग) जहां ऐसी क्रियाविधि लागू नहीं है या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैंड सरकार और भारत सरकार के बीच करार किसी और अधिक उचित क्रियाविधि के आधार पर सम्भरण के लिए संविदा पूर्ण हो जाने से पूर्व ही निश्चित रूप से तय हो जाना चाहिए।

3(5) निम्नलिखित मामलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं होगा:—

- (क) जहां क्रेता के पास अपने उपकरण के पर्याप्त मानकीकरण की बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त कारण है।
- (ख) उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण सीमा संभरकों की संख्या सीमित है और क्रेता की मार्केट जानकारी ऐसी है कि उससे यह आशा की जा सकती है कि वह योग्य संभरकों को जानता है।
- (ग) जहां भारतीय आयातकों और विदेशी संभरकों के बीच चल रहे वर्तमान संबंध और नीदरलैंड और/या विकसनीय देशों में उपलब्ध और समरूप संभरकों के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कर्जदार यह समझता है कि आयात केवल नीदरलैंड से ही प्रभावी होने चाहिए। ऐसे मामलों में माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन (अनुबन्ध 1) की कंडिका 31 से 39 में निहित अधिप्राप्ति का नियम अपनाया जाना चाहिए।

3(6) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में क्रेता किसी भी एकमात्र संभरक से सीधे ही माल खरीद सकता है:—

- (1) वाणिज्यिक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में पंजीकृत ब्रांड नाम की वह पण्यवस्तु शामिल होती है जो आयातक द्वारा पुनः बेचने के लिए है और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमतः प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक है या विनिर्माणकर्ता है।
- (2) वाणिज्यिक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में वह पण्यवस्तु शामिल होती है जो विनिर्माण संसाधन या अंतिम उत्पाद के सज्जीकरण और पुनः बिक्री के लिए प्राप्त की जाती है और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमतः प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक विनिर्माणकर्ता है।
- (3) विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पुर्जों की अदमा बबली का सुनिश्चय करने हेतु अधिप्राप्ति केवल एक स्रोत से की जा सकती है।
- (4) आयातक एक ऐसा विनिर्माणकर्ता है जिसके उपकरण और कच्चे माल का फार्मुला ऐसे कच्चे माल की विशेष किस्म के साथ अधिक से अधिक उपयोग के लिए बनाए गए है जो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- (5) आयातक औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत मूल रूप से की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना चाहता है या फिरसे उसे प्राप्त करना चाहता है बशर्ते कि मूल अधिप्राप्ति की तुलना में अनुपूर्वक अधिप्राप्ति कम है और कुछ अवसर पर ही की जाती है और जब मूल अधिप्राप्ति के संबंध में निर्माण कार्य अभी चल रहा है या मूल अधिप्राप्ति के तुरन्त बाद ही की जाती है।

(6) सीदे का मूल्य डी एक एल 1 25 मिलिलियन से कम है।

3(7) परामर्शदाता फर्मों के चुनाव के लिए औपचारिक प्रतियोगी बोली क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय फर्मों द्वारा परामर्शदाता फर्मों को सुझावों के लिए निमन्त्रण भेजने से पूर्व ही ऐसी भावी फर्मों की एक सूची वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए, इसके बाद सूची नीदरलैंड की सरकार को भेजी जाएगी जो इसे स्वीकृति दे सकती है या परामर्शदाता की पसन्द को रद्द कर सकती है और नीदरलैंड में परामर्शदाता क्षेत्र की जानकारी के आधार पर इस सूची को बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकती है।

3(8) जहां औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बाजी के आधार पर माल की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव किए जाते हैं तो आयातक को चाहिए कि वह जैसे ही निविदा नोटिस भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय नियति बुलेटिन में विज्ञापन के लिए भेजे जाएं उसी समय इसकी मीन प्रतियों का वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) नई दिल्ली का भ्रमण कराते हुए भारत में नीदरलैंड के राजदूतावास को भेज दे।

3(9) खण्ड 2(2) में उल्लिखित "पुष्टि आदेश" शर्त का अर्थ है भारतीय लाइसेंसहारी द्वारा विदेशी सभरक को दिया गया वह आदेश जो बाद वाले के पुष्टिकरण आदेश द्वारा विधिवत् समर्थित हो या यह सविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी सभरक दोनों द्वारा विधिवत् समर्थित हो या क्रय सविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी सभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो। विदेशी सभरको के भारतीय अधिकृतियों के पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

3(10) यदि सविदा डच सभरक के साथ की गई तो सविदा के लागत-बोमा-भाड़ा/लागत एवं भाड़ा मूल्य को, डच गिलडर में व्यक्त करना चाहिए और यदि सविदा पात्र स्रोत देशों के सभरको के साथ की गई हो तो उनकी मुद्रा में व्यक्त करना चाहिए।

3(11) सविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद उधार पर होनी चाहिए अर्थात् पालसदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर। विदेशी सभरको भारतीय आयातकों की किसी भी प्रकार की साथ सुविधा उपलब्ध करने की स्वीकृति नहीं देगे।

3(12) सविदा के मूल्य में सम्मिलित भारतीय अतिवर्तों के बमीशन की श्रवणश को विशेष रूप से अंकित किया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी प्रकार भी भुगतान भारतीय अतिवर्तों को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा में प्रेषण स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के भाग के रूप में होने और इसलिए लाइसेंस के लिए बसूल किए जाएंगे।

3(13) क्रय आदेश और सभरक के पुष्टिकरण आदेश कदल अग्रेजों में ही होने चाहिए।

3(14) सविदा में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए —

(1) सविदा भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है (यदि सविदा का मूल्य डच गिलडर में 50,000 या इससे कम हो) और यह भारत सरकार तथा नीदरलैंड सरकार दोनों के अनुमोदन के अधीन है (यदि सविदा का मूल्य डच गिलडर में 50,000 से अधिक हो जाता है)।

(2) यह सविदा डच सामान्य प्रयाजन क्रेडिट के लिए लाइसेंस शर्तों के अन्तर्गत ही गटे भुगतान क्रियाविधि द्वारा संचालित होगी और इस संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही यह प्रभावी होगी।

(3) "माल डच मूल्य/विनिर्माण के हैं" (नीदरलैंड में सभरको के मामले में)

या

"माल मूल्य/विनिर्माण के हैं" (पात्र स्रोत देशों के सभरको के मामले में)।

(4) नीदरलैंड्स से आयात किए जाने वाले माल के लिए सभरको का नीदरलैंड्स पुजी निवेशक बैंक को उस जिले व नीदरलैंड वाणिज्य मंडल द्वारा जिसमें सभरक स्थापित है जारी किया गया/प्रमाणित किया हुआ दृग बार में एक प्रमाण पत्र वा प्रतिया में देना पड़ेगा कि माल नीदरलैंड मूलक है। यह प्रमाणपत्र भुगतान प्राप्ति के समय अन्य पोट-पदान दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रमाण-पत्र का एक नमूना अनुबन्ध 5 में दिया गया है।

पात्र स्रोत देशों के सभरको के मामले में सभरको का "माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन (अनुबन्ध-1)" में दिए गए उद्गम नियमों के अनुसार एग० आई० आ० का माल के उद्गम का प्रमाण देना पड़ेगा।

3(15) जहां प्रयाजन निष्पादन गारंटी अपेक्षित है वहां सभरको से बैंक गारंटी/वॉरंटी के प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए।

खण्ड 4—भारत सरकार नीदरलैंड पुजी निवेशक बैंक द्वारा सविदा का अनुमोदन

1(1) (क) सविदा पूर्ण होने के तुरन्त बाद ही आयातकों को आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति के साथ/सविदा/सभरण आदेश की 5 फोटो या प्रमाणित प्रतियां वाणिज्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) का भेजनी चाहिए। पात्र स्रोत देशों के सभरको के साथ पूर्ण की गई सविदाओं के मामले में उसकी 8 प्रतियां भेजी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयातक के लिए अनुबन्ध-2 में उल्लिखित सूचना भी भेजना आवश्यक है।

(ख) डच सभरको के साथ पूर्ण की गई सविदाओं के मामले में आयातकों का स्टाम्प समार्वर द्वारा विधिवत् न्याय निर्णीत निर्धारित पत्र में अनुबन्ध 4 अन्तर्गत अनुसूचित बैंक से एक बैंक गारंटी भेजनी चाहिए। बैंक गारंटी सविदा की श्रवणश के समतुल्य रूप का दर्शाते हुए व्याज और अन्य प्रभार सहित उस श्रवणश के लिए हानी चाहिए जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है परिवर्तन की दर आयात लाइसेंस की जारी होने की तिथि को प्रवर्तित राजस्व और वैकिंग विभाग द्वारा अधिगृहित विनियम दर होगी।

4(2) जब सभरक सविदा औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बाजी या औपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बाजी पर आधारित है तब निम्नलिखित सूचनाएं भी प्रस्तुत की जानी चाहिए —

(1) उस प्रयाजन का नाम जिसमें निविदा सूचना विज्ञप्ति की गई थी।

(2) उन पार्टियों के नाम जिन्होंने निविदा पृष्ठताछ के भेदे दाम बनाए हैं।

(3) विशिष्ट प्रस्ताव का चुनने के लिए कारण और यह भी बताया जाए कि यह न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त बोलों की।

4(3) यदि सविदा दस्तावेज, प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए लाइसेंस, आयात लाइसेंस और बैंक गारंटी सही पाए जाते हैं तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग सविदा की प्रतियों को हेग में भारत के राजदूतावास के माध्यम से डच प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजेगा।

4(4) 50,000—इन्च गिल्डर या इससे कम मूल्य की सविदाओं के समर्थन में उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के अनुमोदन के बारे में भारतीय आयातक के उनकी सविदा/समर्थन आवेदन की प्रतियां उच्च प्राधिकारियों को भेजते समय बता दिया जाएगा। 50,000 इन्च गिल्डर से अधिक की सविदाओं के लिए, जैसे ही इन्च क्रेडिट के अन्तर्गत उच्च प्राधिकारियों द्वारा सविदा के वित्तदान के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है जैसे ही आयातक को यह सूचित कर दिया जाएगा कि उनकी सविदा प्रभावी हो गई है।

खण्ड 5-संभरकों का भुगतान

(क) नीदरलैंड के संभरकों का भुगतान

5(1) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूंजीनिवेशक बैंक वि. हेग को एक अधिकार पत्र (अनुबंध 5 के रूप में) हेग में भारत के राज-दूतावास के माध्यम से पोतलवान दस्तावेज के मुद्दे संभरकों के लिए भुगतान को प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा और सविदा आदि की प्रतियों के साथ उसे इन प्राधिकारियों को अग्रणीत किया जाएगा।

5(2) प्राधिकार पत्र की वैधता का सुनिश्चय संबिदा में निर्दिष्ट वितरण अनुसूची को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। किसी भी मामले में प्राधिकार पत्र, आयात लाइसेंस की वैधता के बाद वैध नहीं होगा।

5(3) बैंकिंग क्रेडिट के अन्तर्गत सामान्यतः उच्च बैंक द्वारा संभरकों को भुगतान पोतलवान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के मुद्दे ही किए जाते हैं अतः इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए गए आयातों के लिए रियायती अवधि की सुविधा लागू नहीं होगी।

5(4) संभरकों को पोतलवान/भुगतान प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के भीतर पूरा न किया जाने के मामले में, आयातक को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) के साथ प्राधिकार पत्र की समाप्ति अवधि से बहुत पहले ही प्राधिकार पत्र में उपयुक्त वृद्धि के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। यदि मांगी गई वृद्धि अवधि मूल आयात लाइसेंस की वैधता से अधिक हो तो पुनर्वैध मूल आयात लाइसेंस की फोटो प्रति और बैंक से वह पत्र जिसमें बैंक गारंटी की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है, आवेदन पत्र के साथ भेजी जानी चाहिए।

5(5) यदि प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन, प्राधिकार पत्र की वैधता तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो जाती तो प्राधिकार पत्र में अप्रयुक्त शेष धनराशि वापिस कर दी गई समझी जाएगी और प्राधिकार पत्र अपने आप खत्म हो गया समझा जाएगा।

5(6) मूल परक्राम्य पोतलवान दस्तावेज निरपवाद रूप से नीदरलैंड पूंजी निवेशक बैंक द्वारा भारत में संबंधित आयातक के बैंक को भेजे जाएंगे जिसे वह सुनिश्चित करने के बाद ही सर्वोच्च आयातक को परक्राम्य दस्तावेज रिहा करने चाहिए कि आयातक ने निम्नलिखित को जमा कर दिया है:—

(1) सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17 जनवरी, 1976 में यथा निर्धारित और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं में समय समय पर यथा अधिसूचित या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुद्रा विनिमय नियंत्रण पत्रिकाओं के माध्यम से गणना की जाने वाली प्रचलित मिश्रित दर पर उच्च गिल्डर में संभरकों को भुगतान के समतुल्य रूपः

(2) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूंजीगत निवेश बैंक एन बी, वि. हेग द्वारा संभरकों को वास्तविक भुगतान की तारीख से आयातक द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में समतुल्य रूप के वास्तविक निक्षेप की तिथि तक निश्चित जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि के लिए वेबे उपर्युक्त (1) सार्वजनिक सूचना

सं० 46 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर और 30 दिनों की अवधि से अधिक के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से व्याज।

5(7) यह सुनिश्चय करने की जिम्मेदारी संबंधित भारतीय बैंक की होगी कि आयातक को आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व ही वेध धनराशि सरकार के लेखे में ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है। लाइसेंसधारी को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि बैंकरो से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व ही वेध धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे में जमा करा दी जाती है।

5(8) आयातकों को अपेक्षित रुपया निक्षेप केवल विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से करना चाहिए और सार्व-जनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 में यथा अपेक्षित लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी उनके द्वारा पुष्टीकृत करवा लेनी चाहिए। अपेक्षित प्रपत्र 'एस' संबंधित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेज दिया जाएगा।

5(9) खंड 5(6) में उल्लिखित धनराशि को स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली के पास केन्द्रीय सरकार के लेखे में निक्षेप के लिए निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा की जानी चाहिए:—

"के-डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेज डिपोजिट नाट बियरिंग इन्वेस्ट-843-सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेट्रा एण्ड-परचेजिस एटसेट्रा अन्डर उच्च जनरल परपज क्रेडिट 1977-78"

5(10) उपर्युक्त उल्लिखित रूप निक्षेप की सूचना वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31 मई, 1974 और 103 आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 12-10-1976 में निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल खजाना बालान को भी भेजना चाहिए। प्राधिकार पत्र सं० के संबंध में सूचना विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके लिए रुपया निक्षेप किया गया है, उच्च संभरकों को भुगतान की तिथि, व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है, निरपवाद रूप से राजकोष चालान में संकेतित की जानी चाहिए।

प्रतिपूर्ति क्रियाविधि

5(11) उन आयात लाइसेंसों के मामले में जहां उनका मूल्य 1 लाख रूपये से कम है, आयातक को प्रतिपूर्ति क्रिया विधि को चुनने की छूट होगी बशर्ते कि निष्पादन प्रावि के लिए कोई भी भुगतान रोकता जाना जरूरी नहीं है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आयातकों को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनकी संबिदा में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि भुगतान की विधि प्रतिपूर्ति प्रणाली द्वारा होगी। आयातक को एक लाख पत्र भारत सरकार द्वारा उनके संबिदा के अनुमोदन प्राप्त होने पर खोलना होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातक द्वारा यथा निर्दिष्ट नीदरलैंड में संभरकों के बैंक के लिए लाख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करने हुए आयातक के बैंक को एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध 6) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) द्वारा जारी किया जाएगा, आयातक द्वारा लाख पत्र के मुद्दे भुगतान आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के आधार पर किया जाएगा। सामान्यतः संभरकों को सभी पोतलवान/भुगतान उपर्युक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 महीनों के भीतर पूरा कर दिए जाने चाहिए। संभरकों को पोतलवान/भुगतान तीस महीने की अवधि के भीतर पूरा न किए जाने के मामले में आयातक को चाहिए कि वह निरपवाद रूप से संभरकों को पोतलवान/भुगतान को पूरा करने के लिए, समय सीमा की वृद्धि के लिए, इस निर्धारित अवधि के समाप्त होने से कम से कम एक महीना पूर्व ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य

विभाग डब्ल्यू ई 3 अनुभाग से सम्पर्क स्थापित करें। यह आवेदन, मांगी गई अवधि वृद्धि को शामिल करते हुए पुनर्विधित आयात लाइसेंस की फोटो प्रति द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि ऐसा आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो उनकी सविदा में अप्रयुक्त शेष धनराशि वापिस कर दी गई समझी जाएगी। आयातक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को प्राप्त के पोतलवान के 15 दिनों के भीतर ही संभरक को किए गए भुगतान के संबंध में अपने बैंक से एक प्रमाण पत्र और डक संभरक से इस बारे में एक प्रमाण पत्र के साथ बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि "उसने..... डक गिल्डर की धनराशि जो बीजक मूल्य या माल के पोतलवान के 100% के बराबर है" उसे प्राप्त कर लिया है। यह वह भी सुनिश्चय करेगा कि संभरक द्वारा खंड 3(14) (4) में उल्लिखित माल के उद्गम के बारे में प्रमाण पत्र की दो प्रतियाँ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक के माल के पोतलवान के 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भेज दी जाती हैं। आयातकों की ओर से आर्थिक कार्य विभाग को जल्दी से प्रतिपूर्ति दस्तावेजों को भेजने से सम्बद्ध किसी भी लापरवाही पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को आयातक के नाम में सभी आयात लाइसेंस निलंबित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आयातक गलती करता रहे तो ऐसी हालत में उसके मामले को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की काली सूची में रखने के लिए सिफारिश की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आयातक को आयात नियंत्रण आदि को शासित करने वाले अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना/सजा किया जा सकता है। आयातक द्वारा प्रतिपूर्ति क्रिया-विधि का विकल्प लेने के मामले में उसे सविदा की 8 फोटो प्रतियाँ वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी सविदा के लिए अनुमोदन प्राप्त करते समय भेजनी चाहिए।

(ख) पात्र स्रोत देशों में संभरकों को भुगतान

5(12) आयातक द्वारा उसके आवेदन पत्र में यथा संकेतित संभरक के नाम में पात्र स्रोत देश में संभरक के बैंक के लिए साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध-6 के रूप में) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) द्वारा खोला जाएगा। उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के साथ सविदा की प्रतियाँ भी हेग में भारत के राजदूतावास द्वारा डक प्राधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।

5(13) पूर्व की कड़िकाओं में उल्लिखित प्राधिकार पत्र की पावती के बाद आयातक का बैंक उक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर और बैंड आयात लाइसेंस के मद्दे अपने बैंकर के माध्यम से संभरक के नाम में एक साख पत्र खोलेगा। इस संबंध में सूचना सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

5(14) संभरक को भुगतान किए जाने के बाद संभरक का बैंक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को संभरक द्वारा विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाणपत्र के साथ इस संबंध में पोतलवान दस्तावेज के अपरकाम्य सेट और बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि बाद वाले से भुगतान प्राप्त हो गए हैं।

5(15) संभरक का बैंक संभरक से माल के उद्गम देश के संबंध में एक प्रमाण पत्र या एक प्रमाण (दो प्रतियों में) इस संबंध में प्राप्ति करेगा कि वह माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन के लिए चलन उद्गम देश के नियमों के अनुसार है और उसे सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा।

5(16) आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/माल के लदान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाण पत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे।

आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/माल के लदान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाण पत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे। आयातक को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि लदान दस्तावेज का एक परकाम्य सेट और बीजक की दो प्रतियों के साथ संभरक द्वारा भुगतान की पावती के सयध में विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाण पत्र और खंड 5(14) और 5(15) में उल्लिखित उद्यम प्रमाणपत्र माल के लदान से 15 दिनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दिए जाने हैं।

5(17) आयातक द्वारा साख पत्र के मद्दे भुगतान आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के आधार पर किए जाएंगे।

5(18) सामान्यतः सभी लदान/संभरकों के लिए भुगतान उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण कर दिए जाने चाहिए। ऐसे मामले में जहाँ लदान/संभरकों के लिए भुगतानों को 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण करने की संभावना नहीं तो आयातक को चाहिए कि वह निराशावाद रूप से लदान/संभरकों के लिए भुगतान को पूरा करने के लिए उपर्युक्त अवधि सीमा की समाप्ति से कम से कम एक मास पूर्व ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) से सम्पर्क स्थापित करें। इस प्रकार के आवेदन के साथ पुनर्विधित आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें मांगी गई अवधि वृद्धि भी शामिल हो। यदि इस प्रकार का आवेदन निर्धारित अवधि से पूर्व ही प्राप्त नहीं होता है तो सविदा के अप्रयुक्त शेष को अभ्यापित किया गया समझा जाएगा।

5(19) आयातक की ओर से आर्थिक कार्य विभाग को शीघ्र ही प्रतिपूर्ति दस्तावेज भेजने में किसी भी वृद्धि पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को आयातक के नाम में जारी किए गए सभी लाइसेंसों को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आयातक नुक करता रहे तो उसका मामला मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की कालीसूची में लिखने के लिए भेजा जा सकता है।

5(20) प्रतिपूर्ति दस्तावेज की पावती के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय नीवर लैंड पूंजीगत बैंक को पात्र स्रोत देशों से संभरकों को भुगतान की गई धनराशि को प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करेगा। नीवरलैंड पूंजीगत बैंक प्रतिपूर्ति की तारीख को नीदरलैंड में प्रचलित मुद्रा दर पर नीवरलैंड गिल्डर में समतुल्य धनराशि को प्रतिपूर्ति करेगा।

खंड 6 विधिवत्

6(1) आयातक को चाहिए कि वह लाइसेंस के उपयोग की स्थिति को दर्शाते हुए अनुबंध 7 के रूप में एक त्रैमासिक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेजे।

6(2) इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच यदि कोई झगड़ा उठता है तो भारत सरकार हमकी जिम्मेदार नहीं होगी। संभरक को भुगतान प्रभावी किए जाने से पूर्व ही उसके द्वारा पूर्व की जाने वाली शर्तें आयातक द्वारा साफ रूप से अनुबंध-2 में बता दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो झगड़े के निपटान से संबंधित एक व्यवस्था भी सविदा में शामिल की जाए।

6(3) लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों और आवेदों का तुरन्त पालन करेगा।

6(4) उपर्युक्त कड़िका में दी गई शर्तों का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाई की जाएगी।

अनुबन्ध-1

नीदरलैंड द्वारा द्विपक्षीय विकास ऋण के अतर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन

क. सामान्य

1. ये मार्ग-दर्शन द्विपक्षीय ऋण के अतर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति को शांति करते हैं जो कि शासकीय नीदरलैंड विकास सहायता कार्यक्रम का एक भाग है। ये ऋण विकासशील देशों के लिए उपलब्ध है। पात्र स्रोत देशों का सूची परिशिष्ट 'क' के रूप में सलग्न है। इस सूची में प्राप्तकर्ता देश हमसे शामिल है। नीदरलैंड की सरकार पात्र स्रोत देशों से सभरण को कर्मों को पूरा करने के लिए पात्र स्रोत से इतर स्रोत देशों से साहज और बीमा कीमतों सहित माल और सेवाओं के सीमित सभरण के नए व्यक्तिगत आधार पर सहमत हो सकती है।

2. नीदरलैंड्स की सरकार को इनके लिए अवश्य है। सतुष्ट हो जाना चाहिए कि ऋण से प्राप्त लाभ का उपयोग, अर्थ व्यनस्था, कार्य-क्षमता, अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में निपक्षता और पात्र स्रोत देशों के बीच बिना किसी भेद-भाव को ध्यान में रखते हुए और इन मार्ग-दर्शनों में बताई गई अधिप्राप्ति क्रियाविधियों के अनुसार किया जाना है।

3. कड़का 16 और 17 में उल्लिखित मामलों का छोड़कर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए जिससे यह पता चलता हो या यह परिणाम निकलता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष सभरण को या सभरणों का पक्ष लिया जा रहा है।

4. माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए ऋणी द्वारा अपनाए जाने वाले उद्गम के नियम और नियंत्रण इन मार्ग-दर्शनों के साथ परिशिष्ट 'ख' के रूप में सलग्न कर दिए गए हैं।

5. ऐसे मामले में जहां ऋणी पर अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता तो वह ऐसी व्यवस्थाएँ करेगा जिसे यह सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक है कि खरीददार इन मार्ग-दर्शनों का अनुपालन करता है।

6(1) ऋणी निम्नलिखित मामलों को छोड़कर औपचारिक उसी अंतराष्ट्रीय बोली के माध्यम से माल और सेवाएं प्राप्त करेगा—

(क) जहां नीदरलैंड परम्परागत या आयातों के लिए केवल एक मात्र स्रोत है

(ख) जहां आयातों का मूल्य डी एफ एल 1.25 मिलियन से कम है।

(ग) जहां इस प्रकार की क्रियाविधि लागू नहीं होती या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैंड्स सरकार और ऋणी देश के बीच करार किसी अन्य उचित क्रियाविधि से सभरणों को उनकी बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने से पूर्व ही पूरा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का करार राजकोष नीदरलैंड राजदूतावास के माध्यम से ऋणी द्वारा दो जाने वालों सभी संबद्ध जानकारी के आधार पर किया जाना है।

6(2) जहां भारतीय आयातकों और विदेशों सभरणों के बीच कायम वर्तमान सबंध और नीदरलैंड और या विकासशील देशों में उपलब्ध, और अधिजात सभरणों के अवसर के प्रकाश में ऋणी समझता है कि आयात केवल नीदरलैंड्स से ही प्रभावी किए जाने चाहिए तो खरीददार, केवल नीदरलैंड्स के लिए बोली को सीमित रखने के लिए या नीदरलैंड्स और साथ ही साथ पात्र स्रोत देशों से बोलिया प्राप्त करने के लिए विकल्प रखेगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31-33 के साथ मार्ग-दर्शन का अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 34-38 के साथ अनुच्छेद 30 लागू है।

7. ये मार्ग-दर्शन और साथ ही साथ उद्गम के नियम और पात्र स्रोत देशों की सूची नीदरलैंड की सरकार के सशोधनाधीन है।

ख. औपचारिक बोली अंतराष्ट्रीय बोली के लिए क्रियाविधि

(8) बोली के लिए आमंत्रण जारी करने समय (या ऋणी की ओर से खरीददार) निम्नलिखित दो प्रकाशनों में से कम से कम एक में बोली का विज्ञापन देगा—

भारतीय व्यापार पत्रिका

भारतीय नियति सेवा बुलेटिन

आयातक भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय सेवा बुलेटिन में तथा रिजपित निविदा नोटिस की तीन प्रतिदा भारत स्थित नीदरलैंड्स के राजदूतावास को भेजेगा।

9. प्रतियोगिता को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी अलग-अलग सविदाएँ जिनके लिए जब कभी संभव हो बोलिया आमंत्रित की जाती है वह इनमें बड़ी होनी चाहिए कि अंतराष्ट्रीय आधार पर बोलिया का आविष्कृत कर सके। दूसरी तरफ यह कि यदि तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि में एक परियोजना का विशेष प्रकार की सविदाओं में विभाजित करना संभव हो और इस प्रकार विभाजन से ऋणी को लाभ हो और/या इससे अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता बोलों और भी विशाल बन जाए ता परियोजना विभाजित की जानी चाहिए। अभियांत्रिक, उपकरण और निर्माण कार्य (सामान्यतः "टर्न की कान्ट्रैक्ट" के रूप में जाने जाते हैं) के लिए एकल सविदाओं की आछा की जा सकती है यदि वे उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक सविदाओं के भीतर ऋणी देश के लिए संपूर्ण लाभ अर्पण करती है।

10. विशेष रूप से सविदा कार्यों का सविदाओं के लिए औपचारिक पूर्व योग्यता का वांछा की जा सकती है। यदि पूर्व-योग्यता का वांछा की जाती है तो यह इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः संतोषजनक निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए (1) इसी प्रकार के कार्य में काम का पूर्व अनुभव (2) कामिक, उपकरण एवं संयंत्र के संबंध में इसकी क्षमता और (3) इसकी आर्थिक स्थिति और सबसता। पूर्व-योग्यता क्रियाविधि का विज्ञापन कड़िका 8 में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा। पूर्व-योग्यता के लिए विचार किए जाने वाले इच्छुक ठेकेदारों के लिए संक्षिप्त विशिष्टकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जब पूर्व-योग्यता लागू हो जाती है तो वे सभी कर्म जो पूर्व-योग्यता की शर्तों को पूरा करती है बोली के लिए अनुमत्त होंगी।

11. बोली के दस्तावेज उन भाषाओं में से किसी एक भाषा में तैयार किए जाएंगे जो अंतराष्ट्रीय पत्र-व्यवहार में साधारणतः प्रयोग को जाते हैं और जब तक कानूनी तौर पर रोक नहीं लगा दिया जाता इस बात का उल्लेख करेगी उक्त भाषा दस्तावेज के मूल पाठ में लागू रहेगी।

12. विशिष्टकरण में किए जाने वाले कार्य सभरण किए जाने वाले माल और सेवाओं तथा सुपुर्गों या सखापन की जगह के लिए जहाँ तक संभव हो साफ और सुस्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इंगित विशिष्टकरण के विषय के अनुकूल होगी, जहाँ वे अनुकूल नहीं होगी तो उसका मूल पाठ लागू होगा। विशिष्टकरण में मूल्यांकन के सिद्धांत और बोलियों की तुलना का उल्लेख करेगा जो तब लेख में दिए जाएंगे जब मूल्यांकन किए जाते हैं और बोलियों की तुलना की जाती है। विशिष्टकरण में इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे कि स्वतंत्र और संपूर्ण अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता को स्वीकृत एवं प्रोत्साहन मिल सके।

किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी स्पष्टीकरण गलतियों में सुधार और विशिष्टकरणों में परिवर्तन तथा बोली के लिए आमंत्रण से उनको सीधे ही अवगत करा दिया जाएगा जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया था।

13. यदि इस प्रकार के राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल होने आवश्यक हो तो विशिष्टकरण में यह बताया जाएगा कि वे माल जो अन्य अंतराष्ट्रीय स्वीकृत मानकों को पूरा करते हैं जिनमें उल्लिखित मानकों के अलावा उसके बराबर या अच्छी किस्म की मांग की गई हो तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे।

14. यदि विशेष फालतू पुर्जों की अपेक्षा की जाती है या यह निषेध किया जाता है कि कुछ अनिवार्य गुणकता को बनाए रखने के लिए एक विशेष मात्रा के मानकीकरण की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन और क्षमता पर आधारित होंगे और उनमें केवल नयी पंजीकृत मार्का नाम सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पाद निर्धारित होने चाहिए। अन्तिम मामले में विशिष्टिकरण में विकल्प की उन सामान के प्रस्तावों के लिए स्वीकृति दी जाएगी जिसमें मिलती-जुलती विशिष्टताएं हैं जिनका निष्पादन और क्वालिटी कम से कम उन विशिष्टिकृत स्तर के बराबर है।

15. बोली के लिए निमंत्रण में पात्र स्रोत देशों का उल्लेख किया जाएगा और उद्गम के लागू नियमों को बनाया जाएगा।

16. कोटेशन की जांच पात्र स्रोत देशों के संभरणों के बीच पूर्णतः बराबरी की शर्तों के आधार पर की जाएगी (इसमें माल और उपकरण के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ और अन्य करों और इसी प्रकार के प्रभावी करों की निःशुल्क कीमतों पर कोटेशन के मूल्यांकन भी शामिल हैं) लेकिन ऋणी देश माल और सेवाओं के संभरण के लिए बोली के मूल्यांकन और मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमतें शामिल नहीं हैं, स्थानीय माल और सेवाओं के लिए और उन अन्य पात्र स्रोत देशों के उत्पादों के लिए वरीयता की गुंजाइश देने के लिए जो गृह है या जो इस प्रकार के वर्ग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए अन्य पात्र स्रोत देशों में उत्पन्न होने वाले माल और सेवाओं के लिए प्राधिकृत है। वरीयता की यह गुंजाइश न्यूनतम मूल्यांकित विदेशी बोली के लागत बोमा भाड़ा पर 15 प्रतिशत या बोलीकार के देश में सीमा-शुल्क करों के वर्तमान स्तर इनमें जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी।

17. विशेष मामलों में ऋणी नोदरलैंड सरकार और ऋणी देश के बीच आपसी परामर्श करके कठिका 16 में उल्लिखित वरीयता की गुंजाइश के प्रतिरिक्त गृह के अनुकूल स्थानीय और क्षेत्रीय विनिर्माणकर्ताओं के लिए वरीयता की सीमित गुंजाइश को प्रदान कर सकता है। वरीयता के स्तर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय दर्जा या क्षेत्रीय स्वायत्त और प्रबंध और ऋणी देश के पंजीकरण या इन विनिर्माणकर्ता फर्मों के क्षेत्रीय प्राधिक वर्ग जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

18. बोली दस्तावेज में कोई भी सहमत वरीयताएं प्रवर्धित की जाएंगी और बोली के मूल्यांकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हें लागू किया जाएगा उसे भी बनाया जाएगा।

19. बोलीकारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें वे अपनी बोलियां प्रस्तुत करेंगे।

20. बोलियों को प्राप्त करने और बोली को खोलने के लिए अन्तिम तारीख समय और स्थान बोली के लिए नियंत्रणों में घोषित किया जाएगा और सभी बोलियां निर्धारित समय पर जनता के सामने खोली जाएंगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों को बिना खोले ही लौटा दिया जाएगा। बोलीकार का नाम प्रत्येक बोली या आवेदित या स्वीकृत यदि कोई विकल्पी बोली हो तो उसका कुल मूल्य कंची आवाज में पढ़ा जाएगा और उनका रिकार्ड रख लिया जाएगा।

21. किसी बोलीकार को बोलियां खोलने के बाद अपनी बोली में परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। केवल बोली के मूल में परिवर्तन से भिन्न स्पष्टीकरण स्वीकार किए जा सकते हैं। ऋणी किसी भी बोलीकार को अपनी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है किन्तु किसी भी बोलीकार की बोली के मूल में या अपनी बोली के मूल्य में परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा।

22. कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर जांच से सम्बद्ध कोई भी सूचना स्पष्टीकरण और बोली के मूल्यांकन तथा परिनिर्णय से संबंध

सिफारिश बोलियों के सार्वजनिक रूप से खुलने के बाद मफल बोलीकार के लिए सविदा के परिनिर्णय को घोषित करने से पूर्व किसी भी उस व्यक्ति को नहीं भेजी जाएगी जो ऋणी की ओर से या नोदरलैंड की सरकार की ओर से इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से संबद्ध नहीं है।

23. बोलियों के खोलने के बाद खरीददार उस बात का सुनिश्चय करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या बोलियों के परिफलन में महत्वपूर्ण गलतियों की गई है क्या बोलियां/बोली दस्तावेज की आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुकूल तो है क्या अपेक्षित गारन्टियों और जमानतों की व्यवस्था की गई है, क्या दस्तावेज सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिए गए हैं और क्या दस्तावेज अन्यथा रूप से सही है? यदि कोई बोली वास्तविक रूप से विशिष्टिकरण के अनुकूल नहीं होती है या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से वास्तव में बोली दस्तावेज के अनुकूल नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। तब आर्थिक दृष्टि से विस्तृत निर्धारण के साथ तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा जिससे प्रत्येक अनुकूल बोली का मूल्यांकन किया जा सके और बोलियों को मिलान के लिए समर्थ बनाया जा सके।

24. बोली के लिए निमंत्रण में बताया जाए कि खरीददार को ऐसी सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार है जब कोई बोली विशिष्टिकरण के प्रयोजन के अनुकूल नहीं है और जब प्रतियोगिता के अभाव का प्रमाण मिलता है या निम्न बोलियां उस पूर्व अनुमानित धनराशि की कीमत से अधिक होती हैं जो इस तरह की कार्रवाई को उचित बताने के लिए पर्याप्त है। यदि सभी बोलियां रद्द कर दी जाती हैं तो ऋणी नोदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ऐसी स्थितियों के कारणों की ओर निम्न बोली और अनुमानित कीमत में अन्तर के कारणों को जानने के लिए एक या एक से अधिक न्यूनतम बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है विशिष्टिकरण में परिवर्तन को परावर्तित करने वाली तय की गई या संविदाएं जिनमें परियोजना की अनुमानित कीमत में कमी हो सकती है उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन परियोजना के स्वरूप को वास्तविक रूप से नहीं बदलते। जहां परिवर्तन वास्तविक है वहां पुनः बोली उचित हो सकती है। इसे हर बार नोदरलैंड्स की सरकार द्वारा अनुमोदित कराना होगा।

25. बोलियों के मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में बताए गए नियम और शर्तों के अनुसार और बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से पूर्व इससे सम्बद्ध किसी भी आशोधन के अनुसार होने चाहिए। न्यूनतम मूल्यांकन बोली की स्पष्टी करने के प्रयोजनार्थ कीमत से भिन्न तथ्यों जैसे निर्माण कार्य या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय उपकरण की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता, इसकी सुपुर्दगी को समय और सेवा और फालतू पुर्जों की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा और जहां तक संभव हो सकेगा मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा वे मुद्रा जिनमें बोली कीमत को भुगतान किया जाएगा उनका मूल्यांकन बोली के मिलान के प्रयोजनार्थ सरकारी साधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा की दरों के आधार पर और बोली की अन्तिम तारीख को इस प्रकार के सौदे के लिए लागू दरों के आधार पर किया जाएगा।

26. संविदा का परि-निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा जिनकी बोली पूर्व की कठिकाओं में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्यांकन बोली निषेध की गई हो।

27. अनुरोध करने पर नोदरलैंड्स की सरकार को अधिप्राप्ति के सभी पहलुओं पर अपनी टिप्पणी और सिफारिश प्रदान करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। संविदा का परि-निर्णय होने के बाद नोदरलैंड्स की सरकार को ऋण के उपयोग के मूल्यांकन के लिए सभी सम्बद्ध दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी (उनकी प्रतियों सहित) प्रदान की जाएगी।

(ग) औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली से भिन्न अधिप्राप्ति की क्रियाविधि :

28. कड़िका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में कड़िका 31—39 में उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कड़िका 6 के अनुसार लागू हो सकते हैं।

29. मानकीकरण :

जहाँ खरीददार के पास अपने उपकरण के उचित मानकीकरण को बनाए रखने के लिए विषममतीय कारण हैं।

30. योग्य संभरकों की सीमित संख्या :

उन मामलों में जहाँ विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण योग्य संभरकों की संख्या सीमित है और खरीददार को मार्केट जानकारी ऐसी है कि उससे भागा को जा सकती है कि योग्य संभरकों के बारे में जाने।

31. औपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली :

सामान्य चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली के अंतर्गत खरीददार उन सीमित संख्या के (पूर्व) योग्य संभरकों से बोधिया आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत है जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य समझे जाते हैं।

ऐसे मामले में श्रुणी को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि किसी भी सम्भावित योग्य संभरक को छोड़ नहीं दिया गया है। जब और जैसे ही वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार, से पात्र स्रोत, देशों के सम्भावित संभरकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी जिससे कि वे उचित आधार पर भाग लेने में समर्थ हो सकें।

32. संभरकों का चुनाव केवल उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाना है और जहाँ तक संभव हो वे नोदरलैड्स सहित अनेक पात्र स्रोत देशों से चुने जाते हैं।

33. कड़िका 8 में उल्लिखित से भिन्न औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली की सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण रूप से लागू की जाती हैं।

34. औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति :

यदि औपचारिक प्रतियोगिता बोली की क्रियाविधियों के माध्यम से अधिप्राप्ति नहीं होती है तो वह संतोषजनक वाणिज्यिक नीति के अनुसार और पात्र स्रोत देशों के बीच बिना किसी भेद-भाव के प्राप्त करनी चाहिए।

35. आयातक को औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति के इच्छित उपयोग का विस्तृत और समयोजित प्रचार करना चाहिए। पात्र स्रोत देशों के संभरक जब भी ऐसी सूचना मांगेंगे, तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार उनको व्यापक आधार पर भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक सूचना देगी।

36. वरों और प्रस्तावों की तैयारी के लिए अनुमति समय शामिल की गई संविदाओं के स्वरूप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। साधन सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की अनुमति देने के लिए समय और वितरण दोनों की अनुसूचियाँ पर्याप्त लम्बी होगी।

37. कुछ विशेष मामलों में नोदरलैड्स सरकार सूर्यभाव कैसे प्राप्त किए गए थे इसके पूर्ण व्योरे सहित विक्रय किए गए माल, शामिल किए गए संभरकों और प्राप्त मूल्य वरों के सम्बन्ध में विक्तेताओं से सूचना मांग सकती है।

38. औपचारिक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण संभव सीमा तक यथोचित मार्ग-दर्शन लागू होना चाहिए।

39. एक मात्र संभरक :

निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में क्रेता का किसी एकमात्र संभरक से सीधे ही क्रय करने को अनुमति दी जाती है :—

- (1) एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह पजीकृत व्यापार विंक्षित नाम वाली पथ्यवस्तु शामिल है होती है जो आयातक द्वारा पुनः बिक्री के लिए हो, जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक या विनिर्माता हो ;
- (2) एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह पथ्य-वस्तु शामिल है जो विनिर्माण संसधान या संयोजन और उस अंतिम उत्पाद से पुनः विक्रय के लिए अधिप्राप्ति की जाती है जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित रूप से प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक विनिर्माता हो ;
- (3) पुर्जों की विनिमयशीलता का सुनिश्चय करने के लिए या विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण अधिप्राप्ति केवल एक ही स्रोत से पूर्ण की जा सकती है ;
- (4) क्रेता वह विनिर्माता हो जिसका साज-सामान और कर्षी सामग्री का फार्मूला कर्षी सामग्री की उस विशेष किस्म के जिस सर्वोत्तम उपयोग के लिए बनाया गया हो जो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त की जा सकती हो ;
- (5) यदि संभरक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के अर्धीन मूल रूप से प्राप्त की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना या पुहराना चाहता हो बशर्ते कि सम्पूरक अधिप्राप्ति मूल अधिप्राप्ति के मुकाबले में छोटी हो, केवल कुछ ही अवसरों पर पूर्ण की जाती हो और जब मूल अधिप्राप्ति से संबंधित निर्माण कार्य उस समय भी चल रहा हो या मूल अधिप्राप्ति पूर्ण करने के थोड़े ही समय बाद पूर्ण की जाती हो।
- (6) यदि सोदे का मूल्य डी०एफ० एल० 1.25 मिलियन से कम हो।

घ. परामर्शों के उपयोग के लिए मार्ग-दर्शन .

40. परामर्श देने वाली नियोजित संस्थाएँ इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए कि उनका परामर्श डिजाइन, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक पक्षपात से मुक्त हो और वे प्रतियोगिता के आधार का अनुपालन कर सकती हों। स्थानीय परामर्शदात्री संस्थाओं पर विचार करते समय राष्ट्रीय स्वामित्व का स्तर प्रबन्ध और कार्मिक तथा पंजीकरण जैसी बातों पर उचित ध्यान देना चाहिए।

41. परामर्शदात्री संस्थाओं के जयन के लिए औपचारिक प्रतियोगिता बोली क्रियाविधियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, जयन की प्रक्रिया में श्रुणी को उन प्रस्थापित संस्थाओं की यथोचित संख्या पर विचार करना चाहिए जिनमें कई पात्र स्रोत देशों में समर्थ और स्वतंत्र सेवाएँ अर्पित करने की आशा की जा सकती हो।

यह सूची निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व-मुणों पर आधारित होगी:—

- (1) कार्य की समान किस्मों में संस्था का पहला अनुभव ;
- (2) कर्मचारियों, साज-सामान और संयंत्र के संबंध में इस संस्था की क्षमता ; और
- (3) इसकी वित्तीय स्थिति और सबलता।

यह वाछनीय है कि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण भेजने में पहले ऋणी प्रत्याशित सस्थाओं को सूची नोदरलैड्स सरकार को प्रस्तुत करे। नोदरलैड्स सरकार का परामर्श के चयन को अस्वीकार करने का अधिकार है, इसके प्रतिरिक्त यह नोदरलैड्स में परामर्शदात्री क्षेत्र में अपनी जानकारी के आधार पर यह सुझाव दे सकती है कि हम सूची में वृद्धि की जाती है।

क. शिकायतें :

42. खरीददार बोली के संबंध में बोलियों को प्रस्तुत करने और मक्काओं के प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली शिकायतों को सुनने और उनकी जांच करने की व्यवस्था करेगा।

43. औपचारिक बोली क्रियाविधि के अंतर्गत की गई खरीद के मामले में बोली समाप्त होने की तिथि से पूर्व किए गए प्रतिबंध पण्य वस्तु विनिष्ठिकरण या आमतौर की प्रतिबंध अवधि के संबंध में विषयवस्तु की किसी भी शिकायत का समाधान बोलियों के खुलने से पूर्व ही किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो नोदरलैड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही उचित अवधि के लिए बोली के लिए अन्तिम तिथि स्थगित की जाए।

44. जब शिकायत संबंध संभरकों में से किसी एक के द्वारा की गई है तो शिकायत के विषय से संबंधित और इस पर की गई कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज नोदरलैड्स सरकार द्वारा और ऋणी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होंगे।

परिशिष्ट "क"

विकासशील देशों को संयुक्त द्विपक्षीय ऋण के लिए पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) नोदरलैड्स

(ख) अफ्रीका

उत्तरी साहारा

अल्जीरिया

लीबिया अरब गणराज्य

मोरक्को

तूनीसिया

मिश्र

बर्ज़िनी साहारा :

बोटस्वाना

बुरुण्डि

केमरून

केप वर्दी द्वीप समूह

मध्य अफ्रीका गणराज्य

चाद

कोमोरो द्वीप

कान्गो (जनवादी गणतन्त्र)

जेरी गणराज्य

दहोमी

इथोपिया

गीबन

गीम्बिया

घाना

गिनी

गिनी बिसाऊ

ग्राइबोरी कोस्ट

कीनिया

लिशीयो

लाइबेरिया

मालागासी गणराज्य

मलावी

माली

मरितेनिया

मारिशस

नाइजर

नाइजेरिया

रियूनियन

स्त्रान्दा

सैनेगाल

सेचलेज

सिबरा लैजोन

सोमालिया

टर फार और इसास

सेंट हेलेन और डेपेन्डेन्सिस

सूडान

स्थाजीलीण्ड

तन्जानिया

टोगो

उगान्डा

अपर बोल्टा

जाम्बिया

अमेरिका उत्तरी एवं मध्य :

बहामास

बारबेडोस

बरमदा

कोस्टा रिका

क्यूबा

डोमिनिकन गणराज्य

ई-1 सलबोडोर

गुडैलीप

गुस्डमाला

हैती

होनदुराज (ज)

होम्बरस (क)

जमेका

माटिनिक

मैक्सिको

नीदरलैण्ड्स अन्टलीज

निकारागुआ

पनामा

सेंट पेरी मिक्वेलोन

विनी दाव टोबागो

वेस्ट इन्डीज (क)

बर्ज़िनी :

अर्जेन्टीना

बोलीविया

ब्राजील

चिली

कोलम्बिया

इक्वाडोर

फाकलैण्ड द्वीप समूह

गुयाना

मिनी (फ)

पराग्वे

पीह

सुरीनाम
यूरोप
वीनेजयुले

एशिया मध्य पूर्वी

बैहरीन

इराक

इराक

इजराइल

जोर्डन

कुवैत

लेबनान

ओमान

कतार

सऊदी अरब

यमन (जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य)

सीरिया (अरब गणराज्य)

यमन (अरब गणराज्य)

बहिष्कृत एशिया

अफगानिस्तान

बंगला देश

भूटान

बर्मा

भारत

मालदिव

नेपाल

पाकिस्तान

श्री लंका

सुदूर पूर्व

तूनी

सेमर गणराज्य

हंगकांग

इन्डोनेशिया

कोरिया (गणराज्य)

कोरिया (जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य)

लाओस

मैकी

मालेशिया

फिलीपिन्स

सिंगापुर

थाईलैण्ड

तिमोर

वियतनाम (गणराज्य)

वियतनाम (प्रजातन्त्र गणराज्य)

सामुद्रिक

फिजी

गिलबर्ट एवं एलिस द्वीप समूह

फ्रेन्च पोलिनेशिया

न्यू कैलेडोनिया

न्यू हैवराइडज (ब्र एण्ड फ)

पेसिफिक द्वीप समूह (यू० ए०)

पैपीन्यू गिनी

सोलोमन द्वीप समूह

टोंगा

वालिस और फुतुना

पश्चिमी सामोवा

यूरोप

टर्की

पुर्तगाल

परिशिष्ट "ख"

उद्गम के नियम

1. उद्गम के इन नियमों की विषयाधीन मर्से पात्र स्रोत देशों में उत्पादित माल और सेवाएं होगी।
2. माल के मामले में नीदरलैंड्स से उद्गम का निर्धारण इस क्षेत्र में उस विधान के अधीन होगा जो कि यूरोपीय समुदाय में लागू है।
3. पैरा 2 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण नीदरलैंड्स के वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाएगा।
4. माल के मामले में विकासशील देशों के उद्गम का निर्धारण उस उद्गम नियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली की रूपरेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हों।
5. पैरा 4 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण विकामशील देशों के प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रपत्र 'ए' (जो अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया जाता है)। उद्गम में प्रमाण पत्र द्वारा भेजा जाएगा।
6. सेवाओं के मामले में (अर्थात् मार्ग त्रुटि का पैरा 1) उद्गम का निर्धारण नीदरलैंड सरकार और ऋण लेने वाले देशों के बीच आपसी परामर्श से तदर्थ आधार पर किया जाएगा।
7. ऐसे मामलों में जहां उद्गम के नियमों से वास्तव में कोई समस्या पैदा हो जाती है या ऋण लेने वाले देश को गम्भीर आर्थिक धाटा हा जाता है (उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावी सम्भरणों पर जबर्जस्त प्रतिबन्ध) तो इन नियमों से छुटकारा पाने की स्वीकृति दी जाती सकती है किन्तु वह केवल नीदरलैंड सरकार एवं ऋण लेने वाले देश के बीच आपसी परामर्श के बाद दी जा सकती है।

अनुबन्ध 2

- (ए) भारतीय आयातक का नाम और पता और/या जहां आवश्यक हो परियोजना अधिकारी का नाम व पता।
- (बी) संचरक का नाम और पता। यदि संचरक पात्र स्रोत देश के है तो उस मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी भेजी जानी चाहिए :-
 - (1) राष्ट्रिकता।
 - (2) पात्र स्रोत देशों के द्वारा रखे गए शेषों का प्रतिशत।
- (सी) (1) आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक।
 - (2) मूल्य।
- (डी) (1) नीदरलैंड्स/पात्र स्रोत देश में संचरक के बैंक का नाम और पता
 - (2) भारत में आयात का बैंक (यह वह बैंक होगा जिसने बैंक गारंटी दी है)।
 - (3) भारत में आयातक का बैंक जो कि आयातक के लिए पोतलवान वस्तावेज रिहा करने से पहले भारत के लेखे में रखा जमा करने के लिए उत्तरवायी होगा।

*निजी क्षेत्र के लिए।

**सार्वजनिक क्षेत्र के लिए।

- (इ) डच गिल्डरस में या पात्र स्रोत देश की मुद्रा में सविदा आदेश का मूल्य ।
- (एफ) अधिप्राप्ति की विधि, क्या यह सीधे खरीद पर आधारित है या औपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय बोली पर या चयन कार्मूला प्रन्त-राष्ट्रीय बोली के आधार पर, जिस मामले में यह संकेत किया जाना चाहिये कि क्या सविदा यदि कोई हो तो उन कारणों के साथ न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई है ।
- (जी) अयाप्त किये जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ।
- (एच) माल का उद्गम—यदि कोई हो तो गैर पात्र स्रोत देशों से आयातित सप्टकों का प्रतिशत ।
- (आई) सुपुर्दगी को पूरा करने की संभावित तिथि ।
- (जे) भुगतान की शर्त और संभावित वह तिथि जिस दिन इस सविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी ।
- (के) पोतखदान दस्तावेजों की विस्तृत सूची जैसे अवतरण बिल, बीजक, उद्यम प्रमाण पत्र आदि जिसे विकासशील देशों के लिये नीदरलैंड पुंजी निवेश बैंक या पात्र स्रोत देश में सभरकों के बैंक को चाहिये कि सभरको को भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों के साथ मांग करे ।
- (एल) यदि सविदा में शामिल है तो भारतीय एजेंट का वह कमीशन (ठीक-ठीक धनराशि संकेतित की जानी है) जिसे प्राधिकार पत्र जारी करते समय सविदा के मूल्य में से घटाना पड़ेगा, इस प्रकार का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेंटों को रुपये में आयातकों द्वारा सीधे ही किया जायेगा ।
- (एम) वह मूल्य जिसके लिये प्राधिकार पत्र अपेक्षित है ।
- (एन) बैंक गारंटी की संख्या, दिनांक और मूल्य इसमें उस अवधि का भी संकेत हो जिस तक यह वैध है ।
- (ओ) यदि कोई हो, तो विशेष अनुदेश ।

अनुबन्ध 3

उपबन्ध

सविदा प्रमाणपत्र

सविदा के ध्यौरे

- भारतीय आयात लाइसेंस की संख्या
1. सविदा की संख्या एवं दिनांक
 2. खरीददार को संभरित किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के ध्यौरे
(यदि बहुत सी मदों का संभरण किया जाना है तो प्रमाणपत्र में विस्तृत सूची लगाई जानी चाहिए)
 3. खरीददार को चुकाई जाने योग्य कुल सविदा कीमत (लागत-बीमा भाड़ा, लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का संकेत कीजिए)
डो० एफ० आई०
यदि माल का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्डों की पूर्ति अवश्य की जानी चाहिए ।
 4. नीदरलैंड्स में उत्पन्न नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत किन्तु वह उस माल की खरीद

सभरक द्वारा सीधे ही विदेशों से की गई है अर्थात् विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्री या सप्टकों का प्रतिशत ।

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य

(ख) मदों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण

5. यदि सेवाओं का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्ड की भी पूर्ति की जानी चाहिए ।

6. किए जाने वाले किसी काम का अनुमानित मूल्य या
(क) आपकी-कर्म (साइट इन्जीनियर प्रभारत आदि)

(ख) स्थानीय संभरक

द्वारा खरीददार के देश में निष्पादित की गई सेवा का उल्लेख कीजिए ।

7. उपर्युक्त कड़िका 4 और 5 के सम्बन्ध में यथा आवश्यक अर्हक टिप्पणियों

8. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सभरक द्वारा या नीचे उल्लिखित द्वारा नीदरलैंड्स में नियुक्त किया गया हूँ और इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है । एतद्वारा बचन देता हूँ कि उपर्युक्त कड़िका 4 और 5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं से भिन्न और किसी भी ऐसे माल या सेवा का इस सविदा के निष्पादन में संभरक द्वारा संभरण नहीं किया जाएगा जो नीदरलैंड्स मूल के नहीं है ।

हस्ताक्षरित

ग्रोहदा

सभरक का नाम और पता

.

दिनांक

नीदरलैंड्स वाणिज्यिक मंडल

प्रमाणित

अनुबन्ध 4

गारंटी बॉड

(इस सामान्य प्रमेलेन क्रेडिट के अन्तर्गत माल के आयात स सम्बन्धित प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंको द्वारा भेजा जाना है)

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के बदले (इसके बाद इसे सरकार' कहा गया) इस सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत जारी की गई शर्तों के अनुसार तथा ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण में दिनांक को जारी किया गया लाइसेंस स० का पालन करते हुए के द्वारा (बाद में इसे 'आयातक' कहा गया) के आयात के लिए डच गिल्डर में भुगतान के लिए राजी

होते हुए आयातक के अनुरोध पर हम (बैंक) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेग द्वारा भुगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन की चालू परिस्थिति दर पर जा इस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार परिकल्पित किया जाता है, जब सभरको को किए गए भुगतान की तारीख को सरकारी लेखों में क्रेडिट के लिए समतुल्य पयों के भुगतान की तारीख तक पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर पर और उससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर पर [जैसा कि सार्वजनिक सूचना 46-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16-6-76 में निर्धारित है] गणना किए गए ब्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पावती की प्राप्ति के वस दिना के भीतर विधि के साथ भारत सरकार को क्रेडिट के लिए और उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्ष के विपरीत संकेतित है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं, विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेग द्वारा प्राप्त आयात लखा का परकाम्य सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा जब कि ऊपर के अपेक्षित जमा रुपये पूरे कर लिए गए हों।

2 हम वि . . . (बैंक) सरकार जहाँ और जैसा भी, समय समय पर निदेश दें, आयातक द्वारा समय समय पर सरकार को बी जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य या उस पर कोई भी भ्रम जो आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और वेय रह गया है, जिसमें जब सभरको को भुगतान करने की तारीख से पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर पर और उससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर (वेखे पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना) गणना किया हुआ ब्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो २० से अधिक नहीं है, आयातक द्वारा भुगतान करने में देर होगी, तो उसकी भी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के सभध में जो राशि हमारे (बैंक) द्वारा दी जाती है, उस सभध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर (बैंक), अधिकतम और अनिवार्य होगा।

3 हम (बैंक) आगे इस बात पर सहमत हैं कि सविधा के अन्तर्गत मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या अधूरे भाल छुड़ाने की स्थिति में उसके मूल्य में वृद्धि होने की स्थिति में जैसा कि उपर्युक्त कड़िका I में बताया गया है, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारंटी बाड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम (बैंक) आगे इस बात पर सहमत हैं कि इस गारंटी में जो कुछ किया गया है, वो उल्लिखित करार/सविधा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगा और उसे तब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया पूर्ण रूपेण चुकता कर दिया गया हो और इसकी सारी मांगें पूरी न हो गई हो या उन्मुक्त न हो गई हो।

5 इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या दि (बैंक) के सविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि गारंटी को प्रमाणित किए बिना आयातक और दि (बैंक) पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय समय के लिए स्थगित करे। उपर्युक्त मामले के सभध में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान को दिया गया हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतन्त्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए

नियम या सरकार की ओर से बी गई, कूट या आयातक पर किए गए किसी तरह का अनुग्रह हो या और कोई सामला या बात चाहे जो भी हो, जो जमानतो से सबधित हो, (बैंक) पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6 अन्त में हम (बैंक) यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित रूप में परामर्श पाए बिना भुद्राकाल में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

7. हम (बैंक) सार्वजनिक सूचना सं० 15-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28-1-1972 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 108 आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 तथा इसके बाद समय समय पर जारी की जाने वाली ऐसी ही सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार अतिरिक्त निक्षेप करने का भी बचन देते हैं।

8 इस गारंटी के अन्तर्गत हए (इसमें ब्याज तथा अन्य प्रभार भी शामिल हैं, इसे गारंटी की धनराशि के 1% से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हमारी जिम्मेदारी है और यह गारंटी दिन* मास 19 तक लागू रखी जाएगी। जब तक इस गारंटी के अन्तर्गत 6 मास के भीतर लिखित रूप में मांगें पूरी नहीं कर ली जातीं, और जब तक उसके बाद तक दूसरे 6 मास के भीतर जो तक होगी और उनकी मांगों के लिए मुकवमा या कार्यवाही लागू न हो जाए, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे और हम लोग इसके अन्दर निहित सारी जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे।

. दिन का दिनांक,

वास्ते (बैंक)

श्री (नाम और मोहवा) के द्वारा

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत

हस्ताक्षर

*यह तारीख उस तारीख में एक मास और जोड़ कर गिनी जाएगी जिस तारीख तक सभरको को सभी भुगतान पूरे कर देने की सभावना है।

टिप्पणी—स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा न्याय निमित्त किया जाना है।

अनुबन्ध—5

संख्या—एफ 14() डब्ल्यू ई—3/7

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक . . .

सेवा में,

विकासशील देशों के लिए दि नीदरलैंड्स इन्वेस्टमेंट बैंक,

दि हेग,

नीदरलैंड्स

. लाख नीदरलैंड्स गिल्डर्स के ऋण के लिए समझौता

प्रिय महोदय गण,

प्रधिकार पत्र संख्या

भारत को आपके बैंक द्वारा दिए गए ऋण में से भारत के

सर्वश्री और हालैड के
सर्वश्री के बीच
चित्त युक्त किए जाने वाले सीदे के सबंध में अपने आज के आवेदनपत्र
के प्रसंग में हम एतद्वारा निवेदन करते हैं और उपर्युक्त सविदा की
शर्तों के अनुसार
एन० एफ० एल० मात्र की धनराशि हालैड में सभरक को चुकाने के लिये
आपको बिना शर्त और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करते हैं। यह निवेदन
किया जाता है कि उच्च सभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक, पोतलदान
और अन्य वस्तावेज का
(आयातक के बैंक)
सीधे भेज दिये जाए।

सभरकों का विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड एजी निवेश बैंक
को उस जिले के जिसमें नियंत्रित स्थित है, नीदरलैंड व्यापार मण्डल
द्वारा जारी किए गए/प्रमाणित किए गए प्रमाण-पत्र की इस सबंध में
दो प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत आने
वाले माल नीदरलैंड मूल के हैं।

कृपया नामे डालने की सूचना भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक
कार्य विभाग (आर्थिक सहायता लेखा शाखा) जीवन दीप बिल्डिंग, पालिया-
मेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भ्रममारित करें। यह प्राधिकार पत्र
..... तक बंध रहेगा।

कृते भारत का राष्ट्रपति
()

प्रतिनिधि
(आयातक के बैंक को)]

आयातक को मूल दस्तावेज रिहा करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चय
कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 8 आईटीसी (पी एन)/76
दिनांक 17-1-1976 और ऐसे ही सार्वजनिक सूचनाएं जो समय समय
पर जारी की जाएं उनमें निर्धारित तरीके में मुद्रा विनियम की मिश्रित
दर पर गणना किए जाने वाले समस्त रूप और उम पर सभरकों को
भुगतान की तिथि से सरकारी लेखों में धनराशि जमा कराने की तिथि
तक सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आईटीसी/पी एन/76 दिनांक 16-6-76
में निर्धारित दरो पर ध्याज जमा करा दिया गया है।

अनुबन्ध 6

भारत सरकार
वाणिज्य मन्त्रालय

संख्या एफ-4 () डब्ल्यू ई-3/

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली

विषय.—सामान्य प्रयोजन उच्च क्रेडिट के अन्तर्गत की गई सविदा प्रसिद्धि

प्रिय महादय,

सर्वश्री
..... ने

(भारतीय आयातक)

..... रूप (.....
..... रूप) के मूल्य के लिए सामान्य प्रयोजन उच्च
क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस मध्या
दिनांक के मद्दे लागत वीमा-भाडा/

लागत एवं भाड़े की
(.....) धनराशि के
लिए
के सभरण के लिए सर्वश्री
.....
(विदेशी सभरक)
के साथ सविदा की है। सविदा की एक प्रति संलग्न है।

2. ऊपर के रूप की धनराशि में से
भारतीय एजेंट के कमीशन के रूप में
धनराशि भारतीय मुद्रा में भ्रवा की जानी है। विदेशी मुद्रा में सभरक
को भ्रवा की जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विदेशी मुद्रा स्रोतों में से
अव्ययुक्त की जाएगी जिसकी बाद में
धनराशि तक उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट में से प्रतिपूर्ति की जानी है।

3. आपको उनके बैंकरो अर्थात् सर्वश्री
..... के माध्यम से सर्वश्री
..... के नाम
में इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर
और वैध प्रायात लाइसेंस के मद्दे, सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक
यू० सी प्रो० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते
हुए एक साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

4. मुद्रा विनियम नियंत्रण मनुषल के खण्ड 7 पैरा 10 के अनुसार,
आपको यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि साख पत्र की समाप्ति तिथि
सर्वाधिकतम प्रायात लाइसेंस में यथा उल्लिखित पोतलदान के लिए अन्तिम
तिथि के पैंतालीस (45) दिनों से ज्यादा नहीं है।

5. साख पत्र में यह भी प्रावधान होगा कि सर्वश्री
.....
(विदेशी सभरक)

अपरक्राम्य पोतलदान दस्तावेजों का एक सेट और बीजक की दो प्रतियां
जो उच्च सभरक द्वारा हम प्रमाण पत्र द्वारा पुष्ठांकित हो कि भुगतान
उनके द्वारा प्राप्त हो गया है, सीधे ही सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० प्रो० बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली को भेजेगा।

जिस जिला में नियंत्रित है उस जिले के नीदरलैंड व्यापार मण्डल
से साख पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल के नीदरलैंड मूल के होने के
संबंध में जारी किए गए/प्रमाणित किए गए/इस साख पत्र के अन्तर्गत
आने वाले माल उद्यम के सबंध में उचित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी
किए गए प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां भी वे प्राप्त करेंगे और नियंत्रक
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेंगे।

6. आप को, यदि कोई हो तो बैंक खातों को छोड़कर बीजक/माल
के पोतलदान के मद्दे आपके, द्वारा सर्वश्री
..... को किए गए
प्रेषण का एक प्रमाण पत्र भी सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित्त
मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० प्रो० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली को भेजना होगा।

7. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

()

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

सविषय की प्रति के साथ प्रति इनको प्रेषित :—

1. भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा विनियम नियंत्रण विभाग, बम्बई-1

2. प्रति निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :—

(1)

(भारतीय आयातक)

यह सुनिश्चय कर लिया जाए कि सर्वश्री

(विदेशी बैंकर)

ने नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू० सी० ओ० बैंक ब्रिडिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भुगतान बीजक सहित पोतलदान और अन्य दस्तावेजों (अप्रकाश्य) का एक सेट, बीजक की दो प्रतियां जिस पर संभरक द्वारा यह प्रमाण-पत्र विधिवत पृष्ठांकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां भेज दी गई है।

(2) सर्वश्री

(विदेशी बैंक)

आप से यह अनुरोध है कि प्रत्येक आदायगी पर भुगतान बीजक सहित पोतलदान और अन्य दस्तावेजों (अप्रकाश्य) का एक सेट बीजक की दो प्रतियां जिस पर संभरक द्वारा यह प्रमाण पत्र विधिवत पृष्ठांकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक ब्रिडिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेज दी जाए।

(3) नियंत्रक, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू० सी० ओ० बैंक ब्रिडिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

अनुबन्ध 7

इस (सामान्य उद्देश्य) क्रेडिट के अंतर्गत उपयोग के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट को प्रदर्शित करने वाला विवरण

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. दिए गए आदेशों का मूल्य
5. प्राधिकार-पत्र की संख्या और दिनांक
6. प्राधिकार-पत्र की धनराशि
7. प्राधिकार-पत्र की वैधता की तारीख
8. त्रैमासिक के दौरान उपयोग की गई धनराशि इस गिल्डर
9. उपयोग की गई कुल धनराशि इस गिल्डर
10. सरकारी खाते में जमा की गई कुल धनराशि रुपए
11. आगामी त्रैमासिकों के दौरान किया जाने वाला भुगतान
12. अव्यवस्था, यदि कोई हो

परिशिष्ट II

इस सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए शर्तें

खण्ड 1, सामान्य

1 (1) नीदरलैंड्स इन्वेस्टमेंट बैंक और आंटविकलिम सेंडिंग एन० बी० द्वारा प्रदान किए गए 1977-78 के लिए इस सामान्य प्रयोजन क्रेडिट को विक्रयशील देशों के लिए खोल दिया गया है। तदनुसार इस क्रेडिट के अधीन वित्तयुक्त किए जाने वाले माल एवं पण्य-वस्तुएं एवं इससे संबंध आनुषांगिक सेवाएं नीदरलैंड्स से आयात की जा सकती हैं और परिशिष्ट 'क' के रूप में 'नीदरलैंड्स द्वारा द्विपक्षी विकास ऋण के अंतर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन' सूची में सम्मिलित सभी देश (अनुबन्ध-1) इस क्रेडिट के अंतर्गत 'पात्र लोग' देश होंगे। दोनों साथ करारों अर्थात् डी एफ एल 1.20 मिलियन और डी एफ एल 54 मिलियन प्रतिपूर्ति की अंतिम तिथि 31-12-1980 होगी।

1 (2) किन्तु पात्र के इतर स्रोत देशों से रसायन के संबंध में 10% की सीमा तक और अन्य आयातों के संबंध में 20% की सीमा तक के संघटकों को इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है। यदि कोई हो तो इस संबंध में विशिष्ट आवेदन संविदा पूर्ण होने से पूर्व ही वित्तमन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को किए जाने चाहिए।

1 (3) इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्त दान के लिए पात्र स्रोत देशों से उपयुक्त खंड 1(2) में संकेतित सीमा से अधिक संभरण को संपूर्ण बनाने के लिए पात्र से भिन्न देशों से माल और सेवाओं के सीमित संभरणों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके लिए नीदरलैंड्स की सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

खंड 2—आयात लाइसेंस जारी करना

2(1) आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा। वैध अवधि में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह वैध अवधि के भीतर ही सबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करे जो इस मामले में आर्थिक-कार्य-विभाग से परामर्श लेगा।

2(2) उसके आदेश नीदरलैंड्स में समुद्रपार संभरकों को या अनुबन्ध 1 में उल्लिखित देशों को लागत बीमा भाड़ा/लागत तथा भाड़ा के आधार पर अवश्य दिए जाने चाहिए और आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 4 मास के भीतर ही आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। यदि उसके आदेश देने का निर्णय निर्धारित चार मास की अवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह जैसा भी मामला हो, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए कि क्यों नहीं प्रारम्भिक वैध अवधि के भीतर ही आदेश देने का काम पूरा हो सका, इसके औचित्य एवं आख्या के साथ आदेश देने की अवधि में वृद्धि की मांग करने के लिए प्रस्ताव रखें। आदेश देने की ऐसी अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन पर विचार प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और चार मास की अवधि की वृद्धि दे सकते हैं। लेकिन, यदि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 8 मास से अधिक की वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरावध रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अर्थ कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) वित्त मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए।

2(3) लाइसेंस पर (इस सामान्य प्रयोजन क्रेडिट) अंकित होगा और यह उस सार्वजनिक सूचना की मध्या का संकेत करेगा जिसके अन्तर्गत यह लाइसेंस शर्तें जारी की जाती हैं। प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिए

लाइसेंस कोड 'एम'/'एन एन' होंगे। इस लाइसेंस कोड का उल्लेख सभी पंतिवदान प्रलेखों में होना चाहिए और साथ ही साथ रुपया जमा करने समय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रेषित प्रपत्र "एम" में इसका उल्लेख होना चाहिए।

2(4) जैसे ही आयातक आयात लाइसेंस प्राप्त करता है उसे चाहिए कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ बिल मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को एक रिपोर्ट भेजे :—

- (i) आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक
- (ii) मूल्य
- (iii) यदि कोई हो तो आयात लाइसेंस में संकेतित मुद्रा विनिमय दर
- (iv) वह तारीख जिस तक आर्थिक कार्य विभाग को संविदा की प्रतियां भेजने की संभावना है।

खंड 3—क्रेडिट को पूर्ण करना

3(1) इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तबान के लिए पात्र संविदा का न्यूनतम मूल्य डी एक एल—25,000 होगा।

3(2) आयात लाइसेंस के मुद्दे एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक सविदा करने के लिए अनुमति दी जाएगी जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के तुरन्त बाद ही बिल मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

3(3) माल के आयात के लिए सविदा और नीदरलैंड से सेवाओं और पात्र ओत देशों का निश्चय अनुबंध में यथा उल्लिखित माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

3(4) निम्नलिखित मामलों की छोड़कर माल और सेवाएं औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से प्राप्त की जाएगी :—

- (क) जहां नीदरलैंड आयातों के लिए परम्परागत या केवल एक-मात्र स्रोत है ; या
- (ख) अठों आयातों का मूल्य डी एक एल 1.25 मिलियन से कम का है ; या
- (ग) जहां ऐसी क्रिया-विधि लागू नहीं है या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैंड सरकार और भारत सरकार के बीच करार किसी और अधिक उचित क्रिया-विधि के आधार पर संभरण के लिए संविदापूर्ण हो जाने के पूर्व ही निश्चित रूप से तय हो जाना चाहिए।

3(5) निम्नलिखित मामलों में औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं होगा :—

- (क) जहां क्रेता के पास अपने उपकरण के पर्याप्त मासकीकरण को बनाए रखने के लिए सुविधापूर्ण कारण है।
- (ख) उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण योग्य संभरणों की संख्या सीमित है और क्रेता की मार्केट जानकारी ऐसी है कि उसके यह आशा की जा सकती है कि वह योग्य संभरणों को जानता हो।
- (ग) जहां भारतीय आयातकों और विदेशी संभरणों के बीच चल रहे वर्तमान सम्बन्ध और नीदरलैंड और/या विकासशील देशों में उपलब्ध और समरूप संभरणों के क्षेत्र को ध्यान में रखते

हुए कर्जदार यह समझता है कि आयात केवल नीदरलैंड से ही प्रभावी होने चाहिए। ऐसे मामलों में माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन (अनुबन्ध I) की कड़िका 31 से 39 में निहित अधिप्राप्ति का नियम अपनाया जाना चाहिए।

3(6) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में क्रेता किसी भी एकमात्र संभरण से सीधे ही माल खरीद सकता है :—

- (i) वाणिज्यिक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में पंजीकृत ब्राड नाम की वह पण्य वस्तु शामिल होती है जो आयातक द्वारा पुनः बेचने के लिए है और जिसके लिए आयातक संभरण का नियमन प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरण एकमात्र वितरक है या विनिर्माणकर्ता है ;
- (ii) वाणिज्यिक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में वह पण्य-वस्तु शामिल होती है जो विनिर्माण प्रक्रियागत करने या अंतिम उत्पाद के सज्जीकरण और पुनः बिक्री के लिए प्राप्त की जाती है और जिसके लिए आयातक संभरण का नियमन प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरण विनिर्माणकर्ता है ;
- (iii) विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पुर्जों की अवला-बदली का सुनिश्चय करने हेतु अधिप्राप्ति केवल एक स्रोत तक की जा सकती है।
- (iv) आयातक एक ऐसा विनिर्माणकर्ता है जिसके उपकरण और कच्चे माल का फार्मुला ऐसे कच्चे माल की, विशेष किस्म के साथ अधिक से अधिक उपयोग के लिए बनाए गए है जो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं ;
- (v) आयातक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के अंतर्गत मूल रूप से की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना चाहता है या फिर से उसे प्राप्त करना चाहता है वशत कि मूल अधिप्राप्ति की तुलना में अनुपूर्वक अधिप्राप्ति कम है, और कुछ अवसर पर ही की जाती है और जब मूल अधिप्राप्ति के संबंध में निर्माण कार्य अभी चल रहा है या मूल अधिप्राप्ति के तुरन्त बाद ही की जाती है ;
- (vi) सौदे का मूल्य डी० एक० एल० 1.25 मिलियन से कम है।

3(7) परामर्शदाता फर्मों के चुनाव के लिए औपचारिक प्रतियोगी बोली क्रिया विधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, भारतीय फर्मों द्वारा परामर्शदाता फर्मों को सुझावों के लिए नियंत्रण भेजने से पूर्व ही ऐसी भावी फर्मों की एक सूची बिल मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए। इसके बाद सूची नीदरलैंड की सरकार को भेजी जाएगी जो इसे स्वीकृति दे सकती है या परामर्शदाता की पसंद को रद्द कर सकती है। और नीदरलैंड में परामर्शदाता क्षेत्र की जानकारी के आधार पर इस सूची को बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकती है।

3(8) जहां औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर माल की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव किए जाते हैं तो आयातक को चाहिए कि वह जैसे ही निविदा नोटिस भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय निर्यात बुलेटिन में विज्ञापन के लिए भेजे जाएं उसी समय इसकी तीन प्रतियों को बिल-मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग), नई दिल्ली को अर्पण करते हुए भारत में नीदरलैंड के राजदूतावास को भेज दे।

3(9) खंड 2(2) में उल्लिखित "पुष्टि आवेदन" शर्त का अर्थ है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरण को दिया गया वह आवेदन जो बाद वाले के पुष्टिकरण आवेदन द्वारा विधिवत समर्थित हो या 'कब संविदा

जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकृतों पर आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकृतों के पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

3(10) यदि संविदा डच संभरक के साथ की गई तो संविदा के लागत बीमा भाड़ा/लागत एवं भाड़ा मूल्य को, डच गिल्डर में व्यक्त करना चाहिए और यदि संविदा पात्र स्रोत देशों के संभरकों के साथ की गई हो तो उनको मुद्रा में व्यक्त करना चाहिए।

3(11) संविदा में भुगतान की व्यवस्था तकद आधार पर होनी चाहिए अर्थात् पोत-खदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर विदेशी संभरकों भारतीय आयातकों को किसी भी प्रकार की साख-सुविधा उपलब्ध करने की स्वीकृति नहीं देंगे।

3(12) संविदा के मूल्य में सम्मिलित भारतीय अधिकृतों के कमीशन की धराराश को विशेष रूप से अंकित किया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान भारतीय अधिकृतों को भारतीय रूप में किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा में प्रेषण स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के भाग के रूप में होंगे और इसलिए लाइसेंस के लिए वसूल किए जाएंगे।

3(13) क्रय आदेश और संभरक के पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में ही होने चाहिए।

3(14) संविदा में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए :—

- (i) संविदा भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। यदि संविदा का मूल्य डच गिल्डर्स में 50,000 या इससे कम हो (और यह भारत सरकार तथा नीदरलैंड सरकार दोनों के अनुमोदन के अधीन है यदि संविदा का मूल्य डच गिल्डर्स 50,000 से अधिक हो जाता है)
- (ii) यह संविदा डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के लिए लाइसेंस शर्तों के अंतर्गत दी गई भुगतान क्रिया-विधि द्वारा संचालित होगी और इस संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बावजूद ही यह प्रभावी होगी।
- (iii) "माल डच मूल्य/विनिर्माण के हैं" (नीदरलैंड्स में संभरकों के मामले में)

या

"माल मूल्य/विनिर्माण के हैं" (पात्र स्रोत देशों के संभरकों के मामले में)

- (iv) नीदरलैंड्स से आयात किए जाने वाले माल के लिए संभरकों को नीदरलैंड्स पूंजी निवेशक बैंक को उस जिले से नीदरलैंड वाणिज्य मंडल द्वारा जिसमें संभरक स्थापित है जारी किया गया/प्रमाणित किया हुआ इस बारे में एक प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में देना पड़ेगा कि माल नीदरलैंड्स मूल का है। यह प्रमाण-पत्र भुगतान प्राप्ति करते समय अन्य पोत-खदान दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रमाण-पत्र का एक नमूना अनुबंध-3 में दिया गया है।

पात्र स्रोत देशों के संभरकों के मामले में संभरकों को "माल और सेवाओं" की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग-दर्शन (अनुबंध-1) में दिए गए उद्गम में दिए गए उद्गम नियमों के अनुसार एन० आई० ओ० को माल के उद्गम का प्रमाण देना पड़ेगा।

3(15) जहां प्रभावित निष्पादन गारंटी के अपेक्षित हों वहां संभरकों से बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

खंड-4 भारत सरकार/नीदरलैंड पूंजी निवेशक बैंक द्वारा संविदा का अनुमोदन

4(1) संविदा पूर्ण होने के तुरन्त बाद ही आयातकों को आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति के साथ संविदा/संभरण आदेश की 5 फोटो या प्रमाणित प्रतियां वाणिज्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेजनी चाहिए। पात्र स्रोत देशों के संभरकों के साथ पूर्ण की गई संविदाओं के मामले में उसकी 8 प्रतियां भेजी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयातक के लिए अनुबंध-2 में उल्लिखित सूचना भी भेजना आवश्यक है।

4(2) जब संभरक संविदा औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली या औपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली पर आधारित हो तब निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत की जानी चाहिए :—

- (i) उस प्रकाशन का नाम जिसमें संविदा सूचना विज्ञप्ति की गई थी।
- (ii) उन पार्टियों के नाम जिन्होंने संविदा पृष्ठताछ के मद्दे नज़र रखा है।
- (iii) विशिष्ट प्रस्ताव को चुनने के लिए कारण और यह भी बताया जाए कि यह संविदा न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त बोली थी।

4(3) यह संविदा दस्तावेज, प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन, आयात लाइसेंस और बैंक गारंटी सभी पाए जाते हैं तो वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग संविदा की प्रतियों को हेग में भारत के राजदूतावास के माध्यम से डच प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजेगा।

4(4) (क) 50,000 डच गिल्डर या इससे कम मूल्य की संविदाओं के संबंध में डच प्राधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के अनुमोदन के बारे में भारतीय आयातक को उनकी संविदा संभरण आदेश की प्रतियां डच प्राधिकारियों को भेजते समय बता दिया जाएगा।

4(4) (ख) 50,000 डच गिल्डर से अधिक संविदाओं के लिए जैसे ही डच क्रेडिट के अंतर्गत डच प्राधिकारियों द्वारा संविदा के वित्तदान के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, आयातक को यह सूचित कर दिया जाएगा कि उनकी संविदा प्रभावी हो गई है।

खंड-5 संभरकों को भुगतान

(क) नीदरलैंड के संभरकों को भुगतान

5(1) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूंजी निवेशक बैंक दि हेग को एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध-7 के रूप में) हेग में भारत के राजदूतावास के माध्यम से पोत-खदान दस्तावेज के मद्दे संभरकों के लिए भुगतान को प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा और संविदा प्राप्ति की प्रतियों के साथ उसे डच प्राधिकारियों को अग्रप्रेषित किया जाएगा।

5(2) प्राधिकार पत्र की वैधता का सुनिश्चय संविदा में निविष्ट वितरण अनुसूची को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। किसी भी मामले में प्राधिकार पत्र आयात लाइसेंस की वैधता के बावजूद वैध नहीं होगा।

5(3) चूंकि क्रेडिट के अंतर्गत सामान्यतः डच बैंक द्वारा संभरकों को भुगतान पोत-खदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के मद्दे दिए जाते हैं अतः इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान किए गए आयातों के लिए रियायती अवधि की सुविधा लागू नहीं होगी।

5(4) संभरकों को पोत-खदान/भुगतान प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के भीतर पूरा न किया जाने के मामले में आयातक को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) के साथ प्राधिकार पत्र में छपयुक्त वृद्धि के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। यदि भागी

गई वृद्धि अवधि मूल आयात लाइसेंस की वैधता से अधिक हो तो पुनर्वैध मूल आयात लाइसेंस की फोटो प्रति और बैंक से वह पत्र जिसमें बैंक गारन्टी की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है, आवेदन पत्र के साथ भेजी जानी चाहिए।

5(5) यदि प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन प्राधिकार पत्र की वैधता तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो जाती तो प्राधिकार पत्र में अप्रयुक्त शेष धनराशि वापिस कर दी समझी जाएगी और प्राधिकार पत्र अपने आप खत्म हो गया समझा जाएगा।

5(6) मूल परलाम्प्य पोत-लवान दस्तावेज निरपवाद रूप से नीदरलैंड पूजी निवेशक बैंक द्वारा भारत में सबधित आयातक के बैंक को भेजे जाएंगे। वह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंको में से किसी एक बैंक की शाखा होगी जिसे यह सुनिश्चित करने के बाद ही सबधित आयातक को पराक्राम्य दस्तावेज रिहा करने चाहिए कि आयातक से निम्नलिखित को जमा कर दिया है—

(1) सार्वजनिक सूचना सं० 8-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 17 जनवरी, 1976 में यथा निर्धारित और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं में समय-समय पर यथा अधिसूचित या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से गणना की जाने वाली प्रचलित मिश्रित दर पर बच गिरुद्धर में सभरकों की भुगतान के समतुल्य रूप।

(2) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूजीगत निवेश बैंक एन वी वि हेग द्वारा सभरको को वास्तविक भुगतान की तारीख से आयातक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारों, दिल्ली या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में समतुल्य रुपये के वास्तविक निक्षेप की तिथि तक निश्चित जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि के लिए देखें उपयुक्त (1) सार्वजनिक सूचना सं० 48-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर और 30 दिनों की अवधि से अधिक के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज।

5(7) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित भारतीय बैंक की होगी कि आयातक को आयात दस्तावेज सीपने से पूर्व ही वेय धनराशि सरकार के लेखे में ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है। लाइसेंस धारी को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंकरो से दस्तावेजों की मुपुर्वगी लेने से पूर्व ही वेय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे में जमा करा दी जाती है।

5(8) सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों को अपेक्षित रुपया निक्षेप केवल विदेशी मुद्रा विनियम के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से करना चाहिए और सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई० टी० (पी० एन०)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 में यथा अपेक्षित लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति भी उनके द्वारा पृष्ठांकित करवा लेनी चाहिए। अपेक्षित प्रपत्र "एस" सम्बन्धित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई को भेज दिया जाएगा।

5(9) खंड 5(6) में उल्लिखित धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारों शाखा, दिल्ली या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के पास केन्द्रीय सरकार के लेखे में निक्षेप के लिए निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा की जानी चाहिए—

"के—डिपोजिट्स एंड एक्वासांजे डिपोजिट नाट बियरिंग इन्ट्रेस्ट—
843—सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फॉर परचेजिस एटसेट्रा एक्वांड—परचेजिस एटसेट्रा अउर डब जनरल परपज क्रेडिट
1977-78"

5(10) उपर्युक्त उल्लिखित रूप निक्षेप की सूचना वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 31 मई, 1974 और 68 GI/78—3

सं० 103-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12-10-76 से निधार्णि प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल खजाना चासान को भी भेजना चाहिए। प्राधिकार पत्र सं० के सम्बन्ध में सूचना, विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके लिए रुपया निक्षेप किया गया है, डच संभरक को भुगतान की तिथि, ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है, निरपवाद रूप से राजकोष चासान में सकेतिक की जानी चाहिए।

(ख) पात्र स्रोत देशों को भुगतान

5(11) आयातक द्वारा उसके आवेदन-पत्र में यथा सकेतिक संभरक के नाम से पात्र स्रोत देश में संभरक के बैंक के लिए साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र (अनुबन्ध 1-8 के रूप में) वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई 3 अनुभाग) द्वारा खोला जाएगा। उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के साथ सविदा की प्रतियां भी हेग में भारत के राजदूतावास द्वारा डच प्राधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।

5(12) पूर्वी की कंठिकाओं में उल्लिखित प्राधिकार पत्र की पावती के बाद आयातक का बैंक उक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर और वध आयात लाइसेंस के मद्दे अपने बैंक के माध्यम से संभरक के नाम में एक साख पत्र खोलेगा। इस सम्बन्ध में सूचना सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

5(13) संभरक को भुगतान किए जाने के बाद संभरक का बैंक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को संभरक द्वारा विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाण-पत्र के साथ इस सम्बन्ध में पोतलवान दस्तावेज के अपरक्राम्य सेट और बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि भाव वाले से भुगतान प्राप्त हो गए हैं।

5(14) संभरको का बैंक संभरक के मालक के उद्गम देश के सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र या एक प्रमाण (दो प्रतियों में) इस सम्बन्ध में प्राप्त करेगा कि वह माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शानि के लिए सलग्न उद्गम देश के नियमों के अनुसार है और उसे सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगी।

5(15) आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/मास के लवान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाण-पत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे। आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/मास के सदान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाण-पत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे। आयातक को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लवान दस्तावेज का एक परक्राम्य सेट और बीजक की दो प्रतियों के साथ संभरक द्वारा भुगतान की पावती के सम्बन्ध में विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाण-पत्र और खंड 5(13) और 5(14) में उल्लिखित उद्गम प्रमाण-पत्र माल के लवान से 15 दिनों के भीतर वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, सहायता लेखा परीक्षा नियंत्रक, को भेज दिए जाते हैं।

5(16) आयातक द्वारा साख पत्र के मद्दे भुगतान आयात लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के आधार पर किए जायेंगे।

5(17) सामान्यतः सभी लदान/संभरकों के लिए भुगतान उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण कर दिए जाने चाहिए। ऐसे मामलों में जहां लदान/संभरकों के लिए भुगतानों को 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण करने की सभावना न हो तो आयातक को चाहिए कि वह निरपवाद रूप से लदान/संभरकों के

लिए भुगतान को पूरा करने के लिए उपर्युक्त अवधि सीमा की समाप्ति से कम से कम एक मास पूर्व ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) से संपर्क स्थापित करे। इस प्रकार के आवेदन के साथ पुनर्विध आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें मार्ग गई अवधि वृद्धि भी शामिल हो। यदि इस प्रकार का आवेदन निर्धारित अवधि से पूर्व ही प्राप्त नहीं होता है तो संविदा के अप्रयुक्त शेष को अम्यापित किया गया समझा जाएगा।

5(18) आयातक की ओर से आर्थिक कार्य विभाग को शीघ्र ही प्रतिपूर्ति वस्तावेज भेजने में किसी भी वृद्धि पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को आयातक के नाम में जारी किए गए सभी लाइसेंसों को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आयातक जूक करता रहे तो उसका मामला मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को काली सूची में लिखने के लिए भेजा जा सकता है।

5(19) प्रतिपूर्ति वस्तावेज की पावती के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, नीदरलैंड पूंजीगत बैंक को पात्र स्रोत देशों से संभरकों को भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करेगा। नीदरलैंड्स पूंजीगत बैंक प्रतिपूर्ति की तारीख को नीदरलैंड में प्रचलित मुद्रा दर पर नीदरलैंड गिल्डर में समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

खंड 6—विधि

6(1) आयातक को चाहिए कि वह लाइसेंस के उपयोग को दर्शाते हुए अनुबंध 9 के रूप में त्रैमासिक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-3 अनुभाग) को भेजे।

6(2) इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच यदि कोई सगड़ा उठता है तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। संभरक को भुगतान प्रभावी किए जाने से पूर्व ही उसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें आयातक द्वारा माफ रूप से अनुबंध-2 में बता दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो झगड़े के निपटान से संबंधित एक व्यवस्था भी संविदा में शामिल की जाए।

6(3) लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों और आदेशों का तुरन्त पालन करेगा।

6(4) उपर्युक्त कड़िका में दी गई शर्तों का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध-I

नीदरलैंड्स द्वारा द्विपक्षीय विकास ऋण के अस्तंगत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन

क. सामान्य

1. ये मार्गदर्शन द्विपक्षीय ऋण के अस्तंगत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति को शासित करते हैं जो कि शासकीय नीदरलैंड्स विकास सहायता कार्यक्रम का एक भाग है। ये ऋण विकासशील देशों के लिए उपलब्ध हैं। पात्र स्रोत देशों की सूची परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है। इस सूची में प्राप्तकर्ता देश इसमें शामिल हैं। नीदरलैंड्स की सरकार पात्र स्रोत देशों से संभरण की कमी को पूरा करने के लिए पात्र स्रोत से इतर स्रोत देशों से वाहन और बीमा कीमतों सहित माल और सेवाओं के सीमित संभरण के लिए व्यक्तिगत आधार पर सहमत हो सकती है।

2. नीदरलैंड्स की सरकार को इसके लिए अवश्य ही संतुष्ट हो जाना चाहिए कि ऋण से प्राप्त लाभ का उपयोग, प्रथी व्यवस्था, कार्यक्षमता, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निष्पक्षता और पात्र स्रोत देशों के बीच बिना किसी भेदभाव को ध्यान में रखते हुए और इन मार्गदर्शनों में बताई गई अधिप्राप्ति क्रियाविधियों के अनुसार किया जाना है।

3. कड़िका 16 और 17 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए जिससे यह पता चलता हो या यह परिणाम निकलता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष संभरक को या संभरकों का पक्ष लिया जा रहा है।

4. माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए ऋणी द्वारा अपनाए जाने वाले उद्गम के नियम और नियंत्रण इन मार्गदर्शनों के साथ परिशिष्ट 'ख' के रूप में संलग्न कर लिए गए हैं।

5. ऐसे मामले में जहां ऋणी पर अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह ऐसे व्यवस्थाएं करेगा जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि खरीददार इन मार्गदर्शनों का अनुपालन करता है।

6(1) ऋणी निम्नलिखित मामलों को छोड़कर औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से माल और सेवाएं प्राप्त करेगा :—

(क) जहां नीदरलैंड्स परम्परागत या आयातों के लिए केवल एक-मात्र स्रोत है,

(ख) जहां आयातों का मूल्य डी० एफ० एल० 1.25 मिलियन से कम है,

(ग) जहां इस प्रकार की क्रियाविधि लागू नहीं होती या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैंड्स सरकार और ऋणी देश के बीच करार किसी अन्य उचित क्रियाविधि से संभरकों को उनकी बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने से पूर्व ही पूरा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का करार राजकीय नीदरलैंड्स राजदूतावास के माध्यम से ऋणी द्वारा दी जाने वाली सभी सम्बद्ध जानकारी के आधार पर किया जाना है।

6(2) जहां भारतीय आयातकों और विदेशी संभरकों के बीच कायम वर्तमान संबंध और नीदरलैंड्स और/या विकासशील देशों में उपलब्ध और अभिज्ञात संभरणों के अवसर के प्रकाश में ऋणी समझता है कि आयात केवल नीदरलैंड्स से ही प्रभावी किए जाने चाहिए तो खरीदार, केवल नीदरलैंड्स के लिए बोली को सीमित रखने के लिए या नीदरलैंड्स और साथ ही साथ पात्र स्रोत देशों से बोलियां प्राप्त करने के लिए विकल्प रखेगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31-33 के साथ मार्गदर्शन का अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 34-38 के साथ अनुच्छेद 30 लागू है।

7. ये मार्गदर्शन और साथ ही साथ उद्गम के नियम और पात्र स्रोत देशों की सूची नीदरलैंड्स की सरकार के संशोधनाधीन हैं।

(ख) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए क्रिया विधि

8. बोली के लिए आमंत्रण जारी करते समय ऋणी (या ऋणी की ओर से खरीददार) निम्नलिखित दो प्रकाशनों में से कम से कम एक में बोली का विज्ञापन देगा :—

भारतीय व्यापार पत्रिका

भारतीय निर्यात सेवा बुलेटिन

आयातक भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय सेवा बुलेटिन में यथा विज्ञापित निविदा नोटिस की तीन प्रतियां भारत स्थित नीदरलैंड्स के राजदूतावास को भेजेगा।

9. प्रतियोगिता को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी अलग-अलग सविधाएँ जिनके लिए जब कभी संभव हो बोलिया आमंत्रित की जाती है वह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बोलियों को आकर्षित कर सके। दूसरी तरफ यह कि यदि तकनीकी और प्रशान्तिनिक दृष्टि से एक परियोजना को विशेष प्रकार की सविधाओं में विभाजित करना संभव हो और इस प्रकार के विभाजन से श्रुणी की लाभ हो और/या इससे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली और भी विशाल बन जाए, तो परियोजना विभाजित की जानी चाहिए। अभियान्त्रिक उपकरण और निर्माण कार्य (सामान्यतः 'टर्न की कान्ट्रैक्ट' के रूप में जाने जाते हैं) के लिए एकल सविधाओं की बाछा की जा सकती है यदि वे उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक सुविधाओं के भीतर श्रुणी देश के लिए सम्पूर्ण लाभ अर्पण करती है।

10. विशेषरूप से मिविल कार्यों की सविधाओं के लिए औपचारिक पूर्व योग्यता की बाछा की जा सकती है। यदि पूर्वयोग्यता की बाछा की जाती है तो यह इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः सतोष-जनक निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए (1) इसी प्रकार के कार्य में फार्म का पूर्व अनुभव (2) कार्मिक, उपकरण एवं सयंत्रक सखध में इसकी क्षमता और (3) इसकी आर्थिक स्थिति और सक्षमता। पूर्वयोग्यता क्रियाविधि का विज्ञापन कडिका 8 में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा। पूर्वयोग्यता के लिए विचार किए जाने वाले हल्छुक ठेकेदारों के लिए सक्षिप्त विशिष्टिकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जब पूर्वयोग्यता लागू हो जाती है तो वे सभी फर्म जो पूर्वयोग्यता की शर्तों को पूरा करती हैं बोली के लिए अनुमत होंगी।

11. बोली के दस्तावेज उन भाषाओं में से किसी एक भाषा में तैयार किए जाएंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-व्यवहार में साधारणतः प्रयोग की जाती है और जब तक कानूनी तौर पर रोक नहीं लगा दिया जाता इस बात का उल्लेख करेगी उक्त भाषा दस्तावेज के मूल पाठ में लागू रहेगी।

12. विशिष्टिकरण में किए जाने वाले कार्य, सभरण किए जाने वाले माल और सेवाओं तथा सुपुर्दगी या सस्थापन की जगह के लिए जहाँ तक संभव हो साफ और मुस्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इाइन विशिष्टिकरण के विषय के अनुकूल होंगी, जहाँ वे अनुकूल नहीं होंगी तो उसका मूल पाठ लागू होगा। विशिष्टिकरण में मूल्यांकन के मिद्धात और बोलियों की तुलना में का उल्लेख करेगा जो द्रव्य लेख में लिए जाएंगे जब मूल्यांकन किए जाते हैं और बोलियों की तुलना की जाती है। विशिष्टिकरण में इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए जिससे कि स्वतन्त्र और सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की स्वीकृति एवं प्रोत्साहन मिल सके।

किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी स्पष्टीकरण या गलतियों में सुधार और विशिष्टिकरणों में परिवर्तन तथा बोली के लिए आमंत्रण से उनको शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया था।

13. यदि इस प्रकार के राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल होने आवश्यक हो, तो विशिष्टिकरण में यह बताया जाएगा कि वे माल जो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों का पूरा करते हैं जिनमें उल्लिखित मानकों के अलावा उसके बराबर या अच्छी किस्म की माग की गई है। तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे।

14. यदि विशेष फालतू पुर्जों की अपेक्षा की जाती है या यह निश्चय किया जाता है कि कुछ अनिवार्य गुणकर्ता को बनाए रखने के लिए एक विशेष मात्रा के मानकीकरण की आवश्यकता है तो

विशिष्टिकरण निष्पादन और क्षमता पर आधारित होंगे और उनमें केवल तभी पजीकृत मार्का नाम, सूची सख्या या विशेष चिनिर्माता के उत्पाद निर्धारित होने चाहिए। अन्तिम मामले में विशिष्टिकरण में विकल्प की उन सामान के प्रस्तावों की लिए स्वीकृति दी जाएगी जिसमें मिलती जुलती विशिष्टताएँ हैं और जिनका निष्पादन और क्वालिटी कम से कम उन विशिष्टिकृत स्तर के बराबर है।

15. बोली के लिए निमंत्रण में पात्र स्रोत देशों का उल्लेख किया जाएगा और उनमें उद्गम के लागू नियमों को बताया जाएगा।

16. कोटेशन की जाच पात्र स्रोत देशों के सभरणों के बीच पूर्णतः बराबरी की शर्तों के आधार पर की जाएगी (इसमें माल और उपकरण के लिए सीमा शुल्क टैरिफ और अन्य करों और इसी प्रकार के प्रभावी करों की निशुल्क कीमतों पर कोटेशन के मूल्यांकन भी शामिल हैं) लेकिन, श्रुणी देश माल और सेवाओं के सभरण के लिए बोली के मूल्यांकन और मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमतें शामिल नहीं हैं, स्थानीय माल और सेवाओं के लिए और उन अन्य पात्र स्रोत देशों के उत्पादों के लिए वरीयता की गुंजाइश देने के लिए जो गृह में हैं या जो इस प्रकार के वर्ग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए, अन्य पात्र स्रोत देशों में उत्पन्न होने वाले माल और सेवाओं के लिए प्राधिकृत हैं। वरीयता की यह गुंजाइश/न्यूनतम मूल्यांकित विदेशी बोलियों के लागत बीमा भाड़ा पर 15 प्रतिशत या बोलीकार के देश में सीमा-शुल्क करों के वर्तमान स्तर, इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

17. विशेष मामलों में, श्रुणी, नीदरलैंड्स सरकार और श्रुणी देश के बीच आपसी परामर्श करके, कडिका 16 में उल्लिखित वरीयता की गुंजाइश के अतिरिक्त गृह के अनुकूल स्थानीय और क्षेत्रीय चिनिर्माण-कर्ताओं के लिए वरीयता की सीमित गुंजाइश को प्रदान कर सकता है। वरीयता की स्तर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय वर्ग या क्षेत्रीय स्वास्थ्य और प्रबंध तथा श्रुणी देश के पजीकरण या इन चिनिर्माणकर्ता फर्मों के क्षेत्रीय आर्थिक वर्ग जैसे तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

18. बोली दस्तावेज में कोई भी सहमत वरीयताएँ प्रदर्शित की जाएगी और बोली के मूल्यांकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हें लागू किया जाएगा उसे भी बताया जाएगा।

19. बोलीकारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें वे अपनी बोलिया प्रस्तुत करेंगे।

20. बोलियों को प्राप्त करने और बोली का खोलन के लिए अन्तिम तारीख, समय और स्थान बोली के लिए नियंत्रणों में घोषित किया जाएगा और सभी बोलियाँ निर्धारित समय पर जनता के सामने खोली जाएंगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियाँ को बिना खोले ही लौटा दिया जाएगा। बोलीकार का नाम, प्रत्येक बोली या आवेदित या स्वीकृत यदि कोई विकल्पी बोली हो तो उसका कुल मूल्य ऊँची आवाज में पढ़ा जाएगा और उनका रिकार्ड रख लिया जाएगा।

21. किसी बोलीकार को बोलिया खोलने के बाद अपनी बोली में परिवर्तन करने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी। केवल बोली के मूल में परिवर्तन स भिन्न स्पष्टीकरण स्वीकार किए जा सकते हैं। श्रुणी किसी भी बोलीकार को अपनी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है। किन्तु किसी भी बोलीकार को बोली के मूल में या अपनी बोली के मूल में परिवर्तन के लिए नहीं कहा जा सकता।

22. कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर जाच से सम्बद्ध कोई भी सूचना स्पष्टीकरण और बोली के मूल्यांकन तथा परिनिर्णय से सम्बद्ध मिफारिश, बोलियों के सार्थजनिक रूप से खुलने के बाद सफल बोलीकार

के लिए संविदा के परिनिर्णय को घोषित करने से पूर्व किसी भी उस व्यक्ति को नहीं भेजी जाएगी जो श्रृणी की ओर से या नीदरलैंड्स की सरकार की ओर से इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से सम्बद्ध नहीं है।

23. बोलियों के खुलने के बाद खरीददार इस बात का सुनिश्चय करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या बोलियों के परिकल्पन में महत्वपूर्ण गलतियाँ की गई हैं, क्या बोलियाँ बोली दस्तावेज की आवश्यकताओं के पूर्णतया अनुकूल तो हैं, क्या अपेक्षित गारन्टियों और जमानतों की व्यवस्था की गई है, क्या दस्तावेज सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिए गए हैं और क्या दस्तावेज अन्यथा रूप से सही हैं, यदि कोई बोली वास्तविक रूप से विशिष्टीकरण के अनुकूल नहीं होती है या उसमें भ्रष्टीकृत भाग हैं या अन्यथा रूप से वास्तव में बोली दस्तावेज के अनुकूल नहीं हो तो उसे भ्रष्टीकार कर दिया जाएगा।

तब आर्थिक दृष्टि से विस्तृत निर्धारण के साथ तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा जिस से प्रत्येक अनुकूल बोली का मूल्यांकन किया जा सके और बोलियों को मिलाने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

24. बोली के लिए निमज्जन में बताया जाए कि खरीददार को ऐसी सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार है जब कोई बोली विशिष्टीकरण के प्रयोजन के अनुकूल नहीं है और जब प्रतियोगिता के भ्रम का प्रमाण मिलता है या निम्न बोलियाँ उन पूर्व अनुमानित धराशायी की कीमत से अधिक होती हैं जो इस तरह की कार्रवाई को उचित बनाने के लिए पर्याप्त है। यदि सभी बोलियाँ रद्द कर दी जाती हैं तो श्रृणी नीदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ऐसी स्थितियों के कारणों को और निम्न बोली और अनुमानित कीमत में अन्तर के कारणों को जानने के लिए एक या एक से अधिक न्यूनतम बोलीकारों के साथ सोदा कर सकता है विशिष्टीकरण में परिवर्तन को परावर्तित करने वाली तय की गई दो सविदाएँ जिन से परियोजना की अनुमानित कीमत में कमी हो सकती है उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन परियोजना के स्वरूप को वास्तविक रूप से नहीं बदलते। जहाँ परिवर्तन वास्तविक है वहाँ पुनः बोली उचित हो सकती है। इसे हर बार नीदरलैंड्स की सरकार द्वारा अनुमोदित करना होगा।

25. बोलियों के मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में बताए गए नियम और शर्तों के अनुसार और बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से पूर्व इस से सम्बद्ध किसी भी प्राशोधन के अनुसार होने चाहिए। न्यूनतम मूल्यांकित बोली की स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ कीमत से भिन्न तथ्यों जैसे निर्माण कार्य या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय उपकरण की कार्य क्षमता और विषयसनीयता, इस की सुपुर्गों को समय और सेवा और फालतु पुर्जों की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा और जहाँ तक सम्भव हो सकेगा मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा वे मुद्रा जिन में बोली कीमत का भुगतान किया जाएगा उन का मूल्यांकन केवल बोली के मिलान के प्रयोजनार्थ सरकारी साधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा की दरों के आधार पर और बोली की अन्तिम तारीख को इस प्रकार के सोदे के लिए लागू दरों के आधार पर किया जाएगा।

26. संविदा का परिनिर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा जिस की बोली पूर्व की कड़िकाओं में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्यांकित बोली निश्चित की गई हो।

27. अनुरोध करने पर नीदरलैंड्स की सरकार को अधिप्राप्ति के सभी पहलुओं पर अपनी टिप्पणी और सिफारिश प्रदान करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। संविदा का परिनिर्णय होने के बाद नीदरलैंड्स की सरकार को श्रृणी के उपयोग के मूल्यांकन के लिए सभी सम्बद्ध दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी (उनकी प्रतियों सहित) प्रदान की जाएगी।

(ग) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली से निम्न अधिप्राप्ति की क्रिया विधि

28. कड़िका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में कड़िका 31-39 में उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कड़िका 6 के अनुसार लागू हो सकते हैं।

मानकीकरण

29. जहाँ खरीददार के पास अपने उपकरण के उचित मानकीकरण को बनाए रखने के लिए विषयसनीय कारण हैं।

योग्य संभरकों की सीमित संख्या

30. उन मामलों में जहाँ विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण योग्य संभरकों की संख्या सीमित है और खरीददार की मार्किट जानकारी ऐसी है कि उस से आशा की जा सकती है कि योग्य संभरकों के बारे में जाने।

31 औपचारिक खुलिवा अन्तर्राष्ट्रीय बोली

सामान्य खुलिवा अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत खरीददार उन सीमित संख्या के (पूर्व) योग्य संभरकों से बोलियों आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत है जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य समझे जाने हैं।

ऐसे मामलों में श्रृणी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी संभावित योग्य संभरक को छोड़ ही दिया गया है। अब और जैसे वे वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार, से पात्र स्रोत देशों के संभावित संभरकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी जिस से कि वे उचित आधार पर भाग लेने में समर्थ हो सके।

32. संभरकों का चुनाव केवल उन की योग्यताओं के आधार पर किया जाता है और जहाँ तक सम्भव हो वे नीदरलैंड्स सहित अनेक पात्र स्रोत देशों से चुने जाने हैं।

33. कड़िका 8 में उल्लिखित से भिन्न औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली को सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण रूप से लागू की जानी हैं।

34. औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति

यदि औपचारिक प्रतियोगिता बोली की क्रियाविधियों के माध्यम से अधिप्राप्ति नहीं होती है तो यह संतोषजनक वाणिज्यिक नीति के अनुसार और पात्र स्रोत देशों के बीच बिना किसी को भेदभाव के प्राप्त करनी चाहिए।

35. प्रायातक को अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति के इच्छित उपयोग का विस्तृत और समायोजित प्रकार करना चाहिए। पात्र स्रोत देशों के संभरक जब भी ऐसे सूचना मांगेंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार उन को न्यायोचित आधार पर भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक सूचना देगी।

36. दरों और प्रस्तावों की तैयारी के लिए अनुमित समय शामिल की गई सविदाओं के स्वरूप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। साधन सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को अनुमति देने के लिए समय और वितरण दोनों की अनुसूचियाँ पर्याप्त लम्बी होंगी।

37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैंड्स सरकार मूल्यभाव कैसे प्राप्त किए गए थे इस के पूर्ण व्योरे सहित विक्रय किए गए माल, शामिल किए गए संभरकों और प्राप्त मूल्य दरों के सङ्ग्रह में विक्रेताओं से सूचना माग सकती है।

38. औपचारिक स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण संभव सीमा तक यथोचित मार्ग दर्शन लाभ होना चाहिए।

39. एक मात्र संभरक

निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में क्रेता को किमी एकमात्र संभरक से सीधे ही क्रय करने की अनुमति दी जाती है :

- (1) एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह पंजीकृत व्यापार चिह्नित नाम वाली पुण्यवस्तु शामिल होती है जो आयातक द्वारा पुनः बिक्री के लिए हो, जिस के लिए आयातक संभरक का नियमित प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक या विनिर्माता हो।
- (2) एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह पुण्यवस्तु शामिल है जो विनिर्माण समाधान या संयोजन और उस अन्तिम उत्पाद के पुनः बिक्रय के लिए अधिप्राप्ति को जानी है जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित रूप से प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक विनिर्माता हो।
- (3) पुर्जों की विनियमशीलता का सुनिश्चय करने के लिए या विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण अधिप्राप्ति केवल एक ही स्रोत से पूर्ण की जा सकती है।
- (4) क्रेता वह विनिर्माता हो जिसका साज सामान और कच्ची सामग्री का फार्मुला कच्ची सामग्री की उस विशेष किस्म के जिस सर्वोत्तम उपयोग के लिए बनाया गया हो जो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त की जा सकती हो।
- (5) यदि संभरक औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अधीन मूल रूप से प्राप्त की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना या दुहराना चाहता हो बशर्त कि संभरक अधिप्राप्ति मूल अधिप्राप्ति के मुकाबले में छोटी हो, केवल कुछ ही अवसरों पर पूर्ण की जाती हो और जब मूल अधिप्राप्ति से संबंधित निर्माण कार्य उस समय भी चल रहा हो या मूल अधिप्राप्ति पूर्ण करने के थोड़े समय बाद पूर्ण की जाती हो।
- (6) यदि सौदे का मूल्य डी० एफ० एन० 1.25 मिलियन से कम हो।

(घ) परामर्शकों के उपयोग के लिए मार्गदर्शन

40. परामर्श देने वाली नियोजित संस्थाएं इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए कि उन का परामर्श डिजाइन, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक पक्षपात से मुक्त हों और वे प्रतियोगिता के आधार का अनुपालन कर सकती हो। स्थानीय परामर्शदात्री संस्थाओं पर विचार करते समय राष्ट्रीय स्वामित्व का स्तर प्रबंध और कामिक तथा पंजीकरण जैसी बातों पर उचित ध्यान देना चाहिए।

41. परामर्शदात्री संस्थाओं के चयन के लिए औपचारिक प्रतियोगिता बोली क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, चयन की प्रक्रिया में श्रृणी को उन प्रत्याशित संस्थाओं को यथोचित सल्लाह पर विचार करना चाहिए जिनसे कई पात्र स्रोत देशों से समर्थ और स्वतंत्र सेवाएं अर्पित करने की आशा की जा सकती हो। यह सूची निम्नलिखित बोली को ध्यान में रखते हुए पूर्ण गुणों पर आधारित होगी—

- (1) कार्य की समान किस्मों में संस्था का पहला अनुभव।
- (2) कर्मचारियों, साज-सामान और संयंत्र के संबंध में इस संस्था की क्षमता।
- (3) इसकी वित्तीय स्थिति और सबसत्ता।

यह बांछनीय है कि प्रस्तावों के लिए निर्माण भेजने से पहले श्रृणी प्रत्याशित संस्थाओं की सूची नीदरलैंड्स सरकार को प्रस्तुत करे। नीदरलैंड्स सरकार को परामर्शों के चयन को अस्वीकार करने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त वह नीदरलैंड्स में परामर्शदात्री क्षेत्र में अपनी जानकारी के आधार पर यह सुझाव दे सकती है कि इस सूची में वृद्धि की जाती है।

(ङ) शिकायते

42. खरीददार बोली के संबंध में बोलियों को प्रस्तुत करने और सविदाओं के प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली शिकायतों को सुनने और उनकी जांच करने की व्यवस्था करेगा।

43. औपचारिक बोली क्रियाविधि के अस्तर्गत की गई खरीद के मामले में बोली समाप्त होने की तिथि से पूर्व किए गए प्रतिबन्ध एवं वस्तु विशिष्टिकरण या आमंत्रण की प्रतिबन्ध अवधि के सम्बन्ध में विषयवस्तु की किसी भी शिकायत का समाधान बोलियों के खुलने से पूर्व ही किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो नीदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही उचित अवधि के लिए बोली के लिए अन्तिम तिथि स्थगित की जाए।

44. जब शिकायत सम्बद्ध संभरकों में से किसी एक के द्वारा की गई है तो शिकायत के विषय से संबंधित और इस पर की गई कार्रवाई से संबंधित वस्तावेज नीदरलैंड्स सरकार द्वारा और श्रृणी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होंगे।

परिशिष्ट 'क'

विकासशील देशों की संयुक्त द्विपक्षीय श्रृणु के लिए पात्र स्रोत देशों की सूची

क. नीदरलैंड्स
ख. अफ्रीका
उत्तरी सहारा
अल्जीरिया
लीबिया अरब गणराज्य
मोरक्को
तुनीसिया
मिस्र
बहरीन सहारा
बोटस्वाना
बुरुण्डि
कैमरून
केप वर्दी द्वीप समूह
मध्य अफ्रीका गणराज्य
चाड
कोमोरो द्वीप समूह
कांगो (जनवादी गणतंत्र)
जैरी गणराज्य
एडोमी
इथोपिया
गैबोन
जम्बिया
घाना
गिनी
गिनी बिसाऊ
आइवोरी कास्ट
कीनिया
लिशोथो
लाइबीरिया
मालागासी गणराज्य
मलायी
माली
मारिटेनिया

मारिशस
नाइजर
नाइजेरिया
रियूनियन
रूआन्डा
सेनेगल
सैबियेज
सिबेरा लेओन
सोमालिया
टर्, फार और इमास
सेंट हेलेन और डेनेडेमिज
सूडान
स्वाजीलैंड
तन्जानिया
टोगो
उगान्डा
अपर ओल्डा
जाम्बिया
अमेरिका
उत्तरी एवं मध्य
ब्रह्मास
बारबेडोस
बरमुदा
कोस्टा रिकका
क्यूबा
जोमीनिसन (गणराज्य)
ई। सैलबोडोर
गुडेलोप
गुआटेमाला
हैटी
होनडुराज (न)
होन्डुरस (बी० आर०)
जमैका
माटिनिक
मैक्सिको
नीदरलैंड्स अन्टलीज
निकारागुआ
पनामा
सेंट पेरी/एट मिल्युलोन
एट टोबागो
वेस्ट इंडीज (बी० आर०)
दक्षिण
अर्जेटोना
ब्रीनीडाड इट टोबागो
बोलीविया
ब्राजिल
चिली
कोलम्बिया
इक्वाडोर
काकलेड द्वीप समूह
गुयाना
गिनी (एफ० आर०)
पारागुवे
पीरू
सूरीनाम
युरुखे
वीनेजुएला

एशिया
मध्य-पूर्व
बेहरिन
ईरान
ईराक
इजराइल
जोर्डन
कुवैत
लेबनान
ओमान
कतार
सऊदी अरब
यमन (जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य)
सीरिया (अरब गणराज्य)
यमन (अरब गणराज्य)
दक्षिणी
अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
मालदिव
नेपाल
श्री लंका
पाकिस्तान
सुदूर पूर्व
ब्रुनी
खैमर गणराज्य]
हंग-कांग
इंडोनेशिया
कोरिया (गणराज्य)
कोरिया (जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य)
लाओस
मैको
मलेशिया
फिलीपिन्स
सिंगापुर
थाईलैंड
सिमोर
वियतनाम (गणराज्य)
वियतनाम (प्रजातन्त्र गणराज्य)
सामुद्रिक
फिजी
मिलबस्टे एवं एलिस द्वीपसमूह
मैरूच पोलिनेशिया
न्यू कैलेडोनिया
न्यू हेबराइडज (बी० आर० एण्ड एक० आर०)
पेसेफिक द्वीपसमूह (यू० एस०)
पैपो न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह
टोंगा
वालिस और फुतुना
पश्चिमी सामोआ
यूरोप
टर्की
पुर्तगाल

परिशिष्ट 'ख'

उद्गम के नियम

1. उद्गम के इन नियमों की विषयाधीन मर्दे स्रोत देशों में उत्पादित माल और सेवाएं होगी।
2. माल के मामले में नीदरलैंड्स के उद्गम का निर्धारण इस क्षेत्र में उन विधान के अधीन होगा जोकि यूरोपीय समुदाय में लागू है।
3. पैरा 2 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण नीदरलैंड्स के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाण-पत्र के साथ भेजा जाएगा।
4. माल के मामले में, विकासशील देशों के उद्गम का निर्धारण उस उद्गम नियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली की रूप-रेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हो।
5. पैरा 4 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण विकासशील देशों के प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रपत्र 'ए' (जो अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया जाता है) उद्गम के प्रमाण-पत्र द्वारा भेजा जाएगा।
6. सेवाओं के मामले में (अर्थात् मार्ग-दर्शन का पैरा 1) उद्गम का निर्धारण नीदरलैंड्स सरकार और ऋण लेने वाले देशों के बीच आपसी परामर्श के तदर्थ आधार पर किया जाएगा।
7. ऐसे मामलों में जहां उद्गम के नियमों से वास्तव में कोई समस्या पैदा हो जाती है या ऋण लेने वाले देश को गम्भीर आर्थिक घाटा हो जाता है (उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावनी संभरणों पर जबरदस्त प्रतिबन्ध) तो इन नियमों से छुटकारा पाने को स्वोच्छति दी जा सकती है किन्तु यह केवल नीदरलैंड्स सरकार एवं ऋण लेने वाले देश के बीच आपसी परामर्श के बाद दी जा सकती है।

अनुबन्ध-II

- (ए) भारतीय आयातक का नाम और पता और/या जहां आवश्यक हो परियोजना अधिकारी का नाम और पता
- (बी) संभरक का नाम और पता। यदि संभरक पात्र स्रोत देश के हैं तो उस मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी भेजी जानी चाहिए:—
 - (i) राष्ट्रिकता
 - (ii) पात्र स्रोत देशों के द्वारा रखे गए शेषों का प्रतिशत
- (सी) (i) आयात लाइसेंस की संख्या और विनांक
- (ii) मूल्य
- (डी) (i) नीदरलैंड्स/पात्र स्रोत देश में संभरक के बैंक का नाम और पता
 - * (ii) भारत में आयातक का बैंक (वह यह बैंक होगा जिसने बैंक गारंटी दी है)
 - ** (iii) भारत में आयातक का बैंक जो कि आयातक के लिए पोतलवान वस्तावेज रिहा करने से पहले भारत के लेखे में रुपया जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ई) डच गिल्डरस में या पात्र स्रोत देश की मुद्रा में संविदा आदेश का मूल्य
- (एफ) अधिप्राप्ति की विधि, क्या यह सीधे खरीद पर आधारित है या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय बोली पर या चयन फार्मुला अन्तर्राष्ट्रीय

*निजी क्षेत्र के लिए।

**सार्वजनिक क्षेत्र के लिए।

बोली के आधार पर जिस मामले में यह संकेत किया जाना चाहिए कि क्या संविदा यदि कोई हो तो उन कारणों के साथ न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई है

- (जी) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण
- (एच) माल का उद्गम—यदि कोई हो तो गैर-पात्र स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत
- (आई) सुपुर्वाही को पूरा करने की संभावित स्थिति
- (जे) भुगतान की शर्त और संभावित वह तिथि जिस दिन इस संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी
- (के) पोत-लवान वस्तावेजों की विस्तृत सूची, जैसे अवतरण बिल, बीजक, उद्गम प्रमाण-पत्र आदि जिसे विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूंजी निवेश बैंक या पात्र स्रोत देश में संभरकों के बैंक को चाहिए कि संभरकों को भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों के साथ मांग करें
- (एल) यदि संविदा में शामिल है तो भारतीय एजेंट का वह कमीशन (छोका-छोका धन-राशि संकेतित की जानी है) जिसे प्राधिकार-पत्र जारी करने समय संविदा के मूल्य में से घटाना पड़ेगा, इस प्रकार का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेंटों को रुपये में आयातकों द्वारा सीधे ही किया जाएगा
- (एम) वह मूल्य जिसके लिए प्राधिकार-पत्र अपेक्षित है
- (एन) बक गारंटी की संख्या, विनांक और मूल्य इसमें उस अवधि का भी संकेत हो जिन तक यह वैध है
- (ओ) यदि कोई हो, तो विशेष अनुदेश।

अनुबन्ध-III

डच क्रेडिट

संविदा प्रमाण-पत्र

संविदा के द्यौरे

- भारतीय आयात लाइसेंस की संख्या
 1. संविदा की संख्या एवं दिनांक
 2. खरीददार को संभरित किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के द्यौरे
 (यदि बहुत सी मर्दों का संभरण किया जाना है तो प्रमाण-पत्र में विस्तृत सूची लगाई जानी चाहिए)
 3. खरीददार को चुकाई जाने योग्य कुल संविदा कीमत (लागत बीमा भाड़ा लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का संकेत कीजिए)
 डी०एफ०आई०
 यदि माल का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खंडों को पूर्ण अवश्य की जानी चाहिए:—
 4. नीदरलैंड्स में उत्पन्न नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत किन्तु वह उस माल की खरीद संभरक द्वारा सीधे ही विदेशों से की गई है अर्थात् विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित या संघटकों का प्रतिशत—
 (क) प्रतिशत जहाज वर निःशुल्क मूल्य
 (ख) मर्दों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण

5. यदि सेवाओं का संभरण किया जाता है तो निम्नलिखित खंड की भी पूर्ति की जानी चाहिए—
6. किए जाने वाले किसी काम का अनुमानित मूल्य या
- (क) आपकी फर्म (साइट इंजीनियर प्रभारत आदि)
- (ख) म्यानीय संभरक
- द्वारा खरीवदार के देश में निष्पावित की गई सेवा का उल्लेख कीजिए।
7. उपर्युक्त कड़िका 4 और 5 के संबंध में यथा आवश्यक अर्हक दिष्पणियां
8. मैं घोषणा करता हूं कि मैं संभरक द्वारा या नीचे उल्लिखित द्वारा नीदरलैंड्स में नियुक्त किया गया हूं और इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है। एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उपर्युक्त कड़िका 4 और 5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं से भिन्न और किसी भी ऐसे माल या सेवा का इस सविदा के निष्पावन में संभरक द्वारा संभरण नहीं किया जाएगा जो नीदरलैंड्स मूल के नहीं है।

हस्ताक्षरित

प्रोहवा

संभरक का नाम और पता

दिनांक

नीदरलैंड्स वाणिज्यिक मंडल

अनुबन्ध—IV

संख्या एक/4 () डब्ल्यूई-3/

भारत सरकार

विस्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

विकासशील देशों के लिए दि नीदरलैंड्स इन्वेस्टमेंट बैंक,

दि हेग,

नीदरलैंड्स।

..... लाख नीदरलैंड्स गिल्डर्स के ऋण के लिए समझौता

प्रिय महोदय गार्,

प्राधिकार-पत्र संख्या

भारत को आपके बैंक द्वारा दिए गए ऋण में से भारत के सर्वश्री

..... और हालैंड के

सर्वश्री

के बीच

वित्त युक्त किए जाने वाले सौदे के सम्बन्ध में अपने आज के प्रावेदनपत्र के

प्रसंग में हम एतद्द्वारा निवेदन करते हैं और उपर्युक्त सविदा की शर्तों

के अनुसार एन० एक० एल०

माल की धनराशि हालैंड में संभरक को चुकाने के लिए आपको बिना शर्त

और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि

इस संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक, पोतलवान और अन्य वस्तुविज

..... को सीधे भेज दिए जाएं।

(आयातक के बैंक)

संभरकों को विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड्स पूजी निवेश बैंक को उस जिले के जिसमें निर्यातक स्थित हैं, नीदरलैंड व्यापार मंडल द्वारा पुष्टि किए गए/प्रमाणित किए गए प्रमाण-पत्र की इस सम्बन्ध में दो प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्राधिकार-पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल नीदरलैंड्स मूल के है।

कृपया नामे डालने की सूचना भारत सरकार, विस्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आर्थिक सहायता लेखा शाखा) जीवन द्वीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को अप्रसारित करें। यह, प्राधिकार-पत्र तक वैध रहेगा।

हुते भारत का राष्ट्रपति

()

प्रतिलिपि

(आयातक के बैंक को)

आयातक को मूल वस्तुविज रिहा करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई०टी०सी० (पी०एन०)/76, दिनांक 17-1-1976 और ऐसी ही सार्वजनिक सूचनाएं जो समय-समय पर जारी की जाएं उनमें निर्धारित तरीके में मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर पर गणना किए जाने वाले समुल्य रूपए और उस पर संभरकों को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखों में धनराशि जमा कराने की तिथि तक सार्वजनिक सूचना सं० 46 आई०टी०सी० (पी०एन०)/76, दिनांक 16-6-76 में निर्धारित दरों पर व्याज जमा कर दिया गया है।

अनुबन्ध—V

संख्या एक-4 () डब्ल्यूई-3/

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषय:—सामान्य प्रयोजन डच क्रेडिट के अन्तर्गत की गई सविदा-प्रतिपूर्ति

प्रिय महोदय,

सर्वश्री

..... ने

(भारतीय आयातक)

..... रूपए (

..... रूपए) के मूल्य के लिए सामान्य प्रयोजन

डच क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए साइसेस संख्या

..... दिनांक

..... के मद्दे लागत बीमा भाड़ा/

लागत एवं भाड़े को

(.....) धनराशि के लिए

..... के सम्भरण के लिए सर्वश्री

..... (विदेशी संभरक)

..... के साथ

सविदा की है। सविदा की एक प्रति संलग्न है।

2. ऊपर के

..... रूपए की धनराशि में से

भारतीय एजेंट के कमिशन के रूप में

..... धनराशि

भारतीय मुद्रा में भुदा की जानी है। विदेशी मुद्रा में सम्भरक की भुदा

की जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विदेशी मुद्रा स्रोतों में से अर्धयुक्त

की जाएगी जिसको बाद में

..... धनराशि तक डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट में से प्रति पूर्ति की जानी है।

3 आपको उनके बैंकरो अर्थात् सर्वश्री के माध्यम से सर्वश्री

के नाम से इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर और बैंक आयात लाइसेंस के मद्दे सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए एक मात्र पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

4 मुद्रा विनिमय नियंत्रण मैन्युअल के खण्ड 7 पैरा 10 के अनुसार, आपको यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि साख-पत्र की समाप्ति तिथि सम्बन्धित आयात लाइसेंस में क्या उल्लिखित पोतलवान के लिए अन्तिम तिथि के पैतालीस (45) दिनों से ज्यादा नहीं है।

5 साख पत्र में यह भी प्रावधान होगा कि सर्वश्री (विदेशी सभरक) अपरक्राम्य पोतलवान वस्तावेजों का एक सेट और बीजक की दो प्रतियां जो रुच सभरक द्वारा इस प्रमाण-पत्र द्वारा पृष्ठांकित हो कि भुगतान उनके द्वारा प्राप्त हो गया है, सीधे ही सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजेगा।

जिस जिला में नियमित है उस जिले के नीदरलैंड्स व्यापार मंडल के साख-पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल के नीदरलैंड्स मूल के होने के संबंध में जारी किए गए/प्रमाणित किए गए/इस साख पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल उद्गम के सम्बन्ध में उचित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां भी वे प्राप्त करेंगे और नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेंगे।

6 आपको, यदि कोई हो तो बैंक खर्चों को छोड़कर बीजक/माल के पोतलवान के मद्दे आप के, द्वारा सर्वश्री को किए गए प्रेषण का एक प्रमाण-पत्र भी सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजना होगा।

7 कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

सविदा की प्रति के साथ प्रति इनको प्रेषित —

भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग, बम्बई-1

2 प्रति निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित —

(1) (भारतीय आयातक)
मह सुनिश्चय कर लिया जाए कि सर्वश्री
..... (विदेशी बैंकर)
ने नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को, भुगतान बीजक सहितपोत लवान और अन्य दस्तावेजों (अपरक्राम्य) का एक सेट, बीजक की दो प्रतियां जिस पर सभरक द्वारा यह प्रमाण-पत्र विधिवत पृष्ठांकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां भेज दी गई है।

(2) सर्वश्री (विदेशी बैंक)
आप से यह अनुरोध है कि प्रत्येक अदायगी पर भुगतान बीजक सहित पोतलवान और अन्य दस्तावेजों (अपरक्राम्य) का एक सेट बीजक की दो प्रतियां जिस पर सभरक द्वारा यह प्रमाण-

पत्र विधिवत पृष्ठांकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाण पत्र की दो प्रतियां नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेज दी जाए।

(3) नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

अनुबन्ध—6

इस (सामान्य उद्देश्य) क्रेडिट के अन्तर्गत उपयोग के सम्बन्ध में त्रैमासिक रिपोर्ट को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

- 1 आयातक का नाम
- 2 आयात लाइसेंस की सख्या तथा दिनांक
- 3 आयात लाइसेंस का मूल्य
- 4 दिए गए आदेशों का मूल्य
- 5 प्राधिकार पत्र की सख्या और दिनांक
- 6 प्राधिकार पत्र की धनराशि
- 7 प्राधिकार-पत्र की वैधता की तारीख
- 8 त्रैमासिक के दौरान उपयोग की गई धनराशि अल गिल्डर
- 9 उपयोग की गई कुल धनराशि इंच गिल्डर
- 10 सरकारी खाते में जमा की गई कुल धनराशि रुपये
- 11 आगामी त्रैमासिकों के दौरान किया जाने वाला भुगतान
- 12 अभ्यर्पण, यदि कोई हो।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

(Import Trade Control)

New Delhi, the 15th April, 1978

PUBLIC NOTICE

No. 25-JTC(PN)/78/F No IPC/39/13/76—The terms and conditions governing the issuance of import licences financed under the Dutch General Purpose Credits for 1977-78 as given in Appendices I & II to this Public Notice are notified, for information.

APPENDIX I

Conditions for Licensing Private Sector Imports under the Dutch General Purpose Credits

Section I—General

I (1) The Dutch General Purpose Credit for 1977-78 extended by the Netherlands Investeringsbank Voor Onwikkelingslanden N. V. is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and commodities and services incidental thereto which are to be financed under the credit can be imported from Netherlands and all countries enumerated in the list at Appendix-A of the "Guidelines for Procurement of Goods and Services under Bilateral Development Loans by the Netherlands" (Annex-1) which will be the "eligible source countries" under the credit. The terminal date of disbursements in both the credit agreements viz Dfl 120 million and Dfl 54 million would be 31-12-1980

I (2) Components, to the extent of 10 per cent in respect of chemicals and 20% in respect of other imports from non-eligible source countries can, however, be considered for being financed under the credit. Specific requests in this regard, if any, should be made to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), W. E. III Section before finalizing the contract.

I (3) Limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries in excess of the limit indicated in Section I (2) may also be considered for financing under the credit. For this, specific approval of the Government of Netherlands will be necessary.

Section II—Issue of Import Licence

II (1) The import licence will be issued on C. I. F. basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing authority concerned within the validity period of the licence who shall consult the Department of Economic Affairs, (W.E. III Section) in the matter.

II (2) Firm order on CIF/C&F basis must be placed on the overseas suppliers in the Netherlands or the countries mentioned in Annex-I and sent to the Department of Economic Affairs, (W. E. III Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. If firm orders cannot be finalised within the time limit of 4 months the Licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period furnishing justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such request for extension in the ordering period will be considered on the merits of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of import licence, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (W. E. III Section), Ministry of Finance.

II (3) The licence will bear the superscription 'Dutch General Purpose Credit' and indicate the public notice number under which these licensing conditions are issued. The licence code for the first and second suffix will be "S"/"NN". This licence code will be mentioned in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Reserve Bank at the time of rupee deposit.

II (4) As soon as the importer receives the import licence, he should send a report to that effect to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W. E. III Section) along with the following information :

- (i) No. and Date of Import Licence ;
- (ii) Value ;
- (iii) Exchange rate, if any, indicated on Import Licence ;
- (iv) Date by which copies of contract are expected to be furnished to the Department of Economic Affairs.

Section III—Finalisation of Credit

III (1) The minimum value of contract eligible for financing under the credit is Dfl. 25,000.

III (2) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract will be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

III (3) The contract for the import of goods and services from the Netherlands and eligible source countries should be finalised keeping in view the Guidelines for Procurement of Goods and Services as detailed in Annex-I.

III (4) Goods and services should be procured through Formal Open International Bidding except in the following cases :

- (a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ; or
- (b) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million ; or
- (c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the Government of India on another more expedient procedure must be reached before the contract for the supplies could be finalised.

III (5) It would also not be necessary to resort to Formal Open International Bidding in the following type of cases :

- (a) where the purchaser has convincing reasons for maintaining reasonable standardisation of this equipment.
- (b) in cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.
- (c) where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only.

In such cases the procurement formula of paragraphs 31 to 39 of the Guidelines for Procurement of Goods and Services (Annex-I) may be followed.

III (6) The purchaser may purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorised distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer ;
- (iii) in order to assure inter-chargeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source ;
- (iv) the importer is a manufacturers whose equipment and raw material formulae are designed for best utilisation with a specific type of raw material which can only be obtained from one source ;
- (v) the importer wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made ;
- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

III (7) Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, before invitations for preposals are sent out by the Indian firms to the consultant firms, a list of such prospective firms should be furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W. E. III Section). The list in turn will be submitted to the Government of Netherlands who may approve the same or reject the choice of a consultant and may on the basis of their knowledge of the consultancy sector in Netherlands suggest that this list is extended.

III (8) Where the goods are proposed to be procured on the basis of Formal Open International Bidding, the importer should forward three copies of the tender notices as soon as these are advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin to the Embassy of the Netherlands in India, New Delhi under intimation to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W. E. III Section), New Delhi.

III (9) The term "Firm orders" referred to in Section II (2) means purchase order placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

III (10) The CIF/C&F value of the contract should be expressed in Dutch Guilders in case of contracts concluded with the Dutch suppliers and in the respective currency in case of contracts concluded with the suppliers in eligible source countries.

III (11) The contract must provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas suppliers.

III (12) The amount of Indian Agent's Commission included in the value of the contract should be specifically indicated. Any payment on this account should be made in Indian rupees to the Agent in India. No remittance of foreign exchange will be permitted for this purpose. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

III (13) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

III (14) The following provisions should be specifically incorporated in the contract :

(i) 'the contract is subject to the approval of Government of India (if the value of the contract is Dutch Guilders 50,000 or below) and subject to the approval of both the Government of India and the Government of Netherlands (if the value of the contract exceed Dutch Guilders 50,000) ;

(ii) This contract will be governed by the payment procedures laid down under the licensing conditions for the Dutch General Purpose Credit and will become effective after the Government of India's approval to this effect has been received."

(iii) "The goods are of Dutch origin/manufacture" (in case of suppliers in Netherlands)

or

"The goods are of _____ origin/manufacture" (in case of suppliers in eligible source countries).

(iv) For the goods to be imported from Netherlands the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank, a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the supplier is established to the effect that the goods are of Netherlands origin. This certificate can be furnished along with the other shipping documents at the time of receiving payment. A specimen of the certificate is at Annex III.

In the case of supplier in eligible source countries the suppliers will have to produce to the N. I. O./proof of origin of goods in accordance with the Rules of Origin appended to the "Guidelines for Procurement of Goods and Services (Annex I).

III (15) For any customary performance guarantee, where required, the suppliers should be asked to furnish a bank guarantee/warranty.

Section IV—Approval of contract by Government of India/NIO.

IV (1) (a) Immediately after the contract is concluded, the importer should furnish 5 photostat or certified copies of the contract/supply orders accompanied by a photostat copy of the Import Licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE, III Section). In case of contracts concluded with suppliers in eligible source countries 8 copies of the same should be furnished. The importer is also required to furnish the information as per details in Annex II.

(b) In case of contracts concluded with Dutch Suppliers, the importer should furnish a bank guarantee from an approved scheduled bank, in the form prescribed (Annex IV) duly adjudicated by the Collector of Stamps. The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount of contract for which letter of Authority is sought plus interest and other charges. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and Banking as prevailing on the date of issue of import licence.

(2) When the supply contract is based on formal open International bidding or formal selective International bidding, the following information should also be furnished :

- (i) Name of the publication in which tender notice was advertised ;
- (ii) Name of the parties who quoted against the tender enquiry ;
- (iii) The reason for selecting a particular offer indicating whether it was the lowest technically suitable bid.

(3) If the contract documents, the request for issue of letter of authorisation, the import licence and Bank Guarantee are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will forward copies of the contract to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague for approval.

(4) In respect of contracts valued at DG 50,000 or below approval of Dutch authorities is not required. The approval of the Government of India will be communicated to the Indian importers while forwarding the copies of their Contracts/supply orders to the Dutch Authorities. For Contracts of value exceeding DG 50,000, as soon as the approval of the Dutch authorities to the financing of the contract under Dutch Credit is received, the importer will be informed that their contract has become effective.

Section V—Payment to the Suppliers :

(A) Payment to the Suppliers in Netherlands.

V(1) A letter of Authority to the Netherlands Investment Bank for Developing Countries, The Hague (in the form at Annex V) authorising payment to the suppliers against shipping documents will be issued and forwarded along with the copies of contract etc. to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague.

V(2) : The validity of the letter of authority will be determined keeping in view the delivery schedule indicated in the contract. In no case will the letter of authority be made valid beyond the validity of the import licence.

V (3) : Since the payments to the suppliers under the credit are generally made by the Dutch Bank against the production of shipping documents the grace period facility will not be applicable to imports financed under this credit.

V(4) : In case the shipment/payments to the suppliers are not completed within the validity period of the Letter of Authority, the Importer should approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III section) for suitable extension of the Letter of Authority well before the expiry period of the Letter of Authority. Such a request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence, if the period of extension sought for is beyond the validity of the original Import Licence and a letter from the bank extending the validity of Bank Guarantee.

V(5) : If the request for extension in the period of validity of the Letter of Authority is not received within a period of six months from the validity date of the Letter of Authority, the un-utilised balance in the Letter of Authority will be deemed to have been surrendered and the Letter of Authority will stand lapsed automatically.

V(6) : The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the N.I.O. to the concerned importer's bank in India who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the importer has deposited :

- (i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports & Exports' Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17th January, 1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India;
- (ii) interest calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16th June, 1976 on the

amount required to be deposited vide item (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N. V., The Hague, to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

V(7) : It shall be the responsibility of the Indian bank concerned, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

V(8) : The importers should make the requisite rupee deposit only through Authorised Dealers in foreign exchange and also get the Exchange Control Copy of the Licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC (PN)/68 dated the 30th August, 1968. The requisite 'S' Form will be sent by the concerned bank to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(9) : The moneys specified in Section V(6) should be deposited only with the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi for credit to the Central Government Account under the head of account

"K—Deposits and advances—Deposit not bearing interest—843—Civil deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Purchases etc. under Dutch General Purpose Credit 1977-78".

V(10) : The advice of the rupee deposits referred to above, should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi by enclosing original receipted treasury challan in the proforma prescribed under Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974. No. 103-ITC(PN)/76 dt. 12-10-1976. The information in regard to Letter of Authority No. amount of foreign currency for which rupee deposit is made, date of payment to the Dutch supplier, amount of interest and period for which it is calculated should invariably be indicated in the challan form.

RE-IMBURSEMENT PROCEDURE

V(11) : In case of import licences where the value is below Rs. 1 lakh, the importer will have the option to adopt the Re-imbursement Procedure provided no payments are required to be withheld for performance etc. Under this system the Importers will not be required to furnish the Bank Guarantee but their contract will have to indicate that the mode of payment will be by re-imbursement system. The importer will have to open a Letter of Credit on receipt of the approval of their contract by the Government of India. For this purpose a Letter of Authority (Annex VI) to the importer's Bank, as indicated by the importer, authorising opening a Letter of Credit on the suppliers' bank in Netherlands will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section). Payments against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence. Normally all shipments/payments to the suppliers should be completed within a period of 20 months from the date of issue of this said Letter of Authority. In case the shipments/payments to the suppliers are not likely to be completed within the period of twenty months, the Importer should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section) at least a month before the expiry of this stipulated period for the extension of the time limit for completing the shipments/payments to the Suppliers. This request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the un-utilized balances of their contract will be deemed as having been surrendered. The importer will furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Parliament Street, New Delhi-1, within 15 days of the shipment of goods a certificate from his Bank of payment made to the

supplier and also two copies of the Invoice bearing a certificate from the Dutch supplier to the effect that "he received a sum of—Dutch Guilders amounting to 100 per cent of the invoice value or shipment of goods." He will also ensure that two copies of the certificate in regard to origin of Goods referred to in Section III(14) (iv) are furnished by the supplier to the Controller of Aid Accounts and Audit within the stipulated period of 15 days of the shipment of goods. Any omission on the part of the importers to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.&E. may be asked to suspend all import licences in the name of the importer. In case the importer persists in his default his case may be recommended to the C.C.I.&E. for being blacklisted. The importer will in addition be liable to penalties/punishment under the law governing Import Control etc. In case the importer decides to adopt the reimbursement procedure, he should furnish 8 photostat/certified copies of the contract while seeking approval of his contract by Ministry of Finance.

(B) Payment to the suppliers in Eligible Source Countries.

V(12) : A Letter of Authority (in form at Annex VI) to the Importers' Bank, as indicated by the Importer in his application authorising opening of a Letter of Credit on the suppliers' bank in the eligible source country in favour of the supplier will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section). Copies of the contract along with a copy of the said Letter of Authority will be forwarded to the Dutch authorities also through the Embassy of India at the Hague.

V(13) : On receipt of the Letter of Authority mentioned in the preceding paragraphs, the Importer's Bank will open a Letter of Credit in favour of the supplier through his banker within a period of 30 days from the date of issue of the said Letter of Authority and against a valid import licence. An intimation to this effect shall be forwarded to the Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V(14) : After the payment to the supplier is made the supplier's bank shall forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the Invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by the latter.

V(15) : The supplier's bank will also obtain from supplier and furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi a certificate or proof (in duplicate) in regard to the origin of the goods being in accordance with the Rules of origin appended to the Guidelines for Procurement of Goods and Services.

V(16) : The importer should forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate of remittance made by them to the supplier against the invoice/shipment of goods excluding bank charges, if any. This certificate should be obtained from the bank through which the Letter of Credit is opened. The importer should also ensure that one set of non-negotiable shipping documents, two copies of invoice with a certificate duly endorsed thereon in regard to receipt of payment by supplier and certificate of origin referred in Sections V(14) and V(15) are forwarded to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Controller of Aid Accounts & Audit within 15 days of the shipment of goods.

V(17) : Payment against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence.

V(18) : Normally all shipments/payments to the supplier should be completed within a period of 20 months from the date of issue of the Letter of Authority referred to above. In case the shipments/payments to the suppliers are not likely to be completed within the period of 20 months, the Importer

should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section) at least a month before expiry of this limit for completing the shipments/payments to the Suppliers. This request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the unutilised balances of the contract will be deemed as having been surrendered.

V(19) : Any omission on the part of the importer to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.&E. may be asked to suspend all import licences issued in the favour of the importer. In case the importer persists in his default, his case may be recommended to the C.C.I.&E. for being blacklisted. The importer will in addition be liable to penalties/punishments under the law governing Import Control etc.

V(20) : On receipt of the reimbursement documents, Controller of Aid Accounts and Audit, in the Ministry of Finance, will make a request to the Netherlands Investment Bank for reimbursement of the amount paid to the supplier in the eligible source countries. The Netherlands Investment Bank will reimburse the equivalent amount in Netherlands guilders at the rate of exchange prevailing in the Netherlands on the date of such reimbursement.

Section VI : Miscellaneous :

VI(1) : The importer should furnish a quarterly report, as in Annex VII, showing the utilisation status of the licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section).

(2) It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the supplier. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment could be effected to him must be clearly spelt out by the importer in Annex II. If necessary, a provision dealing with settlement of disputes may be included in the contract itself.

(3) The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to import licence and for meeting all obligations under Dutch General Purpose Credit.

(4) Any breach/violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEX I

Guidelines for Procurement of goods and services under Bilateral development loans by the Netherlands

A. General

1. These guidelines govern procurement of goods and services under bilateral loans which form part of the official Netherlands Development Aid Programme. These loans are untied in respect of developing countries. A list of eligible source countries is attached as Appendix A. The recipient country is included in this list. The Netherlands Government may agree, on an individual basis, to limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries, with transportation and insurance costs included.

2. The Netherlands Government must be satisfied that the proceeds from the loans are to be used with due care being given to economy, efficiency, fairness in international competition and non-discrimination among eligible source countries in accordance with procurement procedures set out in these guidelines.

3. Except in the cases mentioned in paragraphs 16 and 17, no practices shall be allowed, which could lead to, or result in a particular supplier or the suppliers of a particular country being favoured.

4. The rules of origin and control to be observed by the borrower in the procurement of goods and services, are attached to these guidelines as Appendix B.

5. Where the borrower does not effect direct procurement, he shall make such arrangements as are necessary to ensure that the purchaser complies with these guidelines.

6.(1) The borrower shall obtain goods and services through formal open international bidding except in the following cases :

- (a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ;
- (b) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million ; or
- (c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the borrower on another more expedient procedure must be reached before suppliers are invited to submit their bids, such agreement to be reached on the basis of all relevant information to be supplied by the borrower through the Royal Netherlands Embassy.

6(2) Where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only, the borrower shall have the option to confine bids to the Netherlands only or obtain bids from the Netherlands as well as the eligible source countries. In such cases article 30 of the Guidelines along with articles 31-33 or article 30 along with articles 34-38 are applicable.

7. These guidelines, together with the Rules of Origin and the list of eligible source countries, are subject to amendment by the Netherlands Government.

B. Procedures for Formal Open International Bidding

8. At the time invitations to bid are issued, the borrower (or the purchaser on the borrower's behalf) shall advertise the bidding in at least one of the following two publications :

Indian Trade Journal

Indian Export Service Bulletin

The importer shall send three copies of the tender notices as advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India.

9. In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited should, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is possible from a technical and administrative point of view to divide a project into contracts of a specialized nature and such division is likely to be advantageous to the borrower and/or to allow broader international competitive bidding the project should be divided. Single contracts for engineering, equipment and construction work (commonly known as "Turn-key contracts") may be desirable if they offer overall advantages to the borrower country within the technical and economic facilities available.

10. Formal prequalification may be desirable, in particular for civil works contracts. If prequalification is used, it should be based entirely upon ability to perform satisfactorily, taking into account (i) the firm's previous experience in similar types of work, (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial position and integrity. Advertisement of the prequalification procedure shall be carried out in accordance with the procedure described in paragraph 8. Condensed specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for prequalification. When prequalification is applied, all firms which fulfil the conditions for prequalification shall be permitted to bid.

11. Bidding documents shall be prepared in one of the languages customarily used in international transactions and shall unless prohibited by law specify that the text of the documents in that language is governing.

12. Specifications shall set forth as clearly and precisely as possible the work to be carried out, the goods and services to be supplied and the place of delivery of installation. Drawings shall be consistent with the text of the specifications; where they are not the text shall govern. The specifications shall state the principles of evaluations and comparison of bids, which will be taken into account when evaluations are made and bids are compared. The specifications shall be worded in such a way as to permit and encourage free and full international competition.

Any additional information, clarification or correction of errors and alterations of specifications and invitations to bid shall be communicated promptly to those who requested the original bidding documents.

13. If national standards are cited to which equipment or material must comply, the specifications shall state that goods meeting other internationally accepted standards, which demand an equal or better quality than the standards, mentioned, will also be accepted.

14. Specifications shall be based on performance and potential and should only prescribe registered brand names, catalogue numbers or products of a particular manufacturer if particular spare parts are required or if it has been decided that a certain amount of standardization is necessary to maintain certain essential quality factors. In the last case the specifications shall permit offers of alternative goods which have similar characteristics and whose performance and quality are of a level at least equal to those specified.

15. Invitations to bid shall list the eligible source countries and shall set out the rules of origin applicable.

16. Quotations shall be examined on the basis of strict equality of conditions among suppliers from eligible source countries (including the evaluation of quotations for material and equipment at prices free of customs tariffs and other duties and taxes of like effect). The borrower country, however, is authorised, in the evaluation and comparison of bids to supply goods and services, excluding transport costs, to extend a margin of preference to local goods and services and to products from other eligible source countries which are members of the same regional economic group, consistent with GATT, or which intend to establish such a group, over goods and services originating in other eligible source countries. This margin of preference shall not exceed 15 per cent on the CIF price of the lowest evaluated foreign bid or the existing level of customs duties of the bidder's country, whichever is the lowest.

17. In special cases, the borrower may, after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrowing country, extend a limited margin of preference to local and regional manufacturers, consistent with GATT, in addition to the margin of preference, mentioned in paragraph 16. In assessing the level of preference, due attention should be given to factors like the degree of national or regional ownership and management and the registration in the borrower country or the regional economic group of these manufacturing firms.

18. Bidding documents shall set out any preferences agreed upon and specify the manner in which they will be applied in the evaluation and comparison of bids.

19. Bidders shall be given inadequate time in which to submit their bids.

20. The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening shall be announced in the invitations to bid and all bids shall be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time shall be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted shall be read aloud and recorded.

21. No bidder shall be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but shall not ask any bidder to change the substance or price of his bid.

22. Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards shall be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures on the side of either the borrower or the Netherlands Government before the announcement of the award of a contract to the successful bidder.

23. After the opening of the bids, the purchaser shall examine the bids in order to ascertain whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the requirements of the bidding documents, whether the required guarantees and sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it shall be rejected. A technical analysis together with a detailed assessment in monetary terms shall then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

24. Invitations to bid may state that the purchaser reserves the right to reject all bids when none are responsive to the intent of the specifications, when there is evidence of lack of competition, or when the low bids exceed the cost previously estimated by an amount sufficient to justify such action. If all bids are rejected, the borrower may, after consultation with the Netherlands Government, enter into negotiations with one or more of the lowest bidders to ascertain the causes for such events and the reasons for the difference between the low bid and the cost estimates. Negotiated contracts reflecting changes in the specifications, leading to economies in the estimated cost of the project, may be acceptable, provided the changes do not substantially alter the nature of the project. Where changes are substantial, rebidding may be appropriate. This shall at all times be approved by the Netherlands Government.

25. Evaluations of bids shall be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents and in any modifications thereto prior to the closing date for submission of bids. For the purpose of determining the lowest evaluated bid, commercial factors other than price, such as the time of completion of construction or other work, the efficiency and reliability of the equipment, the time of its delivery and the availability of service and spare parts, shall also be taken into consideration and shall, to the largest possible extent, be expressed in monetary terms. The currencies in which bid prices would have to be paid shall be valued, for bid comparison purposes only, on the basis of rates of exchange published by an official source and applicable to similar transactions at the closing date of the bidding.

26. The award of a contract shall be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid, taking into account the factors mentioned in the preceding paragraphs.

27. The Netherlands Government shall, upon request, be given adequate opportunity to present its comments and recommendations on all phases of procurement. After the award of contract, the Netherlands Government shall be provided with (copies of) all relevant documents and other information necessary for the evaluation of the use of the loan.

C. Procurement Procedures other than Formal Open International Bidding.

28. In the cases mentioned in paragraphs 29 and 30, the procurement formulae of paragraphs 31—39 may be applied in accordance with paragraph 6.

29. Standardization,

Where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

30. Limited Number of Qualified Suppliers :

In cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.

Formal Selective International Bidding

31. Under formal selective international bidding the purchaser is authorized to invite bids from only a limited number of (pre) qualified suppliers known to be able to meet the special requirements of the procurement in question.

In such cases the borrower should ascertain that no potential qualified suppliers have been excluded. The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all necessary information as and when asked for by potential suppliers of eligible source countries to enable them to participate on an equitable basis.

32. The suppliers are to be selected exclusively on the basis of their qualifications and are, as far as possible, to be chosen from several eligible source countries including the Netherlands.

33. All provisions of formal international bidding, other than those of paragraph 8, are to be fully applied.

Informal International Competitive Procurement

34. If procurement is not through the formal competitive bidding procedures, it should be made in accordance with good commercial practice and without discrimination among eligible source countries.

35. The importer should give wide and timely publicity to the intended use of informal international competitive procurement. The Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all information necessary to permit suppliers of eligible source countries to participate on an equitable basis as and when such information is asked for.

36. The time allowed for the preparation of quotations and offers shall be governed by the nature of the contracts involved. Both lead time and delivery schedules shall be long enough to allow meaningful international competition.

37. The Netherlands Government may require the purchaser in particular cases to supply information on the purchases made, including full details concerning how quotations were obtained, the suppliers who are involved and the quotations received.

38. The guidelines for formal open international bidding should be applied to the fullest possible extent as appropriate.

Single Supplier

39. The purchaser is permitted to purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorised distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer;
- (iii) in order to assure interchangeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source;
- (iv) the purchaser is a manufacturer whose equipment and raw material formulae are designed for best utilization with a specific type of raw material which can only be obtained from one source;
- (v) the purchaser wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international

bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made;

- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

D. Guidelines for the Use of Consultants

40. Consultant firms employed should be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and bid documents prepared by them should be free of national, commercial or industrial bias, can be compiled with on a competitive basis. In considering local consultant firms, due attention should be given to factors like the degree of national ownership, management and personnel and registration.

41. Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, in the process of selection, borrowers should consider a reasonable number of prospective firms, which can be expected to render competent and independent services from several eligible source countries. This list shall be based on prequalification, taking into account.

- (i) the firm's previous experience in similar types of work;
- (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant; and
- (iii) its financial position and integrity.

It is desirable that, before invitations for proposals are sent out, the borrower submits the list of prospective firms to the Netherlands Government. The Netherlands Government reserves the right to reject the choice of a consultant, and may, furthermore, on the basis of her knowledge of the consultancy sector in the Netherlands, suggest that this list is extended.

E Grievances

42. The borrower shall make provision for the hearing and investigation of complaints arising in connection with the invitations to bid, the submission of bids and the award of contracts.

43. In the case of purchases conducted under formal international bidding procedures complaints of any substance, regarding restrictive commodity specification or other restrictive terms of the invitation, made prior to the bid closing date, shall be resolved before the opening of bids. If necessary and only after consultation with the Netherlands Government, the bid closing date may be postponed for an appropriate period.

44. When a complaint has been made by one of the suppliers concerned, the documentation relating to the substance of the complaint and action taken thereon shall be available for examination by the Netherlands Government, as well as by the borrower.

Appendix—A

List of eligible source countries for united bilateral loans to developing countries.

A. Netherlands

B. Africa

North of Sahara

Algeria

Libyan Arab Rep.

Morocco

Tunisia

Egypt

South of Sahara

Botswana

Burundi
 Cameroon
 Cape Verde Islands
 Central African Rep.
 Chad
 Comoro Islands
 Congo (People's Rep. of)
 Zaire Rep.
 Dahomey
 Ethiopia
 Gabon
 Gambia
 Ghana
 Guinea
 Guinea Bissau
 Ivory Coast
 Kenya
 Lesotho
 Liberia
 Malagasy Republic
 Malawi
 Mali
 Mauritania
 Mauritius
 Niger
 Negeria
 Reunion
 Rwanda
 Senegal
 Seychelles
 Sirerra Leone
 Somalia
 Terr. Afars and Issas
 St. Helena and dependencies
 Sudan
 Swaziland
 Tanzania
 Togo
 Uganda
 Upper Volta
 Zambia
 America
North and Central
 Bahamas
 Barbados
 Bermuda
 Costa Rica
 Cuba
 Dominican Republic
 El Salvador
 Gaudeloupe
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Honduras (Br.)
 Jamaica
 Martinique
 Mexico
 Netherlands Antilles
 Nicaragua
 Panama
 St. Pierre et Miquelon
 Trinidad et Tobago
 West Indies (Br.)
 South
 Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Chile

Colombia
 Ecuador
 Falkland Islands
 Guyana
 Guiana (Fr.)
 Paraguay
 Peru
 Surinam
 Uruguay
 Venezuela
Asia
 Middle East
 Bahrein
 Iran
 Iraq
 Israel
 Jordan
 Kuwait
 Lebanon
 Oman
 Qatar
 Saudi Arabia
 Yemen (People's DR).
 Syrian (Arab. Rep.)
 Unit Arab Emirates
 Yemen (Arab. Rep.)
South
 Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Burma
 India
 Maldives
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka
Far East
 Brunei
 Khmer Rep.
 Hong Kong
 Indonesia
 Korea (Rep. of)
 Korea (People's Dem. Rep. of)
 Laos
 Macao
 Malaysia
 Philippines
 Singapore
 Thailand
 Timor
 Vietnam (Rep. of)
 Vietnam (Dem. Rep. of)
Oceania
 Fiji
 Gilbert & Ellice Islands
 French Polynesia
 New Caledonia
 New Hebrides (Br. & Fr.)
 Pacific Islands (US)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa
Europe
 Turkey
 Portugal

Appendix 'B' Rules of Origin

1. The subject items of these rules of origin shall be goods and services produced in the eligible source countries.

2. In the case of goods, assessment of the Netherlands origin shall be subject to the legislation in this field which prevails in the European Community.

3. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 2 shall be furnished by means of a certificate of origin, issued by a Chamber of Commerce in the Netherlands.

4. In the case of goods, assessment of origin in developing countries shall be subject to the rules of origin which are established by the European Community in the framework of the General System of Preferences.

5. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 4 shall be furnished by means of a Certificate of Origin, Form A (as in use by the General System of Preferences), issued by an official authority in the developing country.

6. In the case of services (of paragraph 1 of the Guidelines), Origin shall be assessed, on an ad hoc basis, in mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

7. In cases where the Rules of Origin cause substantial problems of serious economic damage to the borrower country (e.g. an over-tight restriction of the number of potential suppliers), deviations from these rules may be permitted, but only after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

ANNEXURE II

- (a) Name and address of the Indian importer and/or Project authority where necessary.
- (b) Name and address of the supplier. In case of suppliers in Eligible Source Countries, the following information should also be furnished—
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by national of the eligible source countries.
- (c) (i) No. and date of Import Licence.
(ii) Value.
- (d) (i) Name and address of the Suppliers Bank in the Netherlands/Eligible Source Country.
 *(ii) The Importers Bank in India (Which will be the bank that has furnished the Bank Guarantee).
 ** (iii) The importers Bank in India which will be responsible to make rupee deposits in Government account before releasing shipping documents to the importer.
- (e) Value of the contract order in Dutch Guilders or the currency of the Eligible Source Country.
- (f) Method of Procurement whether it is based on direct purchase or Formal Open International Bidding, or selective Formal International Bidding, in which case it should be indicated whether the contract has been entered into on the basis of the lowest technically suitable offer, with reason, if any.
- (g) Short description of goods to be imported.
- (h) Origin of Goods—percentage of imported components from non-eligible source countries, if any.
- (i) Expected date of completion of deliveries.
- (j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

*for Private Sector.

**for Public Sector.

68 GI/78—5

(k) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, Certificate of Origin, etc. which the Netherlands Investment Bank for Developing countries or the Suppliers Bank in Eligible Source Country should demand from the suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.

(l) Indian Agents commission, if any, included in the contract (exact amount to be indicated), which will have to be deducted from the contract value while issuing a Letter of Authority. Such commission will be payable by the Importers direct to the Agents in rupees.

(m) Value of which the Letter of Authority is requested.

(n) Number, date and value of Bank Guarantee, indicating the period upto which it is valid.

(o) Special instructions, if any.

ANNEXURE III DUTCH CREDIT CONTRACT CERTIFICATE Particulars of contract

Indian Import Licence No.

1. Number and Date of the Contract

2. Description of goods or services to be supplied to the purchaser

(If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate).

3. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB) Df

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED.

4. Estimated % of the FOB value of the goods not originating in the Netherlands but purchased by the supplier direct from abroad, i.e. % of imported raw material or components used in manufacture.

(a) % FOB value

(b) Description of items and brief specification

5. IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED

6. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by

(a) Your firm (site engineers charges, etc.)

(b) Local supplier

7. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 4 & 5 above

8. I hereby declare that I am employed in the Netherlands by the Supplier named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of Netherlands origin will be supplied by the supplier other than these specified in paragraphs 4 & 5 above.

Signed

Position held

Name and address of

supplier

Date

Certified

Netherlands Chamber of Commerce District.

ANNEXURE IV GUARANTEE BOND

(To be furnished by Banks under the procedure for the import of goods under the Dutch General Purpose Credit)

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Dutch Guilders for the import of _____ by _____ (hereinafter called the Importer) against the import licence number _____ dated _____ issued under the terms and conditions of the Dutch General Purpose Credit and in pursuance of Import in favour of the Importer against the above mentioned agreement, we _____ (Bank) at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursements made by the Netherlands Investment bank for Developing Countries, The Hague nominated by the importer converted at the prevailing composite rate of exchange calculated as per Public Notices issued by the Government in the matter from time to time within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Head of Account as indicated by Government of India under the said Credit together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof (as prescribed in Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16-6-1976) reckoned from the date of payment to the Dutch supplier to the date of payment of rupee equivalent for Credit to the Government Account. The negotiable set of import documents received from the Netherlands Investment bank for Developing Countries, The Hague will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We the _____ (Bank) also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct such sums not exceeding Rs. _____ or any part thereof for the time being due and payable by the Importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof (vide Public Notice *ibid*) reckoned from the date of payment to the Dutch Supplier to the date of actual deposit of the rupee equivalent into Government account. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us _____ (Bank), shall be final and binding on us _____ (Bank).

3. We _____ (Bank) further agree that in case of increase in the value of import or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place in proportion to this change.

4. We _____ (Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importer or the _____ (Bank), and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and the _____ (Bank), shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the _____ (Bank) from its such liability.

6. We _____ (Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government, in writing.

7. We _____ (Bank), hereby undertake to make additional deposits in terms of Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 and such other Public Notices that may be issued time to time hereafter.

8. Our liability under this guarantee is restricted to Rs. _____ (plus interest and other charges, if any, not expected to exceed one per cent of the guarantee amount) and this guarantee shall remain in force till the _____ day* of _____ month, 19_____. Unless claims under this guarantee are made in writing within six months* of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto _____, all Government's rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the _____ day of _____

For _____ (Bank).

Accepted for and on behalf of
the President of India by

Shri _____

(Name & Designation)

Signature _____

*This date shall be arrived at the adding one month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

Note:—The value of the Stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps act.

ANNEXURE V

No. F. 14()-WE.III/

Government of India (Bharat Sarkar)

Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)

Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)

New Delhi, the

_____ of _____, The Hague, Netherlands.

To

Agreement for the loan of _____ million Netherlands
Guilders—Request for direct payment.

Dear Sirs,

The Netherlands Investmentbank for Developing Coun-

LETTER OF AUTHORITY No.

With reference to our application of today's date as to the financing of the transaction between M/s. _____, India and M/s. _____, Holland, out of the loan made by your Bank to India, we hereby request and authorise you unconditionally and irrevocably to pay in accordance with the terms and conditions of the above mentioned contract to the supplier in Holland the amount of N. fl. _____ (_____ only). It is requested that the invoices, shipping and other documents presented by the Dutch supplier be despatched direct to the _____.

The suppliers will also be required to furnish to the Netherlands Investmentbank for Developing Countries a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the Letter of Authority.

Kindly forward the debit advice to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,

Economic Aid (Accounts) Branch, Jeevan Deep, Parliament Street, New Delhi. This letter of Authority will remain valid upto _____

For the President of India,

Copy to _____
(Importer's Bank)

They should ensure that the rupees equivalent at the Composite rate of exchange to be calculated in the manner prescribed in Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 and such other Public Notices that may be issued from time to time together with the interest thereon at the rates prescribed in Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976 from the date of payment to the suppliers to the date of deposit of the amount into Government Account is deposited before releasing the original documents to the Importer.

Annex VI

No. F. (14()-WE. III/

Government of India
(Bharat Sarkar)

MINISTRY OF FINANCE

(Vitta Mantralaya)

Department of Economic Affairs
(Arthik Karya Vibhag)

New Delhi, the

Subject :—Contract entered under General Purpose Dutch Credit—Reimbursement.

Dear Sirs,

Messrs. _____

(Indian importer)

have entered into a contract with Messrs _____

(Foreign supplier)

for the supply of _____

for the amount of _____

_____ C. I. F./C. & F. against
Licence No. _____ dated _____

issued under the Dutch General Purpose Credit for the value
of Rs. _____ (Rupees _____)

A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of _____
an amount of _____ is to be paid as Indian Agents' Commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency which will be financed initially out of the free foreign exchange resources, to be reimbursed later out of the Dutch General Purpose Credit, therefore, amounts to _____.

3. You are authorised to open a letter of credit in favour of Messrs. _____

_____ though their
bankers, viz. Messrs. _____

within a period of thirty days from date of this letter and against a valid Import Licence, under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

4. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of the expiry of the Letter of Credit is not later than forty-five (45) days after the final date for shipment as stated in the relative import licence.

5. The letter of credit will also provide that Messrs. _____

(foreign banker)

will forward directly to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the Dutch Supplier that the payment has been received by the latter.

They will also obtain from the suppliers and furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the Letter of Credit/* issued by the appropriate competent authority in regard to the origin of the goods covered under the Letter of Credit.

6. You are also required to forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi a certificate of remittance made by you to M/s. _____

against the invoice/shipment of goods, excluding Bank charges, if any.

7. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

*To be deleted if not applicable.

Copy with a copy of contract forwarded to :—

Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Bombay-1.

2. Copy also forwarded for information to :—

(i) _____

(Indian importer)

It may be ensured that M/s. _____
(foreign banker)

forward one set of shipping and other documents (non-negotiable) along with payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him, and two copies of certificate in regard to origin of goods to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(ii) M/s. _____
(foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) along with payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him and two copies of certificate in regard to origin of goods may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(iii) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

ANNEX VII

STATEMENT SHOWING QUARTERLY REPORT ON
UTILISATION UNDER DUTCH (G.P.) CREDIT

1. Name of Importer.
2. No. and date of Import Licence
3. Value of Import Licence.
4. Value of orders placed.
5. Letter of Authority No. and date
6. Amount of Letter of Authority
7. Date of Validity of Letter of Authority.
8. Amount utilised during the Quarter. D.G
9. Total amount utilised. D.G
10. Total Amount deposited into Government Account Rs
11. Payment to be made during the subsequent quarters
12. Surrenders, if any.

APPENDIX II

Conditions for Licensing Public Sector Imports under the
Dutch General Purpose Credit

Section I—General

I(1) The Dutch General Purpose Credit for 1977-78 extended by the Nederlandse Investerings bank Voor Ontwikkelingslanden N. V. is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and commodities and services incidental thereto which are to be financed under the Credit can be imported from Netherlands and all countries enumerated in the list at Appendix A of the "Guidelines for Procurement of Goods and Services under Bilateral Development Loans by the Netherlands" (Annex I) which will be the "eligible source countries" under the credit.

I(2) Components to the extent of 10 per cent in respect of chemicals and 20 per cent in respect of other imports from non-eligible source countries can, however, be considered for being financed under the Credit. Specific requests in this regard, if any, should be made to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE III Section) before finalising the contracts.

I(3) Limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries in excess of the limit indicated in Section I(2) may also be considered for financing under the credit. For this, specific approval of the Government of Netherlands will be necessary.

Section II—Issue of Import Licence

II(1) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing authority concerned, within the validity period of the licence, who shall consult the Department of Economic Affairs, (WE III Section) in the matter.

II(2) Firm order on CIF/C&F basis must be placed on the overseas suppliers in the Netherlands or the countries mentioned in the Annex I and sent to the Department of Economic Affairs (WE III Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. If firm orders cannot be finalised within the time limit of 4 months, the Licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period, furnishing justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on

the merits of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of import licence, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs, (WE III Section), Ministry of Finance.

The terminal date of disbursements in both the credit agreements viz Dfl. 120 million and Dfl. 54 million would be 31-12-1980.

II(3) The licence will bear the superscription 'Dutch General Purpose Credit' and indicate the Public Notice number under which these licensing conditions are issued. The licence code for the first and second suffix will be "S"/"NN". This licence code will be mentioned in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Reserve Bank at the time of rupee deposit.

II(4) As soon as the importer receives the import licence, he should send a report to that effect to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE III Section) along with the following information:—

- (i) No. and Date of Import Licence ;
- (ii) Value.
- (iii) Exchange rate, if any, indicated on Import Licence.
- (iv) Date by which copies of contract are expected to be furnished to Department of Economic Affairs

Section III—Finalisation of Contract

III(1). The minimum value of contract eligible for financing under the credit is Dfl. 25,000.

III(2). Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract will be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

III(3). The contract for the import of goods and services from the Netherlands and eligible source countries should be finalised keeping in view the Guidelines for Procurement of Goods and Services, as detailed in (Annexure. I).

III(4) Goods and services should be procured through Formal Open International Bidding except in the following cases :

- (a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ; or
- (b) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million , or
- (c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the Government of India on another more expedient procedure must be reached before the contract for the supplies could be finalised.

III(5) It would also not be necessary to resort to Formal Open International Bidding in the following types of cases —

- (a) where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardisation of this equipment
- (b) in cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers
- (c) where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only.

In such cases the procurement formula of paragraphs 31 to 39 of the Guidelines for procurement of goods and services (Annex. I) may be followed.

III(6) The purchaser may purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer ;
- (iii) in order to assure interchange ability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source;
- (iv) the importer is a manufacturer whose equipment and raw material formulae are designed for best utilisation with a specific type of raw material which can only be obtained from one source ;
- (v) the importer wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made;
- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

III(7). Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, before invitations for proposals are sent out by the Indian firms to the consultant firms, a list of such prospective firms should be furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E.III Section). The list in turn will be submitted to the Government of Netherlands who may approve the same or reject the choice of a consultant and may on the basis of their knowledge of the consultancy sector in Netherlands suggest that this list is extended.

III(8). Where the goods are proposed to be procured on the basis of Formal Open International Bidding, the importer should forward three copies of the tender notices as soon as these are advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India, New Delhi, under intimation to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E.III Section), New Delhi.

III(9). The term "Firm Orders" referred to in Section II(2) means purchase order placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

III(10). The CIF/C&F value of the contract should be expressed in Dutch Guilders in case of contracts concluded with the Dutch suppliers and in the respective currency in case of contracts concluded with the suppliers in eligible source countries.

III(11). The contract must provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian Importer from the overseas suppliers.

III(12). The amount of Indian Agent's Commission included in the value of the contract should be specifically

indicated. Any payment on this account, should be made in Indian rupees to the Agent in India. No remittance of foreign exchange will be permitted for the purpose. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

III(13). The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

III(14). The following provisions should be specifically incorporated in the contract :

- (i) "the contract is subject to the approval of Government of India (if the value of the contract is Dutch Guilders 50,000 or below) and subject to the approval of both the Government of India and the Government of Netherlands (if the value of the contract exceeds Dutch Guilders 50,000).
- (ii) This contract will be governed by the payment procedures laid down under the licensing condition for the Dutch General Purpose Credit and will become effective after the Government of India's contract exceeds Dutch Guilders 50,000).
- (iii) "The goods are of Dutch origin/manufacture" (in case of supplies in Netherlands)

or

"The goods are of.....origin/manufacture"
(in case of suppliers in eligible source countries.)

- (iv) "For the goods to be imported from Netherlands, the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank, a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the supplier is establish to the effect that the goods are of Netherlands origin. This certificate can be furnished along with the other shipping documents at the time of receiving, payment. A specimen of the certificate is at Annex. III.

In the case of supplier in eligible source countries the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank proof of origin of goods in accordance with the Rules of Origin appended to the "Guidelines for Procurement of Goods and Services (Annex. I)."

III(15). For any customary performance guarantee, where required, the suppliers should be asked to furnish a bank guarantee/warranty.

Section IV—Approval of contract by Government of India / Netherlands Investment Bank.

IV(1). Immediately after the contract is concluded, the importer should furnish 5 photostate or certified copy of the contract/supply orders accompanied by a photostate copy of the Import Licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section). In case of contracts concluded with supplies in eligible source countries, 8 copies of the same should be furnished. The importer is also required to furnish the information as per details in Annex. II.

IV (2) When the Supply contract is based on formal open international bidding or formal selective International bidding, the following information should also be furnished :—

- (i) Name of the publication in which tender notice was advertised ;
- (ii) Name of the parties who quoted against the tender enquiry ;
- (iii) The reason for selecting a particular offer indicating whether it was the lowest technically suitable bid.

IV(3). If the contract documents, the request for issue of letter of authorisation and the import licence are found to be in order, the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will forward copies of the contract to the Dutch authorities through the Embassy of Indian at The Hague for approval.

IV (4) (a). In respect of contracts valued at DG 50,000 or below approval of Dutch authorities is not required. The approval of the Government of India will be communicated to the Indian importers while forwarding the copies of their contracts/supply orders to the Dutch Authorities.

(b) For contracts of value exceeding DG. 50,000, as soon as the approval of the Dutch authorities to the financing of the contract under Dutch Credit is received, the importer will be informed that their contract has become effective.

Section V—Payment to the Suppliers :

(A) Payment to the Suppliers in Netherlands

V(1). A letter of Authority to the Netherlands Investment Bank for Developing Countries, The Hague (in the form at Annex. IV) authorising payment to the suppliers against shipping documents will be issued and forwarded along with the copies of contract etc., to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague.

V(2). The validity of the Letter of Authority will be determined keeping in view the delivery schedule indicated in the contract. In no case will the Letter of Authority be made valid beyond the validity of the import licence.

V(3). Since the payments to the suppliers under the credit are generally made by the Dutch Bank against the production of shipping documents, the grace period facility will not be applicable to imports financed under this credit.

V(4). In case the shipment/payments to the suppliers are not completed within the validity period of the Letter of Authority, the Importer should approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.F. III Section) for suitable extension of the Letter of Authority well before the expiry period of the Letter of Authority. Such a request should be accompanied with a photostat copy of the re-validated Import Licence, if the period of extension sought for is beyond the validity of the original Import Licence.

V(5). If the request for extension in the period of validity of the Letter of Authority is not received within a period of six months from the validity date of the Letter of Authority the un-utilised balance in the Letter of Authority will be deemed to have been surrendered and the Letter of Authority will stand lapsed automatically.

V(6). The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Netherlands Investment bank to the concerned importer's bank in India, which would be a branch of any of the nationalised banks who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the importer has deposited :

- (i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports & Export's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the C.C.I.&E. or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India,
- (ii) interest calculated at the rate of 9 per cent. per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976 on the amount required to be deposited vide item (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N. V., The Hague to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

V(7). It shall be responsibility of the Indian Bank concerned, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

V(8). Public Sector importers (including Departments of the Central Government) should make the requisite rupee deposit only through Authorised Dealers in foreign exchange and also get the Exchange Control Copy of the Licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated the 30th August, 1968. The requisite 'S' form will be sent by the concerned bank to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(9). The moneys specified in Section V(6) should be deposited only with the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi to the credit of the Central Government Account under the head of account.—

"K—Deposits and advances—Deposit not bearing interest—843—Civil deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Purchases etc. under Dutch General Purpose Credit 1974-75".

V(10). The advice of rupee deposits referred to above, should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi by enclosing original receipted treasury challan in the proforma prescribed under Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The information in regard to letter of Authority No., amount of foreign currency for which rupee deposit is made, date of payment to the Dutch supplier, amount of interest and period for which it is calculated should invariably be indicated in the challan form.

B. PAYMENT TO THE SUPPLIERS IN ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

V(11). A Letter of Authority (in form at Annex. V) to the Importers Bank, as indicated by the Importer in his application authorising opening of a Letter of Credit on the suppliers' bank in the eligible source country in favour of the supplier will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.F. III Section). Copies of the contract along with a copy of the said Letter of Authority will be forwarded to the Dutch authorities also through the Embassy of India at The Hague.

V(12). On receipt of the Letter of Authority mentioned in the preceding paragraph, the Importer's Bank will open a letter of Credit in favour of the supplier through his banker within a period of 30 days from the date of issue of the said Letter of Authority and against a valid import licence. An intimation to this effect shall be forwarded to the Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V(13). After the payment to the supplier is made the supplier's bank shall forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by the latter.

V(14). The supplier's bank will also obtain from supplier and furnish to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate or proof (in duplicate) in regard to the origin of the goods being in accordance with the Rules of origin appended to the "Guideline for Procurement of Goods and Services."

V(15). The importer should forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate of remittance made by them to the supplier against the invoice/shipment of goods excluding bank charges, if any. This certificate should be obtained from the bank through which the Letter of Credit is opened. The importer should also ensure that one set of non-negotiable shipping documents and two copies of invoice with a certificate duly endorsed thereon in regard to receipt of payment by supplier and certificate of origin, referred to in Section V(13) and V(14) are forwarded to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Controller of Aid Accounts & Audit within 15 days of the shipment of goods.

V(16). Payment against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence

V(17) Normally all shipments/payments to the Supplier should be completed within a period of 20 months from the date of issue of the Letter of Authority referred to above. In case the shipments/payments to the supplier are not likely to be completed within the period of 20 months, the Importer should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section) at least a month before the expiry of this limit for completing the shipments/payments to the suppliers. This request should be accompanied with a photostate copy of the revalidated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the unutilised balances of the contract will be deemed as having been surrendered.

V(18). Any omission on the part of the importer to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.&E. may be asked to suspend all import licences issued in the favour of the importer. In case the importer persists in his default his case may be recommended to the C.C.I. & E. for being blacklisted. The importer will, in addition, be liable to penalties/punishments under the law governing Import Control etc.

V(19). On receipt of the reimbursement documents, Controller of Aid Accounts and Audit in the Ministry of Finance, will make a request to the Netherlands Investment Bank for reimbursement of the amount paid to the supplier in the eligible source countries. The Netherlands Investment Bank will reimburse the equivalent amount in Netherlands guilders at the rate of exchange prevailing in the Netherlands on the date of such reimbursement.

Section VI : Miscellaneous :

VI(1). The importer should furnish a quarterly report, as in Annex. VI, showing utilisation status of the licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section).

VI(2). It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the supplier. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment could be effected to him must be clearly spelt out by the importer in Annex. II. If necessary, a provision dealing with settlement of disputes may be included in the contract itself.

VI(3). The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to import licence and for meeting all obligations under Dutch General Purpose Credit.

VI(4). Any breach of violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEX I

Guidelines for Procurement of goods and services under bilateral development loans by the Netherlands

A. General

1. These guidelines govern procurement of goods and services under bilateral loans which form part of the official Netherlands Development Aid Programme. These loans are untied in respect of developing countries. A list of eligible source countries is attached as Appendix A. The recipient country is included in this list. The Netherlands Government may agree, on an individual basis, to limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries, with transportation and insurance costs included.

2. The Netherlands Government must be satisfied that the proceeds from the loans are to be used with due care being given to economy, efficiency, fairness in international competition and non-discrimination among eligible source countries, in accordance with the procurement procedures set out in these guidelines.

3. Except in the cases mentioned in paragraph 16 and 17, no practices shall be allowed, which could lead to, or result in a particular supplier or the suppliers of a particular country being favoured

4. The rules of origin and control to be observed by the borrower in the procurement of goods and services, are attached to these guidelines as Appendix B.

5. Where the borrower does not effect direct procurement, he shall make such arrangements as are necessary to ensure that the purchaser complies with these guidelines.

6. (1) The borrower shall obtain goods and services through formal open international bidding except in the following cases :

- where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ;
- where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million; or
- where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the borrower on another more expedient procedure must be reached before suppliers are invited to submit their bids, such agreement to be reached on the basis of all relevant information to be supplied by the borrower through the Royal Netherlands Embassy.

6. (2) Where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only, the borrower shall have the option to confine bids to the Netherlands only or obtain bids from the Netherlands as well as the eligible source countries. In such cases article 30 of the Guidelines along with articles 31-33 or article 30 along with articles 34-38 are applicable.

7. These guidelines, together with the Rules of Origin and the list of eligible source countries, are subject to amendment by the Netherlands Government.

B. Procedures for Formal Open International Bidding

8. At the time invitations to bid are issued, the borrower (or the purchaser on the borrower's behalf) shall advertise the bidding in at least one of the following two publications :

Indian Trade Journal.

Indian Export Service Bulletin.

The importer shall send three copies of the tender notices as advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India.

9. In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited should, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is possible from a technical and administrative point of view to divide a project into contracts of a specialized nature and such division is likely to be advantageous to the borrower and/or to allow broader international competitive bidding the project should be divided. Single contracts for engineering, equipment and construction work (commonly known as "Turn-key contracts") may be desirable if they offer overall advantages to the borrower country within the technical and economic facilities available.

10. Formal prequalification may be desirable, in particular for civil works contracts. If prequalification is used, it shall be based entirely upon ability to perform satisfactorily, taking into account (i) the firm's previous experience in similar types of work, (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial position and integrity. Advertisement of the prequalification procedure shall be carried out in accordance with the procedure described in paragraph 8. Condensed specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for prequalification. When prequalification is applied, all firms which fulfil the conditions for prequalification shall be permitted to bid.

11. Bidding documents shall be prepared in one of the languages customarily used in international transactions and shall unless prohibited by law specify that the text of the documents in that language is governing.

12. Specifications shall set forth as clearly and precisely as possible the work to be carried out, the goods and services to be supplied and the place of delivery of installation. Drawings shall be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications shall state the principles of evaluations and comparison of bids, which will be taken into account when evaluations are made and bids are compared. The specifications shall be worded in such a way as to permit and encourage free and full international competition.

Any additional information, clarification or correction of errors and alterations of specifications and invitations to bid shall be communicated promptly to those who requested the original bidding documents.

13. If national standards are cited to which equipment or material must comply, the specifications shall state that goods meeting other internationally accepted standards, which demand are equal or better quality than the standards mentioned, will also be accepted.

14. Specifications shall be based on performance and potential and should only prescribe registered brand names, catalogue numbers or products of a particular manufacturer if particular spare parts are required or if it has been decided that a certain amount of standardization is necessary to maintain certain essential quality factors. In the last case the specifications shall permit offers of alternative goods which have similar characteristics and whose performance and quality are of a level at least equal to those specified.

15. Invitations to bid shall list the eligible source countries and shall set out the rules of origin applicable.

16. Quotations shall be examined on the basis of strict equality of conditions among suppliers from eligible source countries (including the evaluation of quotations for material and equipment at prices free of customs tariffs and other duties and taxes of like effect). The borrower country, however, is authorised, in the evaluation and comparison of bids to supply goods and services, excluding transport costs, to extend a margin of preference to local goods and services and to products from other eligible source countries which are members of the same regional economic group, consistent with GATT, or which intend to establish such a group, over goods and services originating in other eligible source countries. This margin of preference shall not exceed 15 per cent on the CIF price of the lowest evaluated foreign bid or the existing level of customs duties of the bidder's country, whichever is the lowest.

17. In special cases, the borrower may, after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrowing country, extend a limited margin of preference to local and regional manufacturers, consistent with GATT, in addition to the margin of preference, mentioned in paragraph 16. In assessing the level of preference, due attention should be given to factors like the degree of national or regional ownership and management and the registration in the borrower country or the regional economic group of these manufacturing firms.

18. Bidding documents shall set out any preferences agreed upon and specify the manner in which they will be applied in the evaluation and comparison of bids.

19. Bidder shall be given adequate time in which to submit their bids.

20. The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening shall be announced in the invitations to bid and all bids shall be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time shall be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted shall be read aloud and recorded.

21. No bidder shall be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but shall not ask any bidder to change the substance or price of his bid.

22. Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards shall be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures on the side of either the borrower or the Netherlands Government before the announcement of the award of a contract to the successful bidder.

23. After the opening of the bids, the purchaser shall examine the bids in order to ascertain whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the requirements of the bidding documents, whether the required guarantees and sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it shall be rejected. A technical analysis together with a detailed assessment in monetary terms shall then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

24. Invitations to bid may state that the purchaser reserves the right to reject all bids when none are responsive to the intent of the specifications, when there is evidence of lack of competition, or when the low bids exceed the cost previously estimated by an amount sufficient to justify such action. If all bids are rejected, the borrower may, after consultation with the Netherlands Government, enter into negotiation with one or more of the lowest bidders to ascertain the causes for such events and the reasons for the difference between the low bid and the cost estimates. Negotiated contracts reflecting changes in the specifications, leading to economies in the estimated cost of the project, may be acceptable, provided the changes do not substantially alter the nature of the project. Where changes are substantial, re-bidding may be appropriate. This shall at all times be approved by the Netherlands Government.

25. Evaluations of bids shall be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents and in any modifications thereto prior to the closing date for submission of bids. For the purpose of determining the lowest evaluated bid, commercial factors other than price, such as the time of completion of construction or other work, the efficiency and reliability of the equipment, the time of its delivery and the availability of service and spare parts, shall also be taken into consideration and shall, to the largest possible extent, be expressed in monetary terms. The currencies in which bid prices would have to be paid shall be valued, for bid comparison purposes only, on the basis of rates of exchange published by an official source and applicable to similar transactions at the closing date of the bidding.

26. The award of a contract shall be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid, taking into account the factors mentioned in the preceding paragraphs.

27. The Netherlands Government shall, upon request, be given adequate opportunity to present its comments and recommendations on all phases of procurement. After the award of contract, the Netherlands Government shall be provided with (copies of) all relevant documents and other information necessary for the evaluation of the use of the loan.

C. Procurement Procedures other than Formal Open International Bidding.

28. In the cases mentioned in paragraphs 29 and 30, the procurement formulae of paragraphs 31—39 may be applied in accordance with paragraph 6.

29. Standardization where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

30. Limited Number of Qualified Suppliers : In cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.

Formal Selective International Bidding

31 Under formal selective international bidding the purchaser is authorized to invite bids from only a limited number of (pre) qualified suppliers known to be able to meet the special requirements of the procurement in question

In such cases the borrower should ascertain that no potential qualified suppliers have been excluded. The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all necessary information as and when asked for by potential suppliers of eligible source countries to enable them to participate on an equitable basis

32 The suppliers are to be selected exclusively on the basis of their qualifications and are, as far as possible, to be chosen from several eligible source countries including the Netherlands

33 All provisions of formal international bidding, other than those of paragraph 8, are to be fully applied.

Informal International Competitive Procurement

34 If procurement is not through the formal competitive bidding procedures, it should be made in accordance with good commercial practice and without discrimination among eligible source countries

35 The importer should give wide and timely publicity to the intended use of informal international competitive procurement. The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all information necessary to permit suppliers of eligible source countries to participate on an equitable basis as and when such information is asked for

36 The time allowed for the preparation of quotations and offers shall be governed by the nature of the contracts involved. Both lead time and delivery schedules shall be long enough to allow meaningful international competition

37 The Netherlands Government may require the purchaser in particular cases to supply information on the purchases made, including full details concerning how quotations were obtained, the suppliers who are involved and the quotations received

38 The guidelines for formal open international bidding should be applied to the fullest possible extent as appropriate

Single Supplier

39 The purchaser is permitted to purchase directly from a single supplier in one of the following cases

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer,
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end-product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer,
- (iii) in order to assure interchangeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source,
- (iv) the purchaser is a manufacturer whose equipment and raw material formulae are designed for best utilization with a specific type of raw material which can only be obtained from one source,
- (v) the purchaser wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement,

takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made;

- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 125 million

D Guidelines for the Use Consultants

40 Consultant firms employed should be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and bid documents prepared by them should be free of national, commercial or industrial bias, and can be compiled with on a competitive basis. In considering local consultant firms, due attention should be given to factors like the degree of national ownership, management and personnel and registration

41 Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, in the process of selection, borrowers should consider a reasonable number of prospective firms, which can be expected to render competent and independent services from several eligible source countries. This list shall be based on prequalification, taking into account

- (i) the firm's previous experience in similar types of work,
- (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant, and
- (iii) its financial position and integrity

It is desirable that before invitations for proposals are sent out, the borrower submits the list of prospective firms to the Netherlands Government. The Netherlands Government reserves the right to reject the choice of a consultant, and may, furthermore on the basis of her knowledge of the consultancy sector in the Netherlands, suggest that this list is extended

F Grievances

42 The borrower shall make provision for the hearing and investigation of complaints arising in connection with the invitations to bid, the submission of bids and the award of contracts

43 In the case of purchases conducted under formal international bidding procedures complaints of any substance, regarding restrictive commodity specification or other restrictive terms of the invitation, made prior to the bid closing date, shall be resolved before the opening of bids. If necessary and only after consultation with the Netherlands Government, the bid closing date may be postponed for an appropriate period

44 When a complaint has been made by one of the suppliers concerned, the documentation relating to the substance of the complaint and action taken thereon shall be available for examination by the Netherlands Government, as well as by the borrower.

APPENDIX A

List of eligible source countries for untied bilateral loans to developing countries

-
- A Netherlands
 - B Africa
 - North of Sahara
 - Algeria
 - Libyan Arab Rep.
 - Morocco
 - Tunisia
 - Egypt
 - South of Sahara
 - Botswana

Burundi
 Cameroon
 Cape Verde Islands
 Central African Rep.
 Chad
 Comoro Islands
 Congo (People's Rep. of)
 Zaire Rep.
 Dahomey
 Ethiopia
 Gabon
 Gambia
 Ghana
 Guinea
 Guinea Bissau
 Ivory Coast
 Kenya
 Lesotho
 Liberia
 Malagasy Republic
 Malawi
 Mali
 Mauritania
 Mauritius
 Niger
 Negeria
 Reunion
 Rwanda
 Senegal
 Seychelles
 Sierra Leone
 Somalia
 Terr. Afars and Issaa
 St. Helena and dependences
 Sudan
 Swaziland
 Tanzania
 Togo
 Uganda
 Upper Volta
 Zambia
 America
 North and Central
 Bahamas
 Barbados
 Bermuda
 Costa Rica
 Cuba
 Dominican Republic
 El Salvador
 Guadeloupe
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Honduras (Br.)
 Jamaica
 Martinique
 Mexico
 Netherlands Antilles
 Nicaragua
 Panama
 St. Pierre et Miquelon
 Trinidad and Tobago
 West Indies (Br.)
 South
 Argentina
 Bolivia

Brazil
 Chile
 Columbia
 Ecuador
 Falkland Islands
 Guyana
 Guiana (Fr.)
 Paraguay
 Peru
 Surinam
 Uruguay
 Venezuela
 Asia
 Middle East
 Bahrain
 Iran
 Iraq
 Israel
 Jordan
 Kuwait
 Lebanon
 Oman
 Qatar
 Saudi Arabia
 Yemen (People's DR)
 Syrian (Arab. Rep.)
 Unit. Arab Emirates
 Yemen (Arab. Rep.)
 South
 Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Burma
 India
 Maldives
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka
 Far East
 Brunei
 Khmer Rep.
 Hong Kong
 Indonesia
 Korea (Rep. of)
 Korea (People's Dem. Rep. of)
 Laos
 Macao
 Malaysia
 Philippines
 Singapore
 Thailand
 Timor
 Vietnam (Rep. of)
 Vietnam (Dem. Rep. of)
 Oceania
 Fiji
 Gilbert & Ellice Islands
 French Polynesia
 New Caledonia
 New Hebrides (Br. & Fr.)
 Pacific Islands (US)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa
 Europe
 Turkey
 Portugal

APPENDIX 'B'

Rules of Origin

1. The subject items of these rules of origin shall be goods and services produced in the eligible source countries.

2. In the case of goods, assessment of the Netherlands origin shall be subject to the legislation in this field which prevails in the European Community.

3. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 2 shall be furnished by means of a certificate of origin, issued by a Chamber of Commerce in the Netherlands.

4. In the case of goods, assessment of origin in developing countries shall be subject to the rules of origin which are established by the European Community in the framework of the General System of Preferences.

5. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 4 shall be furnished by means of a Certificate of Origin, Form A (as in use by the General System of Preferences), issued by an official authority in the developing country.

6. In the case of services (cf. paragraph 1 of the Guidelines), origin shall be assessed, on an ad hoc basis, in mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

7. In cases where the Rules of Origin cause substantial problems or serious economic damage to the borrower country (e.g. an over-tight restriction of the number of potential suppliers), deviations from these rules may be permitted, but only after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

ANNEXURE II

(a) Name and address of the Indian importer and/or Project authority where necessary.

(b) Name and address of the supplier. In case of suppliers in Eligible Source Countries, the following information should also be furnished—

(i) Nationality.

(ii) Percentage of the shares held by national of the eligible source countries.

(c) (i) No. and date of Import Licence.

(ii) Value.

(d) (i) Name and address of the Supplier's Bank in the Netherlands/Eligible Source Country.

* (ii) The Importers' Bank in India (which will be the bank that has furnished the Bank Guarantee).

** (iii) The importers' Bank in India which will be responsible to make rupee deposits in Government account before releasing shipping documents to the importer.

(e) Value of the contract order in Dutch Guilders or the currency of the Eligible Source Country.

(f) Method of Procurement whether it is based on direct purchase or Formal Open International Bidding or Selective Formal International Bidding, in which case it should be indicated whether the contract has been entered into on the basis of the lowest technically suitable offer, with reasons, if any.

(g) Short description of goods to be imported.

(h) Origin of Goods—percentage of imported components from non-eligible source countries, if any.

(i) Expected date of completion of deliveries.

(j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(k) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, Certificate of Origin, etc., which the Netherlands Investment bank for Developing Countries or the Suppliers' Bank in Eligible Source Country should demand from the suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.

(l) Indian Agent's commission, if any, included in the contract (exact amount to be indicated), which will have to be deducted from the contract value while issuing a Letter of Authority. Such commission will be payable by the Importers direct to the Agents in rupees.

(m) Value of which the Letter of Authority is requested.

(n) Number, date and value of Bank Guarantee, indicating the period upto which it is valid.

(o) Special instructions, if any.

*for Private Sector.

**for Public Sector.

ANNEXURE III

DUTCH CREDIT

CONTRACT CERTIFICATE

Particulars of contract

Indian Import Licence No.

1. Number and Date of the Contract.....

2. Description of goods or services to be supplied to the purchaser

(If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate).

3. Total contract price payable by purchaser (State CIF, C&F or FOB) Dfl.....

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED

4. Estimated per cent of the FOB value of the goods not originating in the Netherlands but purchased by the supplier direct from abroad, i.e. per cent of imported raw material or components used in manufacture.

(a) per cent FOB value.....

(b) Description of items and brief specification.....

5. If services are to be supplied the following section should also be completed.

6. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by

(a) Your firm (site engineers charges, etc.).....

(b) Local supplier

7. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 4 and 5 above.....

8. I hereby declare that I am employed in the Netherlands by the Supplier named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of Netherlands origin will be supplied by the supplier other than those specified in paragraphs 4 and 5 above.

Signed.....

Position held.....

Name and address of

Supplied.....

Date.....

Certified

Netherlands Chamber of Commerce..... District.

ANNEXURE IV

No. F. 14()-WE.III/

Government of India

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Netherlands Investment bank for developing Countries,
The Hague, Netherlands.

Agreement for the loan of _____ million Netherlands
Guilders—Request for direct payment.

Dear Sirs,

LETTER OF AUTHORITY No.

With reference to our application of today's date as to
the financing of the transaction between M/s. _____

_____, India and
M/s. _____, Holland out
of the loan made by your Bank to India, we hereby request
and authorise you unconditionally and irrevocably to pay in
accordance with the terms and conditions of the above
mentioned contract to the supplier in Holland the amount of
N. fl. _____ (_____ only).

It is requested that the invoices, shipping and other docu-
ments presented by the Dutch suppliers be despatched direct
to the _____.

The suppliers will also be required to furnish to the
Netherlands Investment bank for Developing Countries a Certi-
ficate in duplicate issued/certified by the Netherlands Cham-
ber of Commerce of the district in which the exporter is
established regarding the Netherlands origin of the goods
covered under the Letter of Authority.

Kindly forward the debit advice to the Government of
India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,
Economic Aid (Accounts) Branch, Jeevan Deep, Parliament
Street, New Delhi. This Letter of Authority will remain
valid upto _____.

For the President of India,

Copy to _____
(Importer's Bank)

They should ensure that the rupees equivalent at the
Composite rate of exchange to be calculated in the manner
prescribed in Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976
and such other Public Notices that may be issued from time
to time together with the interest thereon at the rates pre-
scribed in Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976
from the date of payment to the suppliers to the date of
deposit of the amount into Government Account is deposited
before releasing the original documents to the Importer.

ANNEXURE V

No. F. 14()-WE.III/

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

SUBJECT:—Contract entered under General Purpose Dutch
Credit Reimbursement.

Dear Sirs,

Messrs. _____

_____ (Indian importer)
have entered into a contract with Messrs. _____

(Foreign supplier)

for the supply of _____

for the amount of _____ (_____

_____) C.I.F./C.&F. against Licence

No. _____ dated _____

issued under the Dutch General Purpose Credit for the value

of Rs. _____ (Rupees _____

_____).

A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of _____ an
amount of _____ is to be paid as Indian
Agents' Commission in Indian currency. The sum to be
paid to the supplier in foreign currency which will be financed
initially out of the free foreign exchange resources, to be
reimbursed later out of the Dutch General Purpose Credit,
therefore, amounts to _____.

3. You are authorised to open a letter of credit in favour of
Messrs. _____

_____ though their
bankers, viz. Messrs. _____

within a period of thirty days from date of this letter and
against a valid Import Licence, under intimation to the
Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building,
Parliament Street, New Delhi.

4. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control
Manual, you are required to ensure that the date of the expiry
of the Letter of Credit is not later than forty-five (45) days
after the final date for shipment as stated in the relative
import licence.

5. The letter of credit will also provide that Messrs. _____

(foreign banker)

will forward directly to the Controller of Aid Accounts &
Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of
non-negotiable shipping documents and two copies of the
invoice with a certificate duly endorsed thereon by the Dutch
Supplier that the payment has been received by the latter.

They will also obtain from the suppliers and furnish to the
Controller of Aid Accounts & Audit a certificate in duplicate
issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce
of the district in which the exporter is established regarding
the Netherlands origin of the goods covered under the Letter
of credit/*issued by the appropriate competent authority in
regard to the origin of the goods covered under the Letter
of Credit.

6. You are also required to forward to the Controller of
Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department
of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street,
New Delhi a certificate of remittance made by you to
M/s. _____

against the invoice/shipment of goods, excluding Bank
charges, if any.

7. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

*To be deleted if not applicable.

Copy with a copy of the contract forwarded to :—

Reserve Bank of India, Exchange Control Department,
Bombay-1.

2. Copy also forwarded for information to :—

(i) _____
(Indian importer)

It may be ensured that M/s. _____
(foreign banker)

forward one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him, and two copies of certificate in regard to origin of goods to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(ii) M/s. _____
(foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him and two copies of certificate in regard to origin of goods may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of

Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(iii) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

ANNEXURE VI

Statement Showing Quarterly Report on Utilisation under Dutch (G.P.) Credit

1. Name of Importer.
2. No. and date of Import Licence.
3. Value of Import Licence.
4. Value of orders placed.
5. Letter of Authority No. and date.
6. Amount of Letter of Authority.
7. Date of Validity of Letter of Authority.
8. Amount utilised during the Quarter D.G.
9. Total amount utilised D.G.
10. Total Amount deposited into Government Account. Rs.
11. Payment yet to be made during the subsequent quarters.
12. Surrenders, if any.

